

भारत समर्थक देउबा ने संभाली नेपाल की कमान

>> 11

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 34

मूल्य ₹8 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 14 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

ट्रैप क्राप से इल्लियों को चकमा, हुआ दोगुना मुनाफा



इंदौर: इंदौर के पास सिमरोल गांव के किसान लेखराज पाटीदार ने इल्लियों को चकमा देने के लिए ट्रैप क्राप का इस्तेमाल किया। इससे उनकी फसल सुरक्षित रही और करीब दोगुना मुनाफा भी हुआ। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय राजधानी ▶ पृष्ठ 2

सबसे अधिक व्यास वाली सुरंग से गुजरेगी दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल

नई दिल्ली: दिल्ली-मेरठ कारिडोर पर दौड़ने वाली रैपिड रेल देश की सबसे अधिक व्यास वाली सुरंग से भी गुजरेगी। इस सुरंग का व्यास विभिन्न शहरों में चल रहीं मेट्रो ट्रेनों की सुरंगों से कहीं अधिक होगा। प्रत्येक 250 मीटर पर क्रास पास दिए जाएंगे, ताकि यात्री आपात स्थिति में एक से दूसरी सुरंग में आ-जा सकें। साइड वाक-वे भी होगा, जो आपातकालीन स्थिति में सहायता करेगा।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए ट्वीट हटाएं साकेत गोखले : हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी व संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव रहीं लक्ष्मी एम. पुरी के खिलाफ साकेत गोखले द्वारा किए गए ट्वीट तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, वर्षों की निस्वार्थ सेवा व परिश्रम से हासिल प्रतिष्ठा एक विचारहीन टिप्पणी पर नहीं गिर सकती है। पुरी ने गोखले के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के मानहानि का वाद दाखिल किया है।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

लखनऊ से संभल तक बुना जा चुका था अलकायदा का जाल

लखनऊ: अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल का जाल लखनऊ से संभल तक बुना जा चुका है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी मिनहाज अहमद व मसीरुद्दीन के संपर्क में 20 से अधिक जिलों के युवक थे। खासकर मिनहाज इंटरनेट मीडिया के जरिये उनके लगातार संपर्क में रहता था। एटीएस ने मिनहाज व मसीरुद्दीन को पुलिस रिमांड पर लेकर नए सिरे से पूछताछ शुरू की है। दोनों आतंकियों के साथियों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 7

35,000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का भंडाफोड़

नई दिल्ली : जीएसटी चोरी को लेकर सरकार की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते गत वित्त वर्ष (2020-21) में 35,000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 8,000 मामलों का भंडाफोड़ किया गया। सीजीएसटी जोन और जीएसटी इंटेलीजेंस डायरेक्टरेट के प्रयासों से इस चोरी को पकड़ने में कामयाबी मिली। जीएसटी की चोरी मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) प्राविधान के दुरुपयोग के तहत की जा रही थी।

कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा न दें

पीएम बोले ▶ हिल स्टेशनों-बाजारों में बिना मास्क और प्रोटोकाल की अनदेखी कर भीड़ बढ़ना चिंता की बात

कहा, देश के कुछ जिलों में बढ़ रहे मामले चिंताजनक, वायरस के प्रसार को तत्काल रोकने की जरूरत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पर्यटन स्थलों और बाजारों में बिना मास्क पहने और शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किए बिना लोगों की भीड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। तीसरी लहर को रोकने के लिए आम लोगों में सजगता, सतर्कता और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे लहर को बुलावा न दें। जरा-सी लापरवाही से संक्रमण में उछाल आ सकता है। पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए उन्होंने इसके संकेत को समझने की जरूरत बताई।

मंगलवार को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अपने आप नहीं आती है। तीसरी लहर के पहले मौज मस्ती कर लेने की दलील को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हिल स्टेशनों, बाजारों में बिना मास्क के भारी भीड़ होना और कोरोना प्रोटोकाल का पालन न करना चिंता का विषय है और यह सही नहीं है। कोरोना प्रोटोकाल के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दूसरी लहर के कम होने के बाद नए मामलों की बढ़ती संख्या की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके संकेतों को समझने की जरूरत है। उनका आशय सीधे तौर पर तीसरी लहर की तरफ था। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों को केंद्र की मिली दूसरे स्वास्थ्य पैकेज की मदद से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की सलाह दी। इसके साथ ही राज्य सरकार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस का फैलाव रोकने को कहा।

(कोरोना से जंग-पेज-6)



नई दिल्ली में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की। प्रेट्र

● **कोरोना संकट पर पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने की बात**

> कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग सीना तान कर बोलते हैं कि तीसरे लहर आने से पहले एंज्वाय करना चाहते हैं। लोगों को यह समझना होगा कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अत्यधिक सावधान रहना जरूरी

मोदी ने कहा, वायरस के बदलते स्वरूप पर नजर रखने को जिनोम सिक्वेंसिंग तेज कर दी गई है, इसके बावजूद सावधानी जरूरी है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जहां तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं, वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र, कर्नाटक व ओडिशा में संक्रमण गिरावट रुक गई है। दो-तीन हफ्ते से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या एक समान बने रहने से दूसरी लहर के निम्नतम स्तर पर पहुंचने और तीसरी लहर की शुरुआत की आशंका बढ़ गई है। पीएम शुक्रवार को इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

पीएम की पांच बड़ी बातें

- अगर हम सतर्क रहते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो तीसरी लहर को रोकने में सक्षम होंगे
- सभी को कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना चाहिए, इससे समझौता नहीं होना चाहिए
- हमारे दिमाग में हमेशा यह मुख्य सवाल होना चाहिए कि तीसरी लहर को कैसे रोकना है?
- कोरोना का प्रसार रोकने को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएं
- टीकाकरण बढ़ाने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक संस्थानों, नामचीन हस्तियों और धर्मगुरुओं की मदद लें

मौसम की तरह कोरोना का अंदाजा न लगाएं

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने तीसरी लहर को लेकर कयासबाजी पर तंज कसते हुए कहा, यह मौसम की भविष्यवाणी की तरह नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथ में है। लोगों को कोरोना को रोकने के उपायों का गंभीरता से पालन करना करना चाहिए। उन्होंने ब्रिटेन, रूस, बांग्लादेश और इंडोनेशिया का हवाला देते हुए तीसरी लहर की विस्तार से जानकारी दी

टीकाकरण पर भी सरकार का जोर

टीकाकरण पर गठित टास्कफोर्स के प्रमुख डा. वीके पाल ने कहा, दुनिया के कई देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना प्रोटोकाल का पालन व टीका लगवाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर जब चरम पर थी तब विश्व में रोज नौ लाख नए केस मिल रहे थे। धीरे-धीरे इनकी संख्या प्रतिदिन तीन लाख पर पहुंच गई। अब फिर नए मामले बढ़ने लगे हैं।

अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कश्मीर के लिए बड़ा खतरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की दिन प्रतिदिन बढ़ती ताकत पर लगाम लगने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को वहां से जो सूचनाएं आईं, उससे साफ है कि कम से कम उत्तरी अफगानिस्तान के प्रांतों में तालिबान की ताकत और मजबूत हुई है। अधिकांश जानकार यह मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज होने से कुछ महीने दूर है। ऐसे में भारत की चिंता सिर्फ वहां अपनी अरबों डालर की परियोजनाओं और वहां काम करने वाले भारतीय नागरिकों की ही नहीं है, बल्कि तालिबान के आने से कश्मीर पर पड़ने वाले असर को लेकर भी है।

तालिबान का इस्तेमाल पूर्व में भी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किया है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की मजबूत होती संभावनाओं को देखते हुए भारत को कश्मीर को लेकर सुरक्षा चौकसी और मजबूत करनी होगी।

देश के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने हाल ही में कहा है कि तालिबान का मजबूत होना सीधे तौर पर कश्मीर के हालात से जुड़ा है। वहां आतंकी समूहों को नई ताकत मिल सकती है। वहीं, कूटनीति से जुड़े सूत्रों ने बताया, इस बार हालात इसलिए पेचीदा हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में पाक, तालिबान के साथ चीन भी ज्यादा सक्रिय दिख रहा है। तालिबान ने जैसे चीन के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देने की बात कही है, वह ध्यान देने योग्य है। पाक के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर प्रकाशित की जा रही है कि अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का कार्य चीन की मदद से किया जाएगा।

विस्फोटक हालात

- कश्मीर में आतंक फैलाने में पाकिस्तान कर चुका तालिबान का इस्तेमाल
- अजहर मसूद ने जैश को खड़ा करने में ली थी तालिबान की मदद

दुशांबे में अफगान समकक्ष से जयशंकर की मुलाकात

दुशांबे, प्रेट्र: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगान समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार से भेंट की और युद्धग्रस्त देश की स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए दो दिनी यात्रा पर दुशांबे पहुंचे है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि अफगान विदेश मंत्री संग बैठक कर दुशांबे यात्रा की शुरुआत की। हाल के घटनाक्रम पर उनके अपडेट की सराहना करें। हम कल अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।



एस. जयशंकर। फाइल

काबुल एयरपोर्ट को लेकर तालिबान की तुर्की को धमकी पेज>>11

अमेरिकी राजनयिकों को खौफ नहीं पेज>>11

पांच दिन की देरी के बाद पूरे देश में पहुंचा मानसून



नई दिल्ली में मंगलवार की सुबह आसमान में काले घने बादलों के छाने के साथ झमाझम बारिश के बीच अंधेरा छा गया। इस दौरान वाहन चालकों को लाइट जलाकर गुजरना पड़ा। ध्रुव कुमार

नई दिल्ली, प्रेट्र : पांच दिन की देरी के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे देश में आठ जुलाई को पहुंच जाता है। लेकिन, इस बार यह कुछ देरी से पहुंचा। इससे पहले मानसून के पूरे देश में छाने की सामान्य तारीख 15 जुलाई बताई गई थी। पिछले साल मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए इसकी शुरुआत की तारीख को संशोधित किया था।

सोमवार को मानसून दिल्ली को छोड़कर अपने आखिरी पड़ाव राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिलों तक पहुंच गया था। यह राजस्थान के बाड़मेर में सामान्य तिथि से करीब दो हफ्ते पहले पहुंच गया था। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अनेक हिस्सों में बारिश हुई।

▶ **दिल्ली-एनसीआर में भी लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को हुई बारिश**

मौसम विभाग ने कहा, पिछले चार दिनों से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली पुरवाई हवाओं के चलने से बादलों का दायरा बढ़ गया और कई स्थानों पर बारिश हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी स्थानों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के बाकी बचे हिस्सों तक पहुंच चुका है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने तीन जून को केरल में दस्तक दी थी। इसने 15 जून तक देश के मध्य, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया। हालांकि, पश्चिमी हवाओं जैसी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों में इसका बढ़ना रुक गया था। (पेज-5 भी देखें)

11 सितंबर को होगी नीट (पीजी) 2021

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की स्नातकोत्तर (पीजी) परीक्षा 11 सितंबर को होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह घोषणा की। मांडविया ने ट्वीट किया कि हमने नीट (पीजी) 11 सितंबर, 2021 को कराने का फैसला किया है। युवा चिकित्सक अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं। इससे पहले, 18 अप्रैल को प्रस्तावित नीट-पीजी परीक्षा को कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि नीट-यूजी (स्नातक स्तर) की परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को पूरे देश में कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुएआयोजित की जाएगी।

13 भाषाओं में होगी नीट (यूजी) पेज>>3

नहीं रहा 1983 क्रिकेट विश्व कप का हीरो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मध्यक्रम में अपनी जुझारू बल्लेबाजी के कारण भारतीय क्रिकेट में विशेष पहचान बनाने वाले और 1983 विश्व कप के नायक यशपाल शर्मा का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं।

सुबह की सैर से लौटने के बाद यशपाल बेहोश हो गए थे। उनका लोधी रोड स्थित अंत्येष्टि स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। 1983 विश्व कप टीम के साथी कीर्ति आजाद भी वहां मौजूद थे। यशपाल अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में वनडे की अपनी 40 पारियों में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए। उन्होंने दोनों प्रारूपों में एक-एक विकेट भी लिया। उन्हें अपने जुझारूपन के लिए जाना जाता है। विश्व कप 1983 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में ओल्ड ट्रैफर्ड में खेली गई उनकी अर्धशतकीय पारी क्रिकेट प्रेमियों को हमेशा याद रहेगी।

यशपाल ने रणजी ट्राफी में तीन टीमों पंजाब, हरियाणा और रेलवे का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 160 प्रथम श्रेणी मैचों में 8,933 रन बनाए, जिसमें 21 शतक शामिल हैं। उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 201 रन रहा। उन्होंने दो महिला वनडे मैचों में अंपायरिंग भी की। वह उत्तर प्रदेश रणजी टीम के कोच भी रहे थे। वह उस राष्ट्रीय चयनसमिति का हिस्सा थे, जिसने 2004 में महेंद्र सिंह धौनी को राष्ट्रीय टीम में पहला मौका दिया था। यशपाल 2011 विश्व कप में धौनी की अगुआई में चैंपियन बनने वाली टीम का चयन करने वाली चयन समिति का भी हिस्सा थे। वह उस दौर के भी गवाह रहे जब तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली और टीम के कोच ग्रेग चैपल के बीच 2006 में ठन गई थी। यशपाल ने तब गांगुली का पक्ष लिया था। यशपाल बाद में विभिन्न टीवी चैनलों में क्रिकेट विश्लेषक की भूमिका निभाने लगे थे।

(संबंधित खबरें पेज-12 पर)

यशपाल शर्मा

जन्म : 11 अगस्त 1954, लुधियाना

निधन : 13 जुलाई 2021, दिल्ली



दिल का दौरा पड़ने से निधन, सुबह की सैर से लौटने के बाद हो गए थे बेहोश

> यशपाल जी 1983 की मशहूर टीम के प्रिय सदस्य थे। वह टीम के साथियों, प्रशंसकों के साथ-साथ उभरते क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा थे। उनके निधन से शोक में हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। ओम शांति।
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

क्षेत्रीय भाषा में भी होगी बैंकों की क्लर्क भर्ती परीक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इस मुद्दे पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय ने किया समिति का गठन
- रिपोर्ट आने तक क्लर्क भर्ती परीक्षा पर लगाई गई रोक

पब्लिक सेक्टर बैंक (पीएसबी) या सरकारी बैंकों की क्लर्क भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में देने की इजाजत मिल सकती है। पीएसबी की क्लर्क भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में देने की इजाजत पर विचार के लिए वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आइबीपीएस) की तरफ से आयोजित की जाने वाली क्लर्क भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगले 15 दिनों में कमेटी अपनी सिफारिश देगी और उसके बाद ही आइबीपीएस की परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अभी रिजनल रूरल बैंक (आरआरबी) की भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में दी जा सकती है, लेकिन पीएसबी परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ही देने की इजाजत है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि संविधान ने कई क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन सिर्फ दो भाषा में ही पीएसबी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। कमेटी इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट देगी। सूत्रों के मुताबिक सरकारी बैंकों के कई ब्रांच में उस इलाके की स्थानीय भाषा के जानकार नहीं होते हैं। इससे वहां के स्थानीय निवासियों का सरकारी बैंकों के प्रति भरोसा मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि स्थानीय निवासी अपनी भाषा में बैंककर्मी से संवाद नहीं कर पाते हैं। वित्त मंत्री ने दो साल पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकारी बैंकों में कम से कम एक कर्मचारी वहां की स्थानीय भाषा का जानकार होना चाहिए।

आर्थिक सुधारों वाले विधेयकों को पारित करवाने पर होगा जोर

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी समझे जाने वाले कानूनी संशोधनों को लेकर सरकार अब देरी के मूड में नहीं है। मानसून सत्र में देश की आर्थिक गतिविधियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले डेढ़ दर्जन विधेयक पारित करवाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। इनमें दिवालिया कानून (इंसाल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड-आइबीसी) में संशोधन भी शामिल है। अप्रैल, 2021 में सरकार ने आइबीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। अब अध्यादेश की जगह संशोधित कानून लाया जाएगा। (पेज-3)

बढ़ाया हौसला

प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलिंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों और उनके माता-पिता से की बातचीत

जब पीएम बोले, कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं विनेश को

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलिंपिक के लिए जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से मंगलवार को वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान जब उन्होंने कुश्ती में पदक की उम्मीद हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट के ताऊ महावीर से पूछा कि अपनी बेटी को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं तो सब हंसने लगे। मोदी ने भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से बातचीत के दौरान सभी खिलाड़ियों को संदेश दिया, 'आप अपने कंधों पर अपेक्षाओं का भार लेकर मत दौड़ना। देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

मोदी ने विनेश से पूछा कि परिवार की ख्याति के कारण अपेक्षाओं का बोझ होगा, उससे कैसे निपटती हैं। विनेश ने कहा, 'उम्मीदें जरूरी हैं, जो अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। अपेक्षाओं का दबाव नहीं है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी।'

प्रतिभा क्या नहीं कर सकती: श्रमिक के बेटे तीरंदाज प्रवीण जाधव से मोदी ने कहा, 'जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का चयन सही हो तो देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती, यह हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया है।'

प्रदर्शन पर फोकस : दुनिया की नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी से पीएम ने पूछा, वह अपेक्षाओं और अपने प्रदर्शन के बीच संतुलन कैसे बनाती है, इस पर दीपिका ने कहा, 'मैं पूरा फोकस प्रदर्शन पर रखती हूं।'

कम उम्र में सफर तय किया : मेरठ के कलीना गांव के 19 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी से मोदी ने कहा, आपने काफी कम उम्र में ओलिंपिक तक का सफर तय किया है। लगता है कि आप लक्ष्य के प्रति काफी सजग हैं।'

23 जुलाई से आठ अगस्त तक चलेंगे टोक्यो ओलिंपिक

228 सदस्यीय भारतीय दल जाएगा, जिनमें 119 खिलाड़ी होंगे

119 भारतीय खिलाड़ियों में 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी। यह ओलिंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल होगा



पीएम नरेंद्र मोदी से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से वार्ता के दौरान हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट। साथ में उनके ताऊ महावीर भी मौजूद रहे। एएनआइ

सिलसिला बढ़ेगा

भारतीय हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से मोदी ने कहा कि भारत ने हाकी में ओलिंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं और इस समय उन्हें मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू और मुहम्मद शाहिद जैसे महान खिलाड़ियों की याद आ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम सफलता के उस सिलसिले को आगे बढ़ाएगी।

सचिन का उदाहरण दिया

ओलिंपिक से ठीक पहले पिता को खोने वाले मुक्केबाज आशीष कुमार को सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा, 'सचिन भी अहम टूर्नामेंट खेल रहे थे, तब पिता का निधन हो गया। उन्होंने खेल से पिता को श्रद्धांजलि दी। एक खिलाड़ी के तौर पर आप विजेता हैं ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी विषमताओं पर विजय प्राप्त की है।'

इन खिलाड़ियों से की बातचीत

पीवी सिंधु (बैडमिंटन), सानिया मिर्जा (टेनिस), एमसी मेरी कोम (मुक्केबाजी), सौरभ चौधरी और इलावेनिल वालरेविन (निशानेबाजी), दुती चंद (एथलेटिक्स), मनप्रीत सिंह (हाकी), विनेश फोगाट (कुश्ती), साजन प्रकाश (तैराकी), दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव (तीरंदाजी), आशीष कुमार (मुक्केबाजी), मनिका बत्रा (टेबल टेनिस)।

मंदिर जलाने के 350 आरोपितों से मामले वापस लेगी पाक सरकार

पेशावर, प्रेट्र : पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है। देश की सरकार ने अल्पसंख्यक हिंदुओं की तरफ से कथित तौर पर माफी दिए जाने की आड़ में मंदिर जलाने व हिंसा के आरोपितों को बचा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले साल मंदिर जलाने के मामले में 350 आरोपितों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे।

प्रांत के आंतरिक विभाग के सूत्रों का कहना है कि मामले को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा गठित एक जिरगा में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने आरोपितों को माफ करने का फैसला किया। जिरगा एक पारंपरिक परिषद है, जिसमें समुदाय के सदस्यों द्वारा आम सहमति से फैसला लिया जाता है। आंतरिक विभाग ने आतंकरोधी अदालत को पत्र लिख कर जिरगा के फैसले से अवगत कराया है।

▶ **माफी की आड़ में हिंसा के आरोपितों को बचाया, अल्पसंख्य हिंदुओं में असंतोष**

उल्लेखनीय है कि पिछले साल टेरी कारक जिले में श्री परमहंस जी महाराज की समाधि और उससे जुड़े एक मंदिर में आग लगाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में 350 लोगों को नामजद किया गया था। हमले में करीब 109 लोग संलिप्त थे। उस दौरान ड्यूटी पर मौजूद 92 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और प्रांतीय सरकार को समाधि व मंदिर के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए थे। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद वहां पुनर्निर्माण कार्य में अनावश्यक देर हो रही है।

हारून सराब ने कहा, हिंदू समुदाय को विश्वास में नहीं लिया गया पेज>>11

15 जुलाई को जारी किया जाएगा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नौवीं और 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों की पुनर्मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम। छात्र परिणाम शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 14 जुलाई, 2021

न्यूज गैलरी

46.54 फीसद व्यस्क आबादी को लगी टीके की पहली डोज

नई दिल्ली: राजधानी में टीके की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इस माह की शुरुआत से ही टीकाकरण की यही स्थिति है। टीके की कमी के कारण पिछले तीन दिन कम लोगों को टीका लग पाया था लेकिन मंगलवार को एक बार फिर एक लाख 28 हजार 906 लोगों को टीका लगा। इस रफ्तार को भी बरकरार रखने की चुनौती है। क्योंकि अभी तक करीब 46.54 फीसद व्यस्क आबादी को ही एक डोज लग पाई है। 53.46 फीसद व्यस्क आबादी को अभी एक भी डोज नहीं लगी है। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या करीब एक करोड़ 49 लाख है। इनमें से अभी तक 14.30 फीसद लोगों को ही दोनों डोज टीका लग सका है। दिल्ली में अभी कोवैक्सीन की दो लाख 27 हजार डोज उपलब्ध हैं। समस्या यह है कि इस टीके की आपूर्ति कम होने से पहली डोज लेने वाले 20 फीसद लोगों को ही यह टीका देने की स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृति दी है। (राब्यू)

निष्पक्ष जांच के लिए उपराज्यपाल से मिलेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

नई दिल्ली : एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद व इनके रखरखाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली भाजपा इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) या सीबीआइ से कराने की मांग कर रही है। इसे लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र भी लिखा है। अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के नेता उपराज्यपाल से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में भी गड़बड़ी है। रखरखाव की निविदा को रद करके इसे नए सिरे से जारी करने को कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी हुई है। इस मामले में अनियमितता हुई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। जानबूझकर सिर्फ दो कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया गया। बस खरीद पर नौ सौ करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। (राब्यू)

जेएनयू लाइब्रेरी इंचार्ज ने सेंट्रल लाइब्रेरी अध्यक्ष की शिकायत की

नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के लाइब्रेरी इंचार्ज ने सेंट्रल लाइब्रेरी की चीफ लाइब्रेरियन पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। लाइब्रेरी इंचार्ज सूरज सिंह ने कुलपति प्रो. एम जगदेश कुमार को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि वह चाइनीज भाषा की प्रथम वर्ष की छात्रा अपना बेटी के साथ लाइब्रेरी गए थे। जहां चीफ लाइब्रेरियन मनोरमा त्रिपाठी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उधर, जेएनयू छात्रों ने मंगलवार शाम लाइब्रेरी के सामने प्रदर्शन भी किया। सेंट्रल लाइब्रेरी की चीफ लाइब्रेरियन मनोरमा त्रिपाठी ने कहा कि आरोप निराधार है। (जासं)

मोर के अंडों का बनाया आमलेट, थाने पहुंचे ग्रामीण

नोएडा: नोएडा में एक गांव में कुछ युवकों द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के अंडों का आमलेट बनाकर खाने से नाराज ग्रामीण मंगलवार को कोतवाली पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक गांव बीरमपुर में एक ग्रामीण के प्लाट में राष्ट्रीय पक्षी मोर के चार अंडे रखे थे। आरोप है कि सोमवार की शाम गांव के ही चार युवक अंडों को उठाकर ले गए और आमलेट बना कर खा गए। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कर दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को कोतवाली पहुंचकर आरोपित चारों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। (जासं)

दिल्ली-मेरठ कारिडोर पर सबसे अधिक व्यास वाली सुरंग से गुजरेगी रैपिड रेल

अन्य शहरों में दौड़ रही मेट्रो की सुरंगों का व्यास करीब 5.8 मीटर, रैपिड रेल का होगा 6.5 मीटर

प्रत्येक 250 मीटर पर दिए जाएंगे क्रास पास, यात्री आपात स्थिति में भी आ-जा सकेंगे एक से दूसरी सुरंग में

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ कारिडोर पर दौड़ने वाली रैपिड रेल देश की सबसे अधिक व्यास वाली सुरंग से भी गुजरेगी। इस सुरंग का व्यास विभिन्न शहरों में चल रहीं मेट्रो ट्रेनों की सुरंगों से कहीं अधिक होगा। यही नहीं, प्रत्येक 250 मीटर पर क्रास पास भी दिए जाएंगे, ताकि यात्री आपात स्थिति में एक से दूसरी सुरंग में आ-जा सकें। सुरंग में एक साइड वाक-वे भी होगा, जो रखरखाव गतिविधियों के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति में सहायता करेगा।

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए बनाई जा रही सुरंगों का व्यास 6.5 मीटर रखा जा रहा है, जबकि देश के 15 से 20 शहरों में चल रही मेट्रो ट्रेनों के कारिडोरों में अधिकतम 5.8 मीटर व्यास तक की सुरंगों का निर्माण किया गया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि रैपिड रेल की अधिकतम गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण सुरंगों में शाक वेव्स (तेज कंपन वाली तरंगें) उत्पन्न होंगी। इस वजह से यात्रियों को हवा के दबाव में असुविधा हो सकती है। इसी असुविधा को कम करने के लिए सुरंगों का व्यास 6.5 मीटर करने का निर्णय लिया गया है। अधिक व्यास की सुरंग हवा के उच्च दबाव को न्यूनतम करेगी और लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगी।

उल्लेखनीय है कि आरआरटीएस की सुरंगें जुड़वां होंगी, जो दोनों दिशाओं में रेल चलने के लिए बनेंगी। एक तरफ आनंद विहार से सराय काले खां की ओर जुड़वां सुरंगों का निर्माण किया जाएगा और दूसरी ओर आनंद विहार से साहिबाबाद की तरफ। आनंद विहार से सराय काले खां की ओर की सुरंग की लंबाई लगभग तीन किलोमीटर होगी, जोकि देश में उपलब्ध मेट्रो में से किन्हीं दो स्टेशनों के बीच सबसे लंबा सुरंग का खंड होगा। आनंद विहार से साहिबाबाद की ओर सुरंग लगभग दो किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी।



प्रतीकात्मक फोटो।

> रैपिड रेल के सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए सभी संभव उपायों पर काम किया जा रहा है। इसके मद्देनजर रैपिड रेल की सुरंग का व्यास होगा 6.5 मीटर रखा जाएगा। साथ ही इसमें क्रास पास भी बनाए जाएंगे।
>
> -पुनीत वत्स, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एनसीआर परिवहन निगम

रैपिड रेल के यात्रियों की सुरक्षा के लिए लागू होगा 'आइड्रीम्स'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना में यात्री सुविधा और संपत्तियों के रखरखाव के लिए रीयल टाइम एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम 'आइड्रीम्स' लागू होगा। यह सिस्टम बताएगा कि कब ट्रेन, एएफसी सिस्टम, प्लेटफार्म स्क्रीन डोर, लिफ्ट, एस्केलेटर, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल, ओएचई उपकरणों और अन्य सिविल संरचनाओं सहित अन्य संसाधनों की सर्विस होनी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम का दावा है कि समय पर रखरखाव के चलते यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

एनसीआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि इस सिस्टम से रेलवे में क्रांति आ जाएगी। यह रिकार्ड रखना भी आसान होगा कि यात्री सुविधा के लिए उपकरण की खरीद कब की गई और उसकी सर्विस कब और किसने की। एक क्लिक पर पूरा ब्योरा निकल कर आ जाएगा। यहां तक बताना संभव होगा कि उपकरण का कोई पुर्जा खराब होता है, तो वह कब और कहां से खरीदा गया। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर यात्री सुविधाएं निजी एजेंसी के माध्यम से दी जाएंगी। ऐसे में उसकी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। एनसीआरटीसी का अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर है। आइड्रीम्स सिस्टम के अलावा बिल्डिंग इन्फार्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इंटरनेट आफ थिंग, भवन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पॉड टैक्सी से तय होगा सफर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- कई देशों में परिवहन के लिए चल रही हैं पॉड टैक्सी
- उत्तर प्रदेश में पॉड टैक्सी चलाने वाला यमुना प्राधिकरण होगा पहला शहर

यीडा सिटी (यमुना प्राधिकरण का शहर) प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है, जहां पॉड टैक्सी से लोग सफर करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। दुबई, लंदन, दक्षिण कोरिया में पॉड टैक्सी यात्री परिवहन के रूप में संचालित हो रही हैं। पॉड टैक्सी (अल्ट्रा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट) की इंडियन पोर्ट एंड रेल रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर यमुना प्राधिकरण को सौंप दी है। एयरपोर्ट के साथ पॉड टैक्सी का संचालन शुरू होगा। एक वर्ष के अंदर इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

14.6 किमी लंबी होगा कॉरिडोर : यमुना प्राधिकरण की योजना यमुना एक्सप्रेस वे के समानांतर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक अल्ट्रा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की थी। लेकिन जो डीपीआर तैयार की गई है, उसके हिसाब से अल्ट्रा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की लंबाई 14.6 किमी होगी। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के नजदीक स्थित ट्रांसपोर्ट हब से कॉरिडोर शुरू होगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समाप्त होगा।

औद्योगिक सेक्टरों में मिलेगा लाभ : अल्ट्रा पीआरटी कॉरिडोर औद्योगिक सेक्टरों के बीच होकर सड़क के साथ गुजरेगा। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वालों को इससे परिवहन का सुगम साधन मिलेगा। कॉरिडोर सेक्टर 21, 28, 29, 30, 32, 33 से होते हुए एयरपोर्ट तक होगा। सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क, सेक्टर 29 में अपैरल, हैंडीक्राफ्ट आदि क्लस्टर है। सेक्टर 32 व 33 में खिलौना क्लस्टर, एमएसएमई आदि प्रस्तावित हैं। फिल्म सिटी आने वाले पर्यटकों के लिए भी पॉड टैक्सी आकर्षण का केंद्र होगी।

आठ हजार यात्री करेंगे प्रतिदिन सफर: डीपीआर के अनुसार पॉड टैक्सी से प्रतिदिन करीब आठ हजार यात्री सफर करेंगे। कॉरिडोर को भूतल पर विकसित किया जाएगा। आने-जाने के दोनों ट्रैक बनाने पर करीब 862 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसमें स्टेशन, चार्जिंग प्वाइंट आदि शामिल हैं। प्रत्येक सेक्टर में एक स्टेशन होगा। डीपीआर में चालक विहीन व बैटरी संचालित पॉड टैक्सी चलाने का सुझाव दिया गया है। एक पॉड में 24 यात्री तक बैठ सकेंगे।

परियोजना को विकसित करने के लिए तीन फाइनेंशियल मॉडल का विकल्प : परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए पूंजी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए पीपीपी, हाइब्रिड मॉडल सुझाए गए हैं। इनमें से किसी एक मॉडल का चयन किया जाएगा।

> पॉड टैक्सी की डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसका अध्ययन किया जा रहा है। आगामी बोर्ड बैठक में डीपीआर स्वीकृति के लिए रखी जाएगी। इसके बाद शासन के पास भेजा जाएगा।
>
> -डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

47 फीसद शिकायतें जल बोर्ड से संबंधित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी के लोगों को सबसे अधिक शिकायतें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से हैं। इसमें भी गंदे पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी समस्या है। यह दावा प्रजा फाउंडेशन द्वारा 'दिल्ली में नागरिक मुद्दों की स्थिति' संबंधी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली वालों की कुल शिकायतों में 47 फीसद दिल्ली जल बोर्ड की हैं, यानी हर पांच में से तीन शिकायतें पेयजल से जुड़ी हैं। इसमें भी 27 फीसद शिकायतें गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर की जा रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सरकारी एजेंसियों को 2020 में कुल तीन लाख 36 हजार 868 शिकायतें अलग-अलग माध्यमों से मिली हैं। इसमें अकेले दो लाख 27 हजार 973 शिकायतें डीजेबी से संबंधित थीं। इनमें भी एक लाख 45 हजार 316 शिकायतों को डीजेबी द्वारा 'अन्य' में वर्गीकृत किया गया। इन शिकायतों का न तो निराकरण किया गया और न ही संबंधित विभागों को भेजा गया। डीजेबी में कार्रवाई रिपोर्ट और शिकायतों के निवारण की जानकारी देने का ठोस तंत्र भी नहीं है। प्रजा फाउंडेशन की ट्रस्टी निताई मेहता का दावा है कि 2020 में डीजेबी को प्राप्त कुल शिकायतों में से 47 फीसद 'पानी की कमी' और 'पानी की आपूर्ति नहीं होने' से संबंधित थीं। वहीं, 38 हजार 663 शिकायतें गंदे पानी की आपूर्ति से संबंधित थीं।

गंदे पानी का स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर: दिल्ली में गंदे पानी की समस्या कभी खत्म न होने वाला मुद्दा है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में टाइफाइड के 20 हजार 370 मामले और दस्त दो लाख 39 हजार 575 मामले सामने आए थे। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने की वजह दूषित पानी था। यही नहीं, महामारी के दौरान पानी और साफ जैसी मूलभूत नागरिक सेवाओं के प्रति केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार द्वारा ध्यान भी नहीं दिया गया।

दिल्ली में ये है व्यावहारिक दिक्कत: शिकायतों के निराकरण में होने वाली परेशानी को लेकर दिल्ली के साथ व्यावहारिक दिक्कत यह है कि यहां एक साथ एक ही स्थान पर कई एजेंसियां काम करती हैं। उनके क्षेत्राधिकार को लेकर लोगों में काफी भ्रम है। इसके बाद भी दूसरे विभाग से संबंधित शिकायतों को साझा करने की कोई परस्पर और आसान व्यवस्था नहीं है। इसके चलते नागरिकों की न तो शिकायतें सुनी जाती हैं और न ही लंबे समय तक समस्याएं दूर होती हैं।

नगर निगम के 16 फीसद शौचालय में पानी नहीं

नगर निगम के सार्वजनिक शौचालय की सुविधा में भी गंभीर असमानता देखी गई। तीन में से केवल एक सार्वजनिक शौचालय महिलाओं के लिए है। यही नहीं 10 शौचालय में से एक का पाइप न सीवरेज से जुड़ा है और न ही उसमे बिजली है। इसी तरह 16 फीसद शौचालय में पानी का कनेक्शन नहीं है। फाउंडेशन के निदेशक मिलिंद म्हस्के ने कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को रेखांकित करते हुए बताया कि दिल्ली का 48 फीसद कचरा बिना गीला-सूखा अलग किए लैंडफिल साइट पर पहुंच रहा है। नगर निगम के 272 वार्डों में से केवल 82 वार्ड में ही 80-100 फीसद तक अपशिष्ट अलग होते हैं।

एक्सप्रेस-वे पर परीचौक से सफीपुर तक उप्र का पहला फ्लेक्सिबल क्रेश बैरियर रोप लगेगा

अर्पित त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा

2.58 करोड़ रुपये में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगवाएगा बैरियर, चार महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सड़क हादसे कम करने के लिए प्राधिकरण तीन किलोमीटर सेंट्रल वर्ज पर फ्लेक्सिबल वायर रोप क्रैश बैरियर लगवाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी एक्सप्रेस-वे पर इस तरह का बैरियर लगाया जा रहा है। परी चौक से सफीपुर गांव तक लगने वाले इस बैरियर में 2.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। चार महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक एक्सप्रेस वे पर क्रैश बीम बैरियर लगते रहे हैं। यह मैटल के होते हैं और आमतौर पर अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू के आकार में होते हैं। तेज रफ्तार वाहन जब इससे टकराते हैं तो बीम बैरियर उसे रोक देता है। वाहन के पलटने या सड़क से नीचे गिरने की आशंका कम हो जाती है।

मुंबई के एक्सप्रेस-वे पर लगा है बैरियर : प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक इस तरह का बैरियर मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगा हुआ है। इसमें चार या पांच लचीले धातु के मजबूत तार एक के ऊपर एक लगे होंगे। लचीले होने के कारण वाहन यदि इनसे टकराएंगे तो एक तो वाहन दूसरी तरफ नहीं जाएगा। इसके साथ ही वाहन के टकराने पर लगने वाला तेज झटके की तीव्रता भी कम होगी। इससे हादसे की भयावहता कम होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगते हैं ऐसे बैरियर : फ्लेक्सिबल रोप बैरियर को पिछले वर्ष ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाने के लिए फैसला लिया था। इस तरह के बैरियर अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही लगते थे। उत्तर प्रदेश के किसी एक्सप्रेस-वे पर यह पहली बार लगाया जा रहा है।

90-100 किलोमीटर की रफ्तार पर भी कारगर: ये बैरियर 900 किलोग्राम भारी और 100 किलोमीटर की रफ्तार व 10000 हजार किलोग्राम भार वाहन की 90 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार को झेल सकता है। इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और हादसे में जानमाल की क्षति में कमी आएगी।

> काफी अध्ययन के बाद इन बैरियर को लगाने का निर्णय लिया गया है। अगले दो महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके दो महीने के भीतर बैरियर लगवा दिए जाएंगे।
>
> -एके अरोड़ा, महाप्रबंधक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण



इस तरह लगेगा फ्लेक्सिबल वायर रोप क्रैश बैरियर। सौ. प्राधिकरण

आक्सीजन किल्लत : पुलिस के हल्के जवाब पर अदालत नाराज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आक्सीजन की कमी के कारण जयपुर गोल्डन अस्पताल में 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी

आक्सीजन की कमी के चलते अप्रैल में जयपुर गोल्डन अस्पताल में जान गंवाने वाले 21 कोरोना मरीजों की मौत के मामले में पुलिस की तरफ से दिए गए जवाब पर अदालत ने नाराजगी जताई है। रोहिणी की एक अदालत ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस का उदासीनता भरा रवैया स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को भी लताड़ लगाई और साथ ही संबंधित डीसीपी को सही तरीके से जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया।

मृतकों के स्वजन की तरफ से याचिका दायर कर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी से जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक इस मामले में मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। इसे लेकर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा इतने संवेदनशील मामले को पुलिस हल्के में ले रही है। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में यह तक नहीं बताया कि जांच की दिशा में क्या कदम उठाए गए।

याचिका में कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाए पुलिस-प्रशासन मिलकर दोषियों को बचा रहे हैं। इसके अलावा जांच को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। अगर अस्पताल प्रबंधन के पास पर्याप्त आक्सीजन नहीं थी तो मरीजों को भर्ती ही नहीं करना चाहिए था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रबंधन ने सभी को अंधेरे में रखा और गैर इरादतन हत्या को अंजाम दिया है।

डीडीए भूमि घोटाले में सीबीआइ ने छापेमारी की

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में दिल्ली और उप्र के लखनऊ एवं शामली में 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। तीनों पूर्व अधिकारियों पर डीडीए प्लाटों के गैरकानूनी आवंटन को लेकर मामला दर्ज है।

सीबीआइ के प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने डीडीए के पूर्व सहायक निदेशक सुधांशु रंजन, पूर्व वरिष्ठ सचिवालय सहायक अजीत कुमार भारद्वाज, पूर्व सुरक्षा गार्ड दरवान सिंह और अन्य इकबाल हुसैन, सुनील कुमार मीणा, सपन कुमार, जमालुद्दीन, राजवंत सिंह व शकुंतला देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जाली एवं फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेज और सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी के आधार पर सरिता विहार के समीप मदनपुर खादर इलाके में डीडीए के कई प्लाटों का आवंटन किए जाने की मिली शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।

एक अगस्त से छात्रावास खोलेगा आइआइटी दिल्ली

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आइआइटी दिल्ली) अगस्त महीने से छात्रावास खोलेगा। शुरुआती दिनों में सिर्फ जरूरतमंद छात्रों को कमरे आवंटित किए जाएंगे। ऐसे छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके घर पर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आइआइटी की उच्च स्तरीय बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया है। बहुत जल्द छात्रों को ईमेल भेजकर जानकारी दी जाएगी।

आइआइटी स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रो रीतिका खेरा ने बताया कि कोरोना काल में छात्र घर से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से छात्रों के घर पर पढ़ाई का माहौल नहीं है। छात्रों के लिए अलग कमरा तक नहीं, जहां वे आनलाइन पढ़ाई कर सकें। बहुत से छात्रों ने बिजली, इंटरनेट आदि की दिक्कत भी बताई है। छात्र पत्र लिखकर बार-बार छात्रावास बुलाने की मांग कर रहे थे। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि एक अगस्त से छात्रावास खोले जाएंगे। पहले उन छात्रों को ही बुलाया जाएगा, जिन्हें घर से पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। बकौल रीतिका खेरा, बड़ी संख्या में छात्रों ने टीका लगवा लिया है। कई छात्र संक्रमित भी हुए थे, जिन्हें तीन महीने बाद टीका लगना है। ऐसे में छात्र परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। आइआइटी दिल्ली परिसर में भी टीकाकरण चल रहा है। छात्र इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

50 लाख रुपये की मदद : कोरोना काल में आइआइटी ने प्रथम वर्ष से लेकर चतुर्थ वर्ष और एमएससी के छात्रों की आर्थिक मदद की। छात्रों की मदद के लिए बनाए गए फंड में 70 लाख रुपये इकट्ठा हुए थे। इसमें से 50 लाख रुपये की मदद की गई। आइआइटी ने 200 छात्रों को टैब और 350 छात्रों को डोंगल दिए।

परिवहन विभाग ने फिर दी चेतावनी कि उम्र पूरी कर चुके वाहन स्क्रैप कराएं

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : परिवहन विभाग ने एक बार फिर से लोगों को चेतावनी दी है कि उनका डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप (समाप्त) कराएं। ऐसे वाहन सड़क पर निकाले गए तो जब्त कर लिया जाएगा।

वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने चार एजेंसियां अधिकृत की हैं, लेकिन लोग वाहन स्क्रैप कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लाकडाउन को छोड़ दें तो प्रति माह चारों एजेंसियों को 600 वाहन ही स्क्रैप कराने के लिए पहुंचाया जा रहा है। चारों एजेंसियों को मिलाकर एक माह में 12 हजार वाहन तक स्क्रैप किए जा सकते हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में इस साल दूसरी बार सार्वजनिक सूचना जारी की है। इससे पहले 15 जून को भी विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

योजना

दिल्ली विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में किफायती किराया आवास परिसर योजना को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

गरीबों को कम किराये पर मिलेगा घर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बोर्ड की बैठक मंगलवार को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस योजना से प्रवासी कामगारों और गरीबों को कम किराये पर घर मिल सकेगा। ये आवास सरकारी जमीन के अलावा निजी जमीन पर भी बनाए जा सकेंगे। इसके लिए बिल्डर को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। हालांकि अभी इस योजना को अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा।

डीडीए के मुताबिक इस योजना के लिए शुरुआती मंजूरी 18 मार्च को हुई बोर्ड की बैठक में दी गई थी। इसके बाद पब्लिक नोटिस जारी कर लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए थे। तय नियमों के अनुसार हाउसिंग कांप्लेक्स में सिंगल बेडरूम या डबल बेडरूम और चार या छह बेड की डोरमेट्री शामिल होगी। इस जगह पर 10 फीसद एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) में व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा सकेगी, जिसे बिल्डर बेच भी सकेगा। घर किराये पर देने के लिए लाइसेंस डीड बनवानी होगी, जो कम से कम तीन महीने और अधिकतम तीन साल की हो सकती है।

डायनेमिक पार्किंग मानकों को मिली मंजूरी : बोर्ड बैठक में डायनेमिक पार्किंग मानकों को भी मंजूरी दी गई। नए नियमों के अनुसार दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में पार्किंग के लिए उस योजना के तहत बनने वाले आवासों की संख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान तय किया जाएगा। दिल्ली में मौजूदा समय में मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक पार्किंग के लिए स्थान चिह्नित किए जाते हैं। इसके तहत प्लाट के साइज का कुछ फीसद हिस्सा पार्किंग स्थल के रूप में खाली छोड़ा जाता है। नए नियमों के तहत, जितने आवासीय फ्लैट होंगे, उनकी संख्या के बराबर पार्किंग अनिवार्य रूप से बनानी होगी।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

डीडीए की बैठक में एआरएचसी योजना के तहत फ्लैटों के निर्माण लागत की गणना के लिए प्लिंथ एरिया दरें (पीएआर), व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों और बहु-स्तरीय पार्किंग के तहत क्षेत्र के संबंध में रूपांतरण शुल्क और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट सीआरपीएफ के ट्रांजिट कैंप के निर्माण के लिए भू-उपयोग को मनोरंजक से सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में अब बेसमेंट पार्किंग नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया गया। यहां अब सामान्य पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा।

कमेटी तय करेगी धार्मिक प्लाट आवंटन का फार्मूला

डीडीए बोर्ड की बैठक में धार्मिक स्थलों के प्लाट आवंटन को लेकर नई नीति का एजेंडा भी रखा गया। इसके तहत अब धार्मिक प्लाट का आवंटन निलामी के जरिये किया जाएगा। हालांकि, इसका फार्मूला कमेटी तय करेगी। डीडीए बोर्ड के सदस्यों ने बताया कि इस नीति को लागू करते समय इलाके की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) का भी ध्यान रखा जाए। मसलन, जिस इलाके में किसी धर्म विशेष की अधिक आबादी हो, वहां दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत दी जाए या नहीं, यह बात कमेटी तय करेगी। डीडीए की ओर से गठित चार सदस्यीय कमेटी में तीन राजनीतिक (विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा, सोमनाथ भारती) और एक अधिकारी (मनीष गुप्ता) को शामिल किया गया है। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि धार्मिक स्थलों के प्लाट का मामला संवेदनशील होता है। नीलामी की प्रकिया बेहतर तो है, लेकिन इससे सिर्फ पैसे वाली संस्थाओं को लाभ मिलेगा। नई नीति में कहा गया है कि देशभर से कोई भी व्यक्ति या संस्था दिल्ली में धार्मिक स्थल बनाने के लिए प्लाट का आवेदन कर सकती है।

दिल्ली में बैठकर अमेरिकियों को ठग रहे थे 26 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अमेजन अकाउंट हैक होने का संदेश भेजकर करते थे ठगी

दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली में बैठकर अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाली पांच महिलाओं सहित 26 लोगों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। आरोपित फतेहपुरबेरी के सुल्तानपुर गांव में फर्जी काल सेंटर चला रहे थे। आरोपितों को इस काम वेतन भी मिलता था। इसके अलावा ठगी की रकम से इंसेंटिव भी दिया जाता था। पुलिस ने काल सेंटर से 29 कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। काल सेंटर के मालिक कयूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की टीम को सुल्तानुपर के मंडी रोड पर फर्जी काल सेंटर चलाने की सूचना मिली। गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वे अमेरिका के लोगों को ठगते थे। ठगी के लिए आरोपित अमेरिकी नागरिकों को संदेश भेजते थे कि उनका अमेजन अकाउंट हैक हो गया है। इसके बाद पीड़ित को फोन कर एक एप डाउनलोड करने के लिए कहते, जिसकी मदद से पीड़ित का फोन हैक कर लेते थे। इसके बाद उनके खाते से रुपये निकाल लेते थे। आरोपितों ने पिछले सात माह में अमेरिका के 1,250 से ज्यादा लोगों से करीब चार करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपितों को ठगी के लिए 25 हजार से एक लाख रुपये तक का वेतन मिलता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

10 अक्टूबर को होगी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। अभ्यर्थी upsconline.nic पर 19 जुलाई तक पसंद के परीक्षा केंद्र अपडेट कर सकते हैं।

भूपेंद्र, स्मृति समेत कई मंत्रियों को कैबिनेट समितियों में मिली जगह

जिम्मेदारी ▶ सरकार ने मंत्रिमंडल की आठ समितियों का किया पुनर्गठन

अमित शाह सभी आठ समितियों में हैं, जबकि राजनाथ छह में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली


श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव।


महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी।


ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। फाइल/जागरण आर्काइव

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद कैबिनेट की आठ समितियों का भी पुनर्गठन कर इनमें कई नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को जहां राजनीतिक मामलों की अहम समिति में जगह मिली है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कैबिनेट समितियों की अलग-अलग सौंपी गई जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह सभी आठ समितियों में हैं, जबकि राजनाथ सिंह छह में। छह समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पास है, जबकि एक शाह के पास और एक राजनाथ के पास।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की समितियों का पुनर्गठन अपरिहार्य माना जा रहा था। सरकार के सियासी कदमों से जुड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति का पुनर्गठन करते हुए नए मंत्रियों सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव और मनसुख मांडविया को इसमें शामिल किया गया है। स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह को भी इसमें पहली बार शामिल किया गया है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर और हर्षवर्धन जैसे पूर्व मंत्रियों के स्थान पर इन्हें जगह मिली है।

कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति में नए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरन रिजिजू और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को शामिल किया गया है। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को भी इसमें जगह मिली है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति में अन्य कोई बदलाव नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास समिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति में नए शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एकमात्र नया बदलाव हैं। निवेश और विकास से संबंधित कैबिनेट समिति में तीन नए कैबिनेट मंत्रियों को जगह मिली है। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। कैबिनेट की रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी समिति में भी अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव के साथ धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम व आवास मंत्री हरदीप पुरी को शामिल किया गया है। कैबिनेट में प्रमोशन पाने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी तथा जदयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बने आरसीपी सिंह को बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस समिति में जगह दी गई है।

नए कैबिनेट मंत्रियों में अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव को सबसे ज्यादा दो-दो समितियों में शामिल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जहां कैबिनेट की आवास संबंधी समिति के प्रमुख हैं, वहीं राजनीति, सुरक्षा, संसदीय मामलों, आर्थिक से लेकर सरकार की रीति-नीति के फैसले से जुड़ी सभी आठ कैबिनेट समितियों में शामिल हैं।

वित्त मंत्री होने के नाते निर्मला सीतारमण सात समितियों का हिस्सा हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट की छह समितियों में शामिल हैं, जिनमें संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता भी उनके जिम्मे है। सड़क परिहवन मंत्री नितिन गडकरी चार कैबिनेट समितियों में शामिल हैं।

मानसून सत्र के लिए रणनीति पर शीर्ष भाजपा नेताओं ने की चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा केंद्रीय मंत्रियों ने संसद के आगामी मानसून सत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा करने और विपक्ष का मुकाबला करने को लेकर पार्टी की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को एक बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर हुई, जो एक घंटे से अधिक समय तक चली।

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है और कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद यह पहला सत्र होगा। दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा भयावह थी। विपक्षी दलों द्वारा यह मुद्दा उठाकर सरकार को घेरे जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और मुख्तार अब्बास नकवी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व वी मुरलीधरन सहित अन्य मंत्री बैठक में उपस्थित थे। उनके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी भी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि भाजपा नेताओं ने आगामी सत्र के लिए संसद में पार्टी की रणनीति पर और पूरक अनुदान मांगों और महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि बंगाल में भाजपा की हार के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं और वह कोरोना की दूसरी लहर से जुड़े मुद्दे उठाने की योजना बना रहा है। वहीं, भाजपा अपनी रणनीति को और सुदृढ़ करना चाहती है, ताकि विपक्ष का कारगर तरीके से मुकाबला कर सके।

लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए ट्वीट हटाएं साकेत गोखले : दिल्ली हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ साकेत ने पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में घर खरीदने के मामले में आय के स्रोत को लेकर उठाया था सवाल


दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। फाइल/इंटरनेट मीडिया

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी व संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव रहीं लक्ष्मी एम. पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट तत्काल हटाने का निर्देश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वर्षों की निस्वार्थ सेवा व परिश्रम से हासिल की गई प्रतिष्ठा एक विचारहीन टिप्पणी पर नहीं गिर सकती है। लक्ष्मी पुरी की तरफ से साकेत गोखले के खिलाफ दायर किए गए पांच करोड़ रुपये के मानहानि के दावे पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में साकेत गोखले को तत्काल वे ट्वीट हटाने का निर्देश दिया, जिन पर पुरी ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही कहा कि अगर गोखले 24 घंटे में ट्वीट नहीं हटाएं तो ट्विटर सभी ट्वीट हटा दे। इसके साथ ही पीठ ने साकेत गोखले को निर्देश दिया कि वह भविष्य में लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई अपमानजनक ट्वीट नहीं करें।

गौरतलब है कि साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि पुरी दंपती ने स्विट्जरलैंड में 25 लाख डालर का एक घर खरीदा था और इस खरीदारी की आय का उनके पास पर्याप्त वैध स्रोत नहीं था। इसके जवाब में पुरी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी थी कि संयुक्त राष्ट्र का वेतन कर मुक्त होता है और 2006 में खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह से वैध है। इसके साथ ही उन्होंने मानहानि का दावा किया था। अब पीठ ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के मौजूदा दौर में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अपमान करना बच्चों का खेल बन गया है। बस, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर जाएं और जो मन में आए पोस्ट कर दें। इसके बाद इस तरह के पोस्ट पर हजारों प्रतिक्रियाएं आती हैं और इस प्रक्रिया में जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है।

गोखले के ट्वीट में निहित झूठे अभ्यावेदन पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि गोखले से औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल स्थायी आदेश की जरूरत है। पीठ ने मुख्य वाद पर समन जारी करते हुए चार सप्ताह के अंदर गोखले को लिखित बयान पेश करने का निर्देश भी दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस सितंबर को होगी।

आर्थिक सुधारों वाले विधेयकों को पारित करवाने पर होगा जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मानसून सत्र में 17 विधेयक होंगे पेश, दिवालिया कानून में संशोधन विधेयक भी शामिल


मानसून सत्र पर रहेंगी निगाहें। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी समझे जाने वाले कानूनी संशोधनों को लेकर सरकार अब देरी के मूड में नहीं है। मानसून सत्र में देश की आर्थिक गतिविधियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले डेढ़ दर्जन विधेयक पारित करवाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। इनमें दिवालिया कानून (इंसाल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड-आइबीसी) में संशोधन भी शामिल है।

अप्रैल, 2021 में सरकार ने आइबीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। अब अध्यादेश की जगह संशोधित कानून लाया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद छोटे और मझोले क्षेत्र की कंपनियों में बड़ी संख्या में दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। संशोधित कानून के माध्यम से छोटी व मझोली कंपनियों में दिवालिया प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक तरीके से और बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकेगा। कोल बीयरिंग एरियाज (अधिग्रहण व विकास) संशोधन विधेयक, 2021 कोयला खनन क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लाया जा रहा है। संशोधन के जरिए जिन कंपनियों को कोयला खनन क्षेत्र दिया जाएगा उन्हें उस जमीन का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की छूट होगी। वहां कोयला खनन के साथ इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों से जुड़े कारोबार भी किया जा सकेगा।

सरकार बिजली कानून में संशोधन करने संबंधी बहुप्रतीक्षित विधेयक भी मानसून सत्र में लाएगी। यह कानून विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के साथ ही दूसरी सुविधाएं देने का रास्ता साफ करेगा। यह विधेयक बिजली क्षेत्र में क्रास सब्सिडी को खत्म करने और बिजली वितरण में प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ ही सीमित दायित्व वाले साझेदारी फर्म के काम काज से जुड़े कानून सीमित देयता भागीदारी यानी एलएलपी में संशोधन का एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होगा।

हिंसा मामले में ममता सरकार की बढ़ी मुश्किल

भाजपा कार्यकर्ता के शव का होगा डीएनए टेस्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▶ कलकत्ता हाई कोर्ट ने सात दिन के अंदर डीएनए रिपोर्ट मांगी

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा के मामले में ममता सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित हत्या के मामले में उनके शव का डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। इसके पहले हाई कोर्ट ने दो जुलाई को पिछली सुनवाई में अभिजीत के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को पीठ ने अभिजीत के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि डीएनए सैंपल कोलकाता में सेना के कमांड अस्पताल में लिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट सात दिन अंदर अदालत को सौंपी जाए।

दूसरी ओर, चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति ने भी हिंसा से संबंधित एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि हिंसा के मामले में अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि बंगाल में दो मई को विस चुनाव के नतीजों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इनमें भाजपा के बूथ कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की भीड़ द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। अभिजीत कोलकाता के कांकुरगाछी के शीतलतला के रहने वाले थे। उनके परिवार और भाजपा ने अभिजीत की मौत के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। दो जुलाई को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अभिजीत के शव का कमांड अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया था। इस मामले में पुलिस ने बीते शनिवार को दो मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

बंगाल में आठ विस समितियों से भाजपा विधायकों का इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर हाल में सत्तारूढ़ तृणमूल में शामिल हुए मुकुल रॉय को विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ बंगाल में मुख्य विपक्षी भाजपा आर- पार की लड़ाई पर उतर आई है। मुकुल को पीएसी अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ भाजपा विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा की सभी आठ स्थायी समितियों से इस्तीफा दे दिया।

बंगाल विस में भाजपा विधायक दल के उपनेता मनोज टिग्गा के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से मुलाकात कर समितियों से इस्तीफा सौंप दिया। विस में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिदल ने शाम को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पीएसी अध्यक्ष की नियुक्ति में पक्षपात को लेकर विस अध्यक्ष की शिकायत की। भाजपा विधायकों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को पूरी स्थिति से अवगत कराया कि कैसे बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और विरोधी दल की मर्यादा को नष्ट किया जा रहा है। कहा कि इसके खिलाफ वह राष्ट्रपति व लोस अध्यक्ष को भी ज्ञापन देंगे। बुधवार से प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में विरोधी दल के नेता, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी पत्र भेजकर बताएंगे कि कैसे बंगाल में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुवेंदु ने विस अध्यक्ष बिमान बनर्जी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के विधायक को पीएसी का अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन अध्यक्ष ने इस परंपरा को तोड़ दिया है।

महंगाई पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आक्रामक अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

23 राज्यों में पार्टी के बड़े नेता करेंगे प्रेस कान्फ्रेंस

चाहे बारिश आ जाए या धूप, केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से कोई राहत नहीं मिलने वाली।
- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

कांग्रेस ने महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। संसद के मानसून सत्र में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने का एलान करते हुए कांग्रेस ने इस मसले पर विपक्षी दलों के साथ साझा रणनीति बनाकर सरकार पर हमला करने के अपने इरादे जाहिर कर दिए।

संसद सत्र से पहले महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के जागरूकता अभियान का आगाज करते हुए पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर जान बूझकर लगातार इन्कार की रणनीति अपना रही है, मगर इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। पेट्रोल-डीजल के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ खाद्य व उपभोक्ता महंगाई से लोगों की जिंदगी कठिन हो गई है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। चिदंबरम ने महंगाई के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रबंधन की खामियों को जिम्मेदार ठहराया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 6.26 फीसद पहुंचने की चर्चा करते हुए कहा कि अनाज, सब्जी, फल और यात्रा भाड़ा सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के साथ सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम भी इसी हफ्ते और बढ़ा दिए गए हैं। चिदंबरम ने कहा कि पहली बार दशकों बाद देश में बेरोजगारी दर आठ फीसद पार कर गई है। चार करोड़ रोजगार तो अकेले लाकडाउन में चले गए। कांग्रेस की ओर से हालात सुधारने के लिए तीन प्रमुख मांगें रखते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के दाम घटाने के लिए टैक्स व सेस में कटौती की जाए। दूसरी मांग है कि उपभोक्ता के इस्तेमाल की चीजों पर फौरी तौर पर पुनर्विचार कर उस पर आयात शुल्क कम किया जाए और तीसरी मांग है कि साबुन, तेल, बिस्कुट, टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, कपड़े जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने के लिए तत्काल जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई को लेकर कांग्रेस के अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में बड़े आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की अपनी सीमाएं हैं। कांग्रेस देश भर में अपने तरीके से महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रही है। जल्द ही 23 राज्यों की राजधानियों में पार्टी के बड़े नेता 15 जुलाई तक अलग-अलग प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद मानसून सत्र में महंगाई पर पार्टी सरकार की घेरेबंदी करेगी।

13 भाषाओं में होगी नीट (यूजी)

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को घोषणा की कि पहली बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (यूजी) पंजाबी और मलयालम समेत 13 भाषाओं में होगी। अब जिन भाषाओं में परीक्षा ली जाएगी वे हैं हिंदी, पंजाबी, असमिया, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी।

प्रधान ने ट्वीट में यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में भारतीय छात्र समुदाय की सुविधा के लिए कुवैत में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए एक नया परीक्षा केंद्र खोला गया है। एनईईटी (यूजी) 2021 के लिए पंजीकरण मंगलवार शाम पांच बजे से शुरू हो गया है। जिन शहरों में परीक्षा आयोजित की जानी है, उनकी संख्या 155 से बढ़ाकर 198 की जाएगी। इसी तरह पिछले साल के मुकाबले परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पिछले साल 3,862 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। पिछले साल कोरोना के कारण 13 सितंबर को काफी सावधानियों के बीच परीक्षा हुई थी। परीक्षा में कुल 13.66 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 7,71,500 ने क्वालीफाई किया था।

जेईई मेन और नीट के बाद छात्रों को अब सीयूसेट पर फैसले का इंतजार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दुविधा

▶ शिक्षा मंत्रालय को इसी हफ्ते इस पर भी लेना होगा निर्णय

▶ विश्वविद्यालय दाखिले को लेकर अब तक बनी हुई है उलझन


परीक्षा पर जल्द निर्णय की उम्मीद। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

जेईई मेन और नीट परीक्षा की तारीखों के एलान के बाद छात्रों की निगाहें अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूसेट) पर टिकी है। यह इसलिए भी है, क्योंकि इसी महीने सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) सहित राज्यों के शिक्षा बोर्ड के बारहवीं के रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे में छात्रों की विश्वविद्यालयों और कालेजों में दाखिले को लेकर उत्सुकता बढ़ी हुई है। वहीं सीयूसेट कराने या न कराने को लेकर शिक्षा मंत्रालय अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। ऐसे में विश्वविद्यालय भी उलझन में है। माना जा है कि इसी हफ्ते इस पर कोई निर्णय हो सकता है।

शिक्षा मंत्रालय ने सीयूसेट की यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे लेकर की गई सिफारिश के बाद की है। जिसमें छात्रों के भटकाव और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए जेईई मेंस और नीट की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने को कहा है। मौजूदा समय में विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए छात्र एक साथ कई विश्वविद्यालयों में आवेदन करते हैं। हालांकि इनमें से दाखिला वे किसी एक विश्वविद्यालयों में ही लेते है। इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय इसलिए भी उलझन में हैं, क्योंकि मंत्रालय ने इसे कराने या न कराने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसके चलते दाखिले से जुड़ी वह खुद की तैयारी को भी अंतिम रूप नहीं दे पा रहे है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को ध्यान में रखने हुए पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीयूसेट को इसी साल से कराने का एलान किया था। यूजीसी ने इसे लेकर एक उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित की थी। जिसने अपनी रिपोर्ट भी मंत्रालय को दे दी है। इस बीच मंत्रालय में इसे लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। हालांकि इस पर कोई निर्णय हो पाता है, इससे पहले कैबिनेट में फेरबदल हो गया। ऐसे में सीयूसेट कराने या न कराने का जिम्मा अब नए शिक्षा मंत्री पर आ गया है।

माना जा रहा है कि यदि सीयूसेट इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्तर पर सफल रहता है तो आने वाले दिनों में इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। जिसमें सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। जो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

जल्द भरे जाएंगे उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के पद

दिए संकेत

नए शिक्षा मंत्री ने दिया संकेत, मंगलवार को राष्ट्रपति से भी की मुलाकात, मौजूदा समय में करीब दो दर्जन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद हैं रिक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली


केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से मुलाकात की। एएनआइ

केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित आइआइटी, एनआइटी और ट्रिपल आइटी जैसे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को अब अपने प्रमुखों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कुलपति और निदेशकों के खाली पड़े पदों को जल्द भरने के संकेत दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी मांगी है। स्थिति यह है कि मौजूदा समय में अकेले करीब दो दर्जन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही कुलपति के पद खाली हैं।

इस बीच, शिक्षा मंत्री प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। फिलहाल इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। यहां यह बताना उचित होगा कि राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर भी होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति उनकी ओर से ही की जाती है। हालांकि इसके लिए नामों का पैनल शार्टलिस्ट करके शिक्षा मंत्रालय की ओर से भेजा जाता है। मौजूदा समय में देश में करीब 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद खाली है, उनमें जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसे देश के प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं। इसके साथ ही आइआइटी, एनआइटी और ट्रिपल आइटी में निदेशकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में यह स्थिति तब है, जब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार को लेकर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि नीति में ऐसी स्थिति को लेकर सतर्क किया गया है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के पदों को लंबे समय तक खाली न रखने की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए कोरोना काल में कार्यकाल पूरा कर रहे जेएनयू सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलपति को मंत्रालय ने नई नियुक्ति होने तक पदों पर रहने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के खाली पदों को भरने की कोशिशें पिछले कई महीनों से चल रही थीं। लेकिन यह काम पूरा नहीं हो पाया और इससे पहले कैबिनेट में फेरबदल हो गया। इसमें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को मिल गई है।

इन विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद हैं खाली

मौजूदा समय में जिन विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद खाली हैं, उनमें जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी-शिलांग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय-छत्तीसगढ़, सागर विश्वविद्यालय-मध्य प्रदेश, बिहार और जम्मू-कश्मीर के दो-दो केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली स्थित दो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और नगालैंड का एक-एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इनमें शामिल है।

कह के रहेंगे माधव जोशी



29 विचाराधीन मुकदमों में सांसद आजम खां के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट सीतापुर के जेल अधीक्षक से तलब की अदालत ने। इनमें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से संबंधित मामले भी हैं, जो स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन हैं।

राहुल और पीके ने सिद्धू की नई भूमिका पर की चर्चा

कांग्रेस के झगड़े का समाधान निकालने को लेकर हुई बैठक में प्रियंका भी रहीं मौजूद

हरीश रावत ने कहा, तीन-चार दिन में मिल जाएगी अच्छी खबर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली


राहुल गांधी और प्रशांत किशोर। फाइल फोटो

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की मंगलवार को हुई मुलाकात के बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अंदरूनी लड़ाई का जल्द समाधान निकलने की उम्मीद बन गई है। समझा जाता है कि पंजाब में कैप्टन की चुनावी रणनीति का संचालन कर रहे प्रशांत किशोर ने नवजोत सिद्धू की सूबे में राजनीतिक भूमिका के फार्मूले पर राहुल के साथ बातचीत की। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को हाईकमान की सिरदर्दी बना चुके सिद्धू को पार्टी नेतृत्व जल्द नई जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। राहुल और पीके की मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि अगले तीन-चार दिनों में गुड न्यूज मिल जाएगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल और पीके की इस मुलाकात में पंजाब चुनाव में सिद्धू की भूमिका का स्वरूप तय करने के फार्मूले और विकल्पों पर बातचीत हुई। पीके ने इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व को सूबे की जमीनी राजनीति और चुनावी आकलनों के परिप्रेक्ष्य में सिद्धू को समायोजित करने के लिए अपने सुझाव दिए। पंजाब को लेकर हुई इस बेहद अहम मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत भी मौजूद थे।

मालूम हो कि कैप्टन से जंग लड़ रहे सिद्धू को पंजाब में बड़ी भूमिका देने के लिए प्रियंका शुरू से सक्रिय रही हैं। पिछले दिनों प्रियंका की पहल पर ही राहुल ने सिद्धू से मुलाकात की थी और उसके बाद पिछले हफ्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत की थी। इस मुलाकात के दौरान सोनिया ने सिद्धू को सम्माजनक भूमिका दिए जाने पर मुख्यमंत्री से चर्चा की और स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब चुनाव में पार्टी का चेहरा कैप्टन ही रहेंगे। हाईकमान से मिले इस भरोसे के बाद अमरिंदर ने भी कहा था कि पंजाब कांग्रेस में बदलाव को लेकर हाईकमान जो भी फैसला लेगा उसे वे स्वीकार करेंगे। हालांकि इसके बावजूद पिछले एक हफ्ते में सिद्धू को जिम्मेदारी सौंपने का एलान नहीं हो पाया और वे पिछले दो तीन दिनों में कैप्टन पर तंज कसते हुए कई ट्वीट कर चुके हैं। इतना ही नहीं मंगलवार को तो सिद्धू ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ संभावनाओं के द्वार खुले होने तक का संदेश देने की कोशिश की। इसे देखते हुए राहुल गांधी और पीके की मुलाकात अहम मानी जा रही है और हरीश रावत ने भी यही संदेश देने का प्रयास किया कि पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझने में अब ज्यादा देर नहीं है। रावत ने तो खुले तौर पर यह बयान भी दे दिया है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष समेत संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे।

सिद्धू ने पहले आप को सराहा, फिर उसी पर साधा निशाना

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़ : नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से मंगलवार को किए गए दो ट्वीट ने उनके कांग्रेस में रहने या आम आदमी पार्टी में जाने की दुविधा को बरकरार रखा। उनकी दुविधा का एक बड़ा कारण यह भी है कि अभी तक हाईकमान की ओर से उनके भविष्य को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारी विपक्षी पार्टी आप ने हमेशा मेरे विजन और पंजाब के लिए किए गए मेरे काम को माना है। 2017 से पहले बेअदबी की बात हो या ड्रग्स की, किसानी मुद्दों की बात हो या बिजली संकट की, मेरे काम को महत्व दिया है। आज जो मैं पंजाब माडल पेश करता हूं तो उस पर आम आदमी पार्टी की मेरे साथ सहमति रही है। यह स्पष्ट है कि वह जानते हैं कि असल में कौन पंजाब के हितों के लिए लड़ रहा है। सिद्धू के इस ट्वीट से ऐसा लगा कि वह आम आदमी पार्टी में जाने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह पलटी मार गए। सिद्धू ने एक और ट्वीट कर कहा कि आजकल विपक्षी पार्टी मेरे और अन्य वफादार कांग्रेसियों के बारे में गाती फिर रही है कि अगर तुम आप में आओगे तो कोई बात नहीं... तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। सिद्धू पहले भी बिजली के मामले में ऐसी पलटी मार चुके हैं जब पहले उन्होंने दिल्ली माडल को सराहा लेकिन बाद में उसे ही नकार दिया। उधर, सिद्धू के पहले ट्वीट का जवाब देते हुए आप के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कहा कि असल में पंजाब की लड़ाई कौन लड़ रहा है, यह हम जानते हैं। सिद्धू ने पहले ट्वीट के साथ वीडियो भी शेयर किया था जो 2017 का है। तब उन्होंने भाजपा छोड़ी थी और उनकी आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बातचीत चल रही थी। इस वीडियो में पंजाब मामलों के प्रभारी संजय सिंह उनके भाजपा को छोड़ने की प्रशंसा कर रहे हैं और भगवंत मान उन्हें सबसे ईमानदार नेता बता रहे हैं। वीडियो में भगवंत मान कह रहे हैं कि मैंने तो खुद सिद्धू को आप में आने का आफर दिया था। वह तो मेरे लाफ्टर चैलेंज में जज रहे हैं।

बिजली समझौतों की सुरक्षा के लिए पंजाब कांग्रेस ने नहीं लिया फंड : कैप्टन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि पंजाब कांग्रेस ने प्राइवेट थर्मल प्लांटों से कोई भी राजनीतिक फंड नहीं लिया है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन फंडों का यह राजनीतिक दल हवाला दे रहे है, वह आल इंडिया कांग्रेस ने 2009 से 2014 के बीच में लिए थे। इसका बिजली समझौते के साथ कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि कुछ बिजली कंपनियों से पंजाब कांग्रेस ने फंड नहीं लिए, बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 2009 और 2014 में लिए थे। इनका राज्य की मौजूदा सरकार के साथ कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली खरीद समझौते (पीपीए) अकाली-भाजपा सरकार द्वारा किए गए थे। अब उनकी (कैप्टन) सरकार इनके लिए कानूनी तौर पर पाबंद है और आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य पर भारी जुर्माने के बिना इनको रद नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के खजाने पर और अधिक बोझ डाले बिना बिजली समझौतों के दुष्प्रभावों को ख़त्म करने के लिए कानूनी संभावनाएं तलाश रही है। जबकि अकालियों ने पिछली सरकार के दौरान अपने सहयोगी भाजपा के साथ मिलकर अपनी जेबें भरने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया था।

उन्होंने कहा कि यहां तक कहा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बादलों के नेतृत्व में अकालियों ने 100 करोड़ रुपये का राजनैतिक फंड लिया और एलान सिर्फ 13 करोड़ रुपये का किया। बाकी फंडों से अपनी निजी जेबें भर ली। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, प्राइवेट बिजली कंपनियों की तरफ से आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से लिए गए फंड के विपरीत अरविंद केजरीवाल की पार्टी 'आप' द्वारा साल 2014 के मतदान के दौरान लिया गया चंदा पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नजर में है। क्योंकि इनका न तो कभी भी हिसाब-किताब किया गया और न ही घोषित किया गया। यहां बताने योग्य है कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने 50 लाख रुपये के चार चेकों से संबंधी मामला दर्ज किया है जो साल 2014 के दिल्ली विधान सभा मतदान के दौरान आप को कथित तौर पर दिए गए थे। बीते साल दिल्ली पुलिस ने चार कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी का मामला दर्ज किया था।

मुख्यमंत्री ने दोनों पार्टियों को बीते 10 सालों में अपने-अपने राजनीतिक फंडों का एलान करने की चुनौती दी ताकि पंजाब के लोग इनके दावों और जवाबी-दावों के पीछे की सच्चाई को जान सकें।

शरद पवार से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता

राज्य ब्यूरो, मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एचके पाटिल के साथ राज्य के दो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की। यह मुलाकात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के उस आरोप के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री उन पर नजर रख रहे हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस कोटे के दो वरिष्ठ मंत्रियों बालासाहब थोराट एवं अशोक चह्वाण ने मंगलवार शाम महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एचके पाटिल के साथ शरद पवार के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। राकांपा इसे सद्भावना भेंट बता रही है, जबकि बालासाहब थोराट के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने इस मुलाकात में पवार से राज्य के विभिन्न मुद्दों सहित केंद्र सरकार द्वारा नवगठित सहकारिता मंत्रालय पर चर्चा की। इस मुलाकात में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शामिल नहीं थे। एक दिन पहले ही नाना के एक बयान पर शरद पवार ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया था कि वह बहुत छोटे नेता हैं। उनकी बात पर वह कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। कहा जा रहा है कि इन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का समूह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेगा।

इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उनके द्वारा दो दिन पहले दिए गए बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। उनके अनुसार हर पार्टी के नेतृत्व का दायित्व होता है कि वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाए। हमें समझना चाहिए कि सरकार और पार्टी चलाने का तरीका अलग-अलग होता है।

दिग्विजय के हिंदू विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस में ही उठे विरोधी सुर

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयानों से पार्टी न इत्तेफाक रखती है और न कभी खुद को अलग किया। लेकिन अब हिंदू विरोधी बयानों को लेकर पार्टी में ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ सुर उठ गए हैं। स्पष्ट कहा जाने लगा है कि ऐसे बयानों से कांग्रेस को काफी नुकसान होता रहा है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के सदस्य विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को इस मामले में पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 2003 में जब से दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हुए हैं, वह हिंदू विरोधी बयान देते आ रहे हैं। वह एक वर्ग को खुश करने की मंशा से हिंदुओं को नाराज करते रहे हैं। देश की बड़ी आबादी उनके बयान को ही कांग्रेस का आधिकारिक बयान मान लेती है और पार्टी से नाराज हो जाती है। एक तरफ हिंदू दूर हो रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह जिस वर्ग को खुश करना चाहते हैं, वह भी पार्टी से दूर होता जा रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370, बाटला हाउस मुठभेड़ का मामला, आतंकी ओसामा के नाम में जी जोड़ना आदि कई मामले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के लिए काम कर चुके राय ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गोवा का प्रभारी बनाया गया, लेकिन कांग्रेस जीतकर भी सरकार नहीं बना सकी। सिंह के प्रभारी रहते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। राय ने उप्र में कांग्रेस की दुर्गति और मध्य प्रदेश में कमल नाथ सरकार जाने में भी दिग्विजय सिंह की भूमिका की समीक्षा की मांग की है।

> पूरा देश जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के पक्ष में है। फिर भी दिग्विजय सिंह उल्टा बयान देते हैं। जो कांग्रेस नेता मुस्लिमों के मसीहा बनकर तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं, वे सार्वजनिक बयानबाजी न करें। चाहें तो अपने घर में उनकी उपासना पद्धति अपना लें। कांग्रेस में पहले मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी, लेकिन दिखावे के तौर पर। अब तो खुलेआम हिंदू विरोधी बयान आ रहे हैं। इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है।
> -विश्वबंधु राय, एआइसीसी सदस्य

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने भाजपा के एकाधिकार में सेंध लगाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का नया रास्ता निकाला था। बतौर मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कई ऐसे निर्णय लिए थे, जो सीधे हिंदू वर्ग की धार्मिक भावना से जुड़े थे। जैसे मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ का जीर्णोद्धार, उज्जैन महाकाल मंदिर में निर्माण व सुविधाओं के लिए करोड़ों की योजना और हर गांव में गोशाला निर्माण आदि। इसके अलावा जब अयोध्या में राममंदिर के लिए शिलान्यास किया गया, तब भी कमल नाथ ने प्रदेश में कांग्रेस कार्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित कराया था।

पिता के सरकारी बंगले से बेदखल हो सकते हैं चिराग

राज्य ब्यूरो, पटना: संभव है कि लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) अध्यक्ष चिराग पासवान लुटियन जोन के 12 जनपथ वाले बंगले से बेदखल हो जाएं। हाल ही में केंद्र में मंत्री बने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस बड़े भाई रामविलास पासवान के पर्याय की तरह रहे इस आवास में नहीं रहना चाहते। यह चिराग के लिए झटका है क्योंकि पारस इस आवास में रहने जाते तो उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता। लोगों से कहते कि चाचा पार्टी से बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं। बेघर भी कर दिया।

दिल्ली के जनपथ स्थित 12 नंबर का यह बंगला केंद्रीय मंत्री या उस स्तर के लोगों के लिए निर्धारित है। चिराग सांसद हैं। वीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री बनने पर 14 मार्च, 1990 को रामविलास पासवान को यह आवास मिला था। यहीं रहते चिराग दो बार सांसद बने। सन् 2009 में पासवान लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2010 में राज्यसभा में मनोनीत हुए। पासवान की राजनीतिक हैसियत को देखते हुए तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने आवास बदलने के लिए उन पर दबाव नहीं बनाया।

पंकजा मुंडे ने संकेतों में साधा देवेंद्र फड़नवीस पर निशाना

राज्य ब्यूरो, मुंबई


भाजपा की राष्ट्रीय सचिव ने समर्थकों से कहा- हमारे नेता मोदी, शाह और नड्डा

भाजपा की राष्ट्रीय सचिव एवं महाराष्ट्र की पूर्व विधायक पंकजा मुंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना नेता बताते हुए कहा कि महाभारत में कौरवों की संख्या 100 थी और पांडव सिर्फ पांच थे। लेकिन पांडव जीते, क्योंकि उनके पास धैर्य था। माना जा रहा है कि कौरव-पांडव का उद्धरण देते हुए पंकजा ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस पर निशाना साधने की कोशिश की है।

पिछले सप्ताह हुए मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में पंकजा की बहन एवं बीड से दूसरी बार सांसद बनी प्रीतम मुंडे के बजाय वंजारी समाज के ही ओबीसी नेता भागवत कराड को मंत्री बनाया गया है। इसे राज्य की राजनीति में मुंडे परिवार का कद छोटा करने की कोशिश माना जा रहा है। इससे नाराज स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों के लिए चुने गए मुंडे समर्थक सौ से अधिक नेताओं ने अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। मंगलवार सुबह अपने मुंबई आवास के बाहर जमा हुए इन्हीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भाजपा की राष्ट्रीय सचिव हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे नेता हैं। हमें क्यों डरना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कभी मेरा अपमान नहीं किया। मैं आत्मसम्मान के साथ राजनीति करती हूं।

इसी कड़ी में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए पंकजा ने कहा कि यह सच है कि मुझे खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन देखो, मैं यहां खड़ी हूं। मैं खत्म नहीं हुई हूं। मैं किसी से नहीं डरती। मैं स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की विरासत को आगे ले जा रही हूं। जिन्होंने कभी सत्ता और पद के लिए राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा वंचितों को आगे बढ़ाया। मैं विधायक, सांसद और मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करती। यह मुंडे संस्कृति नहीं है। न ही हम दबाव की राजनीति करते हैं। पंकजा ने यह कहते हुए अपने समर्थकों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया कि भाजपा मेरा घर है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। आप लोग भी विरोधियों के हाथों में मत खेलिए।

बता दें कि देवेंद्र फड़नवीस मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री रहीं पंकजा मुंडे 2019 का विधानसभा चुनाव अपने ही चचेरे भाई धनंजय मुंडे से हार गई थीं। इस हार के बाद वह कई बार कह चुकी हैं कि उन्हें हराने में प्रदेश भाजपा के ही एक वर्ग की बड़ी भूमिका रही है।

अब गुजरात में भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की तैयारी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- राज्य सरकार कर रही है विभिन्न पहलुओं पर विचार

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुजरात सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने पर विचार कर रही है। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

गत दिनों उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-2021 का मसौदा पेश किया गया है। उपमुख्यमंत्री पटेल से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो बच्चों का कानून लागू है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे के संदर्भ में भी सरकार विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है। आवश्यक हुआ तो गुजरात में भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाएगा।

गौरतलब है कि गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम-2005 अमल में है, जिसके तहत दो बच्चों से अधिक होने पर दंपत्ती स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें संशोधन कर दो बच्चों से अधिक होने पर सरकारी योजनाओं के लाभ व सब्सिडी आदि से भी वंचित करने की नीति लागू की जा सकती है।

भाजपा महासचिव ने की कर्नाटक में नई जनसंख्या नीति की वकालत

समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, भाजपा के महासचिव सीटी रवि ने कर्नाटक में भी असम व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नई जनसंख्या नीति लाए जाने की वकालत की। कर्नाटक के चिकमगलुरु से विधायक रवि ने कहा, 'प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। जनसंख्या विस्फोट होने पर हर नागरिक की जरूरतों की पूर्ति मुश्किल होगी।' भाजपा शासित कर्नाटक के कानून मंत्री बासवराज बोम्मई सोमवार को कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हिमाचल के 28वें राज्यपाल

राज्य ब्यूरो, शिमला


शिमला स्थित राजभवन में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद की शपथ लेत राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (बाएं)। जागरण

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मानते हैं कि गोवा की मुक्ति में हिमाचल प्रदेश के लोगों की अहम भूमिका रही है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने कांगड़ा जिला के राम सिंह का जिक्र भी किया। बकौल राज्यपाल, 1961 में गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्ति मिली थी, लेकिन इससे पहले मुक्ति आंदोलन यानी गोवा लिबरेशन मूवमेंट में हिमाचल प्रदेश के कई लोगों ने अपना योगदान दिया। इनमें कांगड़ा के राम सिंह एक थे। मैं उनके परिजनों को ढूंढकर मिलने का प्रयास करूंगा। राज्यपाल ने कहा, 'मैं और गोवा के लोग ऋणी हैं।' उन्हें प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी उपस्थित रहीं।

पत्रकारों के साथ बातचीत में राज्यपाल ने कार्यों के संदर्भ में राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय में एक महीन रेखा भी खींच दी। उन्होंने संकेत दिया कि वह काम करेंगे और प्रदेश सरकार की विकास की पहल को आगे लेकर जाएंगे।

राज्यपाल ने कहा, 'मेरी कोई व्यक्तिगत योजना या प्राथमिकताएं नहीं रहेंगी। टकराव की स्थिति तब पैदा होती है, जब सरकार व राजभवन विपरीत दिशा में सोचते व चलते हैं। मेरा दायित्व सरकार की कार्य योजनाओं को आगे लेकर जाना है।'

आर्लेकर को याद आए 'कदम कदम बढ़ाए जा' की धुन बनाने वाले कैप्टन राम सिंह

जागरण टीम, धर्मशाला

- अब धर्मशाला में नहीं रहते राम सिंह के वंशज

मंगलवार को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद जो पहले शब्द कहे उनमें कैप्टन राम सिंह को याद किया। नवनियुक्त राज्यपाल ने कहा कि कांगड़ा के राम सिंह ने हमें गोवा की मुक्ति के लिए प्रेरित किया। आखिर कौन थे राम सिंह? गोवा 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, 60 साल बाद भी राज्यपाल को कांगड़ा के राम सिंह याद हैं तो जाहिर है, राम सिंह बड़ी हस्ती थे।

राज्यपाल बात कर थे 1914 में खनियारा में पैदा हुए कैप्टन राम सिंह ठाकुर की, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का तराना 'कदम-कदम बढ़ाए जा' को स्वरबद्ध किया था। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सामने ऐसी जोश भरी प्रस्तुति दी कि नेताजी ने उन्हें अपनी वायलिन तोहफे में दे दी। यह 21 अक्टूबर 1943 का दिन था। वह आजादी के बाद आल इंडिया रेडियो की शान रहे। अब उनके वंशज बेशक धर्मशाला में नहीं रहते, लेकिन उनकी याद अमिट है।

गोरखा राइफल में ब्वाय बैंड से शुरू किया सफर : 15 अगस्त, 1914 को फौजी परिवार में जन्मे राम सिंह के पिता का नाम दिलीप सिंह ठाकुर था, जो हवलदार थे। आठवीं तक शिक्षा लेने के बाद 1928 में 14 वर्ष की आयु में सेकेंड फर्स्ट गोरखा राइफल में भर्ती हुए। राम सिंह ने अपने नाना नत्थू चंद ठाकुर से शास्त्रीय संगीत भी सीखा। उन्होंने अंग्रेज एनएस होस्टन और डेविड से ब्रासबैंड, स्ट्रिंगबैंड और डांसबैंड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें डेढ़ रुपये वेतन मिलता था। वेतन की बचत कर उन्होंने वायलिन खरीदा। आजाद हिंद रेडियो स्थापित हुआ तो वह सिंगापुर और रंगून रेडियो स्टेशन में संगीत निर्देशक हुए।

नेता जी ने कहा था, आसान कौमी तराना बनाओ : नेता जी तीन जुलाई, 1943 को सिंगापुर पहुंचे तो उनके स्वागत में राम सिंह ने 'सुभाष जी सुभाष जी वो जान-ए-हिंद आ गए' गाया। नेताजी ने शाबाशी देते हुए कहा था, 'अब तुम सरल व सुगम कौमी तराना बनाओ', जिसे आजाद हिंद फौज के सभी वीर सेनानी उत्साह से गाएं। फिर राम सिंह ने 'कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा'....'भारत के जां निसारो हिलमिल के गीत गाओ हिंदुस्तान हमारा है', 'शीश झुका कर भारत माता तुझको करूं प्रणाम' व 'सबसे ऊंचा दुनिया में प्यारा तिरंगा झंडा हमारा' जैसे गीत बनाए।

लोकतंत्र की ताकत

पति ने बीडीसी का चुनाव लड़ाया और बन गई प्रमुख, बीए पास हैं अनुसूचित जाति की ब्लाक प्रमुख सोनिया

पति सफाई कर्मचारी, पत्नी बनी ब्लाक प्रमुख

बृजमोहन मोगा, सहारनपुर


पति सुनील कुमार के साथ बलियाखेड़ी ब्लाक प्रमुख सोनिया। जागरण

लोकतंत्र कतार के अंतिम व्यक्ति को भी नेतृत्व का अवसर प्रदान करता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कामयाबी है। उप्र के सहारनपुर में सफाईकर्मी सुनील कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ब्लाक क्षेत्र में वह रोज सफाई करते हैं, एक दिन उनकी पत्नी सोनिया वहीं की ब्लाक प्रमुख बन जाएंगी। अब सोनिया भाजपा से ब्लाक प्रमुख का दायित्व संभाल चुकी हैं।

सुनील कई वर्षों से बलियाखेड़ी ब्लाक में सफाई कर्मचारी हैं। उनकी पत्नी सोनिया गृहणी हैं। बीए पास पत्नी को सुनील ने बीडीसी का चुनाव लड़वा दिया। चुनाव जीतने के बाद ब्लाक प्रमुख पद के लिए मारामारी शुरू हुई। सत्ताधारी भाजपा को यहां आरक्षण के मुताबिक अनुसूचित जाति की शिक्षित महिला की तलाश थी। भाजपा नेता मुकेश चौधरी ने बीडीसी सोनिया के नाम का प्रस्ताव दिया तो भाजपा में आम सहमति बन गई। अब सोनिया के पास भाजपा का समर्थन था। रस्साकशी में विपक्षी एक-एक कर हटते गए और सोनिया को बलियाखेड़ी ब्लाक का निर्विरोध ब्लाक प्रमुख चुन लिया गया।

ऐसे मिला मौका : गांव नल्हेडा गुर्जर निवासी सुनील कुमार विकासखंड बलियाखेडी में सफाई कर्मचारी के पद पर अपने ही गांव में कार्यरत हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित हुए तो बीडीसी की सीट आरक्षण के चलते अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षित हो गई। गांव वालों के कहने पर सुनील कुमार ने बीडीसी सदस्य के लिए अपनी पत्नी सोनिया को चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। ब्लाक प्रमुख पद भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ तो भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी ने पढ़ी-लिखी सोनिया को भाजपा की ओर से प्रमुख पद का प्रत्याशी बनवा दिया। नामांकन करने के साथ ही 26 वर्षीय सोनिया निर्विरोध ब्लाक प्रमुख निर्वाचित हो गईं।

प्रमुखी पांच, नौकरी 60 साल की: ब्लाक प्रमुख सोनिया कहती हैं कि चुनाव में पति सुनील कुमार व परिवार का सहयोग रहा है। उनका कहना है कि ब्लाक प्रमुख के नाते वह गांवों के विकास के लिए काम करेंगी लेकिन घर तो पति की तनख्वाह से ही चलता है। उनके पति ने भी निर्णय लिया है कि वह नौकरी करते रहेंगे। प्रमुखी तो पांच साल की है लेकिन नौकरी पूरे 60 साल की।

सपा के घोषणा पत्र में गरीबों, किसानों व युवाओं के लिए होगा खास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पांच साल बाद फिर यूपी की सत्ता में आने की कोशिश में समाजवादी पार्टी इस समय अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटी है। सपा इन दिनों अपने चुनावी घोषणापत्र पर काम कर रही है। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता घोषणा पत्र के लिए सुझाव दे रहे हैं। दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों के घोषणा पत्रों को भी खंगाला जा रहा है।

सपा के इस बार के घोषणापत्र में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए कई वादे होंगे। इनमें गरीबों को फ्री बिजली व पानी से लेकर युवाओं को रोजगार देने जैसी घोषणा शामिल की जा सकती है। किसानों को बीज, खाद आदि के लिए सस्ते दरों पर कर्ज भी मुहैया कराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी इस बार चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने में बड़ी सावधानी बरत रही है।

मारुति हरियाणा में 900 एकड़ में लगाएगी बड़े प्लांट : चौटाला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार निर्माता कंपनी मारुति के हरियाणा से पलायन के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने स्पष्ट किया है कि मारुति करीब 900 एकड़ जमीन में जल्द ही दो बड़े प्लांट लगाने जा रही है। मारुति ने खरखौदा में 800 एकड़ जमीन अपनी कंपनी की गाड़ियां बनाने के लिए तथा 100 एकड़ जमीन सुजुकी की बाइक बनाने के लिए लेने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा गाड़ियों की बैट्री बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों ने भी हरियाणा में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है।

हरियाणा के उद्योग मंत्री के नाते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को मैं कांग्रेस में इकलौता पढ़ा लिखा आदमी मानता हूं, लेकिन मारुति के हरियाणा से पलायन को लेकर दिया गया उनका बयान अपरिपक्व है। सुरजेवाला सिर्फ सनसनी पैदा करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि मारुति कुछ तकनीकी स्टाफ शिफ्ट कर रही है, लेकिन कारों का उत्पादन हरियाणा में ज्यों का त्यों रहेगा।

हद पार कर रहा कृषि कानून विरोधी आंदोलन : दुष्यंत ने कहा कि राज्य में कृषि कानून विरोधी आंदोलन हद पार करता जा रहा है। यह पूरी तरह से राजनीतिक है। कोई सरपंच के चुनाव की तैयारी कर रहा तो कोई कांग्रेस से जुड़ा है। यह आंदोलन पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। यह राजनीतिक दल का आंदोलन है। उपद्रव मचाने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है।

लखनऊ से संभल तक बुना जा चुका था अलकायदा का जाल

नापाक मंसूबे ▶ उत्तर प्रदेश में गहरी जड़ें जमा चुका है अंसार गजवातुल हिंद, आतंकी मिनहाज व मसीरुद्दीन से शुरू की गई पूछताछ, साथियों की जानकारी उगलवाने में जुटी टीम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल का गहरा जाल लखनऊ से संभल तक बुना जा चुका है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी मिनहाज अहमद व मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर के संपर्क में 20 से अधिक जिलों के युवक थे। खासकर मिनहाज इंटरनेट मीडिया के जरिये उनके लगातार संपर्क में रहता था। एटीएस ने मिनहाज व मसीरुद्दीन को पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे नए सिरे से पूछताछ शुरू की है और उनके साथियों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि मिनहाज के लगातार संपर्क में रहे दो युवकों से भी लंबी पूछताछ की गई है और अब दोनों का मिनहाज से सामना कराए जाने की भी तैयारी है। एटीएस के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी भी दोनों आतंकियों से पूछताछ करेंगे।

आतंकियों का स्वजन से होगा सामना: एटीएस मुख्यालय में मिनहाज व मसीरुद्दीन से उनके परिवारीजन का भी सामना कराए जाने की तैयारी है ताकि सामने आए तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। मिनहाज व मसीरुद्दीन ने विस्फोटक व बम बनाने की सामग्री कहां से ली थी। कानपुर में पिस्टल कहां और किसके जरिये हासिल हुई थी। एटीएस दोनों से ऐसे स्थानों की तस्दीक कराएगी। छानबीन में लखनऊ, कानपुर, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर व कुछ अन्य जिलों के निवासी ऐसे युवकों की जानकारी भी मिली है, जो मिनहाज के लगातार संपर्क में थे। इन्हें मिनहाज अक्सर इंटरनेट मीडिया के जरिये संदेश भेजा करता था। इन संदेशों से किस षड्यंत्र का तानाबाना बुना जा रहा था, इसका पता लगाना भी बेहद अहम है।

चैटिंग से खुलेंगे राज : एटीएस मिनहाज के मोबाइल फोन से टेलीग्राम एप पर की गई चैटिंग का ब्योरा जुटाने का भी प्रयास कर रही है ताकि कुछ बिंदुओं पर उससे और गहराई से पूछताछ शुरू की जा सके। मिनहाज से अलकायदा के उन हैंडलर के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, जिनके वह सीधे संपर्क में था। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर छानबीन को आगे बढ़ाया जा रहा है।

अयोध्या, काशी में अलर्ट : एटीएस सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान-अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र से अलकायदा के इंडियन सबकांटीनेंट माड्यूल का संचालन कर रहा उमर हलमंडी प्रदेश के कई युवकों के सीधे संपर्क में है। यही वजह है कि अयोध्या, मथुरा, काशी समेत प्रदेश की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

बिहार–उप्र की ट्रेनों में धमाके करना चाहती थी आइएसआइ

राज्य ब्यूरो, पटना

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) बिहार और उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में टाइमर बम लगाने की साजिश रच रही है। खासकर ऐसी ट्रेन, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर सफर करते हैं, उसको बम से उड़ाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के अनुसार, दरभंगा पार्सल विस्फोट इसी मिशन का हिस्सा था। मामला संज्ञान में आने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर रेल पुलिस के साथ पुलिस-प्रशासन को भी अलर्ट किया है। रेल पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सभी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) जवानों को अलर्ट रहने और स्थानीय पुलिस-प्रशासन के साथ समन्वय कर कड़ी चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है।

तारों को जोड़ो और ट्रेन में बम लगाओ : जानकारी के अनुसार, आइएसआइ ने पंजाब में अपना संपर्क बढ़ाने के लिए आतंकियों को टाइमर के साथ बम देने की पेशकश की। आतंकियों को निर्देश दिया कि तारों को जोड़ो और ट्रेनों में बम लगाओ। ऐसी ट्रेनों में बम लगाने को कहा गया जिसमें उप्र-बिहार के मजदूर आते-जाते हैं। इसका मकसद मजदूरों को निशाना बनाने के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति को बाधित करना था। अतिरिक्त महानिदेशक रेल निर्मल कुमार आजाद ने वरीय अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर बैठक की।

पूछताछ में मिले अहम सुराग : दरभंगा पार्सल विस्फोट मामले में पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ में ट्रेनों में विस्फोट की साजिश से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआइए) भी इस बिंदु पर और विस्तार से जांच कर रही है।

बंगाल में बम की फैक्ट्री बनाने की साजिश रच रहे थे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग का मानना है कि जमात-उल-मुजाहिदीनबांग्लादेश (जेएमबी) तथा हूजी आतंकी राज्य में बम फैक्ट्री बनाने के लिए सक्रिय थे। गत दिनों कोलकाता से गिरफ्तार जेएमबी आतंकियों के पास से मिले कागजात तथा सामग्रियों से इसका पता चला है। गिरफ्तार आतंकियों के अल-कायदा और हूजी आतंकवादी समूहों से संबंध पाए गए हैं। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने भी शुरू कर दी है। बता दें, पिछले दिनों कोलकाता के हरिदेवपुर से तीन जेएमबी आतंकियों को गिरफ्तार किया था। बताते चलें कि लगभग सात साल पहले बंगाल के बर्द्धमान के खगरागढ़ में हुए विस्फोट के बाद जेएमबी आतंकी शिमुलिया मदरसे से सटे एक घर में बम फैक्ट्री लगाने की फिराक में थे। यह विस्फोट खगरागढ़ में किराये के एक मकान में बम एवं विस्फोटक उपकरण बनाने के दौरान हुआ था। इनमें दो संदिग्ध जेएमबी आतंकवादियों की मौत हो गई थी। दो अक्टूबर 2014 को हुए विस्फोट का संबंध जेएमबी से जुड़ा था।

युवाओं को लालच देकर कराई जा रही है हथियारों की तस्करी

जागरण संवाददाता, मेरठ : एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) और एटीएस की टीमें केएलएफ (खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स) के नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि पश्चिमी यूपी के युवाओं को लालच देकर केएलएफ हथियारों की तस्करी करा रहा है। अब एनआइए की टीम ने केएलएफ से जुड़े प्रत्येक सदस्य की संपत्ति का ब्योरा भी जुटाना शुरू कर दिया है।

दरभंगा विस्फोट : दूसरे दिन भी एनआइए ने दर्ज किए बयान

जागरण संवाददाता, दरभंगा : दरभंगा जंक्शन पर 17 जून को पार्सल में हुए विस्फोट की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम ने दूसरे दिन मंगलवार को भी पूछताछ की। स्टेशन अधीक्षक एके सिंह सहित पैनल रूम के पांच कर्मियों का बयान दर्ज किया गया। सभी से क्या देखा, कैसे घटना हुई, जवाबदेह अधिकारी होने के कारण उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई आदि विषयों पर जानकारी ली गई।

छग में मुठभेड़ में जवान और ग्रामीण घायल

नईदुनिया, बीजापुर : छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर उसूर ब्लाक के गलगम और नड़पल्ली के बीच नक्सलियों और फोर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 196वीं बटालियन का जवान घायल हो गया। वहीं, एक ग्रामीण भी अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर के हमले में घायल हुआ है। फोर्स ने तीन नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। मास्टरमाइंड की कोरोना से मौत की सूचना भी है।

उप्र के शाहजहांपुर में 39 संदिग्ध परिवार, जवाब नहीं दे रही बंगाल सरकार

अंबुज मिश्र, शाहजहांपुर : लखनऊ में अलकायदा के आतंकी पकड़े जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, लेकिन शाहजहांपुर की पुलिस परेशान है। इसका कारण हैं 39 संदिग्ध परिवार, जिनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए बंगाल सरकार को 12 रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन जवाब नदारद है। दरअसल जिन परिवारों को पुलिस संदिग्ध मान रही है। वह स्वयं को बंगाल का निवासी बता रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। ऐसे में इनके बांग्लादेश से आए होने की आशंका में पुलिस को इनकी हर गतिविधि पर नजर रखनी पड़ रही है। शाहजहांपुर के तेल टंकी रोड सहित विभिन्न स्थानों पर झुग्गी-झोपड़ियों में परिवार रहते हैं। इनमें से अधिकांश कूड़ा करकट बीनने का काम करते हैं। ये लोग स्वयं को बंगाल के मालदा जिले व उसके आसपास के क्षेत्र का रहने वाला बताते हैं, लेकिन कई के पास संबंधित दस्तावेज नहीं हैं। हालांकि जिले में किसी आपराधिक घटना में इनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस इनका सत्यापन कराना चाहती है।

न्यूज गैलरी

मुफ्त वितरण के लिए राज्यों ने 15.3 लाख टन अनाज उठाया

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त वितरण के लिए राज्यों ने अभी तक 15.30 लाख टन अनाज उठाया है। इस योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज का अतिरिक्त कोटा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाना है। अतिरिक्त अनाज नवंबर तक मुहैया कराया जाएगा। (प्रेट्र)

और मजबूत हुआ पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमानों का बेड़ा

नई दिल्ली : भारतीय नौसेना ने अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान पी-8आइ प्राप्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2009 में आठ पी-8आइ विमानों के लिए समझौता किया था। बाद में वर्ष 2016 में इस प्रकार के चार और विमानों के लिए समझौता हुआ। एक बयान के अनुसार, 'यह वर्ष 2016 में चार अतिरिक्त विमानों के लिए हुए समझौते का दूसरा विमान है। (प्रेट्र)

टैक्स तुरंत और समय पर दें, सिर्फ रील हीरो न बनें

चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने अल्ट्रा-लग्जरी रोल्स रायस घोस्ट कार के आयात पर प्रवेश कर के भुगतान से बचने की कोशिश करने पर तमिल फिल्म अभिनेता विजय को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने अभिनेता पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए दो हफ्ते के भीतर कर के साथ ही जुर्माने की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता से तुरंत और समय पर कर भुगतान करने की उम्मीद की जाती है। सिर्फ रील हीरो नहीं बने रहना चाहिए। (प्रेट्र)

एसयूवी के बोनट पर बैठ शादी करने गई दूल्हन, मामला दर्ज

पुणे : महाराष्ट्र में 23 वर्षीया एक दुल्हन मंगलवार को शादी करने के लिए विवाह स्थल तक एसयूवी (कार) के बोनट पर बैठ कर पहुंची। इसको लेकर दुल्हन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। दुल्हन के एसयूवी बोनट पर बैठकर शादी करने के लिए पहुंचने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो गया है। (प्रेट्र)

जमानत आदेश जेल अधीक्षकों को ईमेल से भेजा जाए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी व्यक्ति कई दिन तक रिहा नहीं हो पाता क्योंकि कोर्ट के आदेश के जेल पहुंचने में देरी होती है। ऐसा ही आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 कैदियों के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के वक्त नाबालिग होने के आधार पर उन्हें तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था लेकिन उनकी रिहाई में करीब चार दिन का वक्त लग गया। सोमवार की देर शाम कैदियों की रिहाई हो पाई। कैदियों के वकील ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया और जमानत आदेश पहुंचने की प्रक्रिया में देरी की बात करते हुए सुझाव दिया कि कोर्ट का आदेश स्कैन कर ईमेल के जरिए संबंधित जेल अधीक्षक को भेजा जाना चाहिए ताकि जमानत मिलने के बाद रिहाई में बेवजह की देरी न हो। कोर्ट ने सुझाव पर विचार करने और प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी करने की बात कही। आठ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी 13 कैदियों के नाबालिग होने के आदेश को देखते हुए सभी को जमानत दी थी।

कांगड़ा में मलबे से निकाले गए चार और शव

जागरण संवाददाता, कांगड़ा

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में आई तेज बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं, मंगलवार को हिमाचल के कांगड़ा में मलबे को हटाकर चार और शव बरामद किए गए। मृतकों में भाई-बहन भी शामिल हैं। हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पांच अभी मलबे में ही दबे हैं।

राहत और बचाव टीमों ने मंगलवार सुबह ही रेस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन 10 बजे बारिश शुरू होने से करीब दो घंटे तक बचाव कार्य बंद करना पड़ा। बता दें कि मस्तो देवी का शव सोमवार सायं ही निकाल लिया था, जबकि उनके पति भीमो राम अभी तक मलबे में ही है।

दोपहर बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले रुलेहड़ का हवाई दौरा किया और बाद में खुद ही घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री प्रभावित परिवारों से भी मिले। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए।

इधर, दिल्ली में भी बारिश से लगा लंबा जाम



नई दिल्ली में मंगलवार की सुबह झमाझम मानसूनी बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली और लोगों के चेहरे खिल गए, वहीं कई स्थानों पर भारी जलभराव से जाम लग गया। विपिन शर्मा

जयराम ठाकुर ने कहा, प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी व उनका पुनर्वास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के स्वजन को चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी सरकार मकान बनाने के लिए हरसंभव सहयोग देगी।

यह था मामला

सोमवार सुबह जिला कांगड़ा में मूसलधार बारिश से रुलेहड़ गांव में भूस्खलन हुआ था और इसकी चपेट में आने से छह मकान दब गए थे और 15 लोग लापता हो गए थे। अभी तक पांच लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। पांच लोगों की मलबे में दबने के मौत हो गई, जबकि शेष अभी मलबे में ही हैं।

द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर गिरी आकाशीय बिजली

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर मंगलवार दोपहर तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी, जिससे मंदिर का ध्वज दंड व ध्वजा क्षतिग्रस्त हो गई। भगवान द्वारकाधीश के जगत मंदिर पर दोपहर करीब दो बजे आसमान से बिजली गिरी, जिससे मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वजा व ध्वज दंड क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर प्रबंधकों का कहना है कि द्वारका नगरी पर आई आफत को भगवान द्वारकाधीश ने अपने ध्वज पर झेलकर लोगों को बचा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधकों एवं जिला प्रशासन से इस घटना की जानकारी प्राप्त की। शाम को जैसे ही इस घटना का पता चला उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क किया। ध्वज दंड के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी फिर से स्थापना के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। जल्द ही उचित प्रक्रिया की जाएगी।

मूसलधार बारिश से उत्तराखंड में बढ़ीं दुश्वारियां

जासं, देहरादून : उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन भी मूसलधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। पहाड़ों में बारिश के कारण दुश्वारियां बढ़ गई हैं। वहीं, मैदानों में जलभराव और सड़कें धंसने से दिक्कत हो गई है। प्रदेशभर में करीब 300 सड़कों पर यातायात बाधित है। सीमांत इलाकों में भूस्खलन के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जबकि, दुर्गम क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी और मसूरी में सर्वाधिक 100 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बुधवार को नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में गरज के साथ तीव्र बौछार पड़ सकती हैं। जबकि, अन्य जिलों में आंशिक बादल छाये रहेंगे।

ग्लेशियर की बर्फ खिसकने से सौ से अधिक भेड़-बकरियों की मौत : उच्च हिमालय में हिमपात के दौरान ग्लेशियर की बर्फ खिसकने से सौ से अधिक भेड़-बकरियां दबकर मर गईं। चरवाहों के टेंट, राशन व अन्य सामान भी बर्फ में दब गया।

पुष्पक एक्सप्रेस को पटरी से उतरने से बचाया, यात्री सुरक्षित

नईदुनिया, भोपाल

लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस को भोपाल के तीन रेलकर्मियों की सजगता ने मंगलवार को पटरी से उतरने से बचा लिया है। ट्रेन में बैठे करीब 1400 रेल यात्री सुरक्षित मुंबई भी पहुंच गए हैं। दरअसल, ट्रेन के एक कोच की ट्रॉली में बड़ा क्रैक आ गया था। अगर इसे भोपाल में नहीं पकड़ा जाता तो तेज गति में कोच दो हिस्सों बंट जा सकता था और ट्रेन पटरी से उतर जाती।

दरअसल, पुष्पक एक्सप्रेस के कोच एस-5 की ट्रॉली का मुख्य हिस्सा क्रैक हो गया था। ट्रॉली पर ही कोच टिका होता है। ट्रॉली दो हिस्सों में बंटती तो स्वाभाविक है कि ट्रेन पटरी से उतरती और बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन उसके पहले भोपाल स्टेशन पर तैनात रेलकर्मी मिलिंद विधुवा, यशवंत राव और महेश मालवीय ने क्रैक को देख लिया। रेलवे को कोच बदलना पड़ा। इस आपरेशन में दो घंटे से ज्यादा लग गए। ट्रेन सुबह 5.50 बजे भोपाल पहुंची थी, जिसे सुबह आठ बजे मुंबई के लिए रवाना किया गया, जो ढाई घंटे की देरी से मुंबई पहुंची।

गलती को पकड़ना गर्व की बात: सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कैरिज एंड वैगन) मिलिंद विधुवा, टेक्नीशियन यशवंत राव और महेश मालवीय ने बताया कि वे रात्रिकालीन शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे। रोलिंग इन पाइंट (स्टेशन परिसर का वह क्षेत्र, जहां से प्लेटफार्म की शुरुआत होती है) पर बैठे थे। आंखें गड़ाकर एक-एक ट्रेन को देख रहे थे। इतने में बीना की तरफ से पुष्पक एक्सप्रेस आई। देखा कि एस-5 कोच में कुछ गड़बड़ है।

> रेलकर्मियों ने जो सतर्कता दिखाई है, वह भोपाल रेल मंडल के लिए गर्व का विषय है। रेलकर्मी इस तरह से सतर्कता दिखाकर दुर्घटनारहित रेल परिचालन में जुटे हैं। – उदय बोरवणकर, डीआरएम, भोपाल रेल मंडल

सिख युवक का मतांतरण कराने की कोशिश

वैभव शर्मा, चंडीगढ़

पंजाब के चंडीगढ़ में एक सिख युवक का मतांतरण कराने की कोशिश का मामला जिला अदालत पहुंच गया है। युवक ने आरोप लगाया है कि पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग मतांतरण कराने के लिए उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। मनीमाजरा निवासी युवक ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने साल 2008 में मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। उसका आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी।

याचिकाकर्ता के वकील दीक्षित अरोड़ा ने बताया कि याचिका में सिख युवक की तरफ से कहा गया है कि वह मूल रूप से अमृतसर का रहने वाला है। उसने 17 नवंबर 2008 को मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम विवाद किया। विवाह से पहले दोनों एक साथ नौकरी करते थे। दोनों ने अमृतसर के गुरुद्वारा साहिब में शादी की थी। उनका एक बेटा भी है। याचिका के जरिये गुहार लगाई गई है कि अदालत ससुराल पक्ष को आदेश दे कि याची को जबरन मतांतरण के लिए मजबूर न किया जाए।

याची का आरोप-बेटे का भी मतांतरण कराना चाहता है ससुराल पक्ष : याचिका में सिख युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष उनके बेटे का भी मतांतरण कराना चाहता है। ससुरालियों की तरफ से इसकी कोशिश भी की जा रही है। ससुराल वालों ने उसके बेटे को भी जबरन अपने पास रखा हुआ है और बेटे को उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में उसकी पत्नी भी ससुराल पक्ष का साथ दे रही है।

लोन लेने से इन्कार करने पर की गई पिटाई : याची ने कहा है कि मतांतरण से बचने के लिए वह पत्नी से अलग रह रहा है। वह लंबे समय से पत्नी से अलग रहता है। उसने चार वर्ष (2008 से 2011) तक दिल्ली में बिताए और फिर साल 2011 से 2015 तक वह अमृतसर में रहा। इस दौरान याचिकाकर्ता पत्नी और ससुराल पक्ष के संपर्क में आने से बचता रहा। मगर बाद में पत्नी के बार-बार कहने पर वह 2016 में चंडीगढ़ लौटा।

पत्नी और ससुराल के लोग उसका मतांतरण कराने पर अब भी अड़े हुए हैं। आरोप है कि 30 मई 2021 को ससुराल पक्ष से उसका विवाद भी हुआ। इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई, क्योंकि याची ने पत्नी के बिजनेस के लिए लोन लेने से इन्कार कर दिया था।

लालच देकर कराया था मतांतरण, अब सनातन धर्म में की वापसी

जागरण संवाददाता, साहिबगंज

झारखंड के साहिबगंज में 14 पहाड़िया आदिवासियों ने मंगलवार को ईसाई से सनातन धर्म में वापसी की। मंडरो प्रखंड स्थित मारीकुट्टी व गुट्टीबेड़ा गांव के इन लोगों ने कुछ साल पहले मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा के प्रलोभन में ईसाई धर्म अपना लिया था और चर्च जाना शुरू कर दिया था। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद यादव की पहल पर सारे लोग सनातन धर्म में वापस आने को तैयार हुए। सनातन धर्म में वापसी से पूर्व मंगलवार को गंगा नदी के तट पर अवस्थित मुक्तेश्वर धाम मंदिर में अनुष्ठान कराया गया। सभी ने गंगा में स्नान कर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव और मां गंगा को साक्षी मानकर सभी ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया और हर-हर गंगे के जयकारे लगाए। वापसी करने वालों ने स्पष्ट कहा कि मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का प्रलोभन देकर लोगों का मत परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पहाड़िया आदिवासी बूढ़ा महादेव (शिव) के पुजारी हैं और गंगा हमारी मां हैं। हम प्रकृति पूजक हैं। बजरंगी प्रसाद यादव ने बताया कि यहां पहाड़िया आदिवासियों का मतांतरण कराया गया है।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हिदायत

असंतोष दबाने में न हो एंटी टेरर ला जैसे कानूनों का दुरुपयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में मौलिक अधिकारों की रक्षा में शीर्ष अदालत की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है कि नागरिकों के असंतोष को कुचलने या उनका उत्पीड़न करने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून सहित अन्य आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना शीर्ष अदालत का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट को सतर्क अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका आगे बढ़ाने के साथ संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियां अलग तरह की हैं। महामारी से लेकर असहिष्णुता बढ़ने जैसे मुद्दों से निपटना है। कोर्ट जब ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उसे 'न्यायिक सक्रियता' या 'न्यायिक अतिरेक' कहा जाता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ सोमवार को अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा सोसाइटी आफ इंडियन ला फर्म्स और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ आर्बिट्रेटर्स के साथ आयोजित एक सम्मेलन में चुनौतीपूर्ण समय में मौलिक अधिकारों की रक्षा में शीर्ष अदालत की भूमिका पर बोल रहे थे।

उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जेलों में भीड़ घटाने पर शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लेख किया और कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जेलों में भीड़भाड़ कम हो क्योंकि वे वायरस के लिए हाटस्पॉट बनने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। लेकिन यह जांचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे क्यों हैं।

अर्नब गोस्वामी मामले में अपने फैसले का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा आतंकवाद विरोधी कानून सहित आपराधिक कानून का दुरुपयोग असंतोष को दबाने या नागरिकों के उत्पीड़न के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में उल्लेख किया है हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना बहुत ज्यादती है। हमें हमेशा अपने फैसलों के गहरे प्रणालीगत निहितार्थों के प्रति सचेत रहना चाहिए उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय शीर्ष अदालत की भूमिका और भारत की आबादी के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले पहलुओं में इसकी भागीदारी को कम करके नहीं आंका जा सकता है।

एलगार परिषद मामले में अमेरिकी कंपनी को राय देने का अधिकार नहीं

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाई कोर्ट से कहा है कि एलगार परिषद नक्सली संबंध मामले में कुछ आरोपितों के इलेक्ट्रानिक उपकरणों में सुबूत डालने का दावा करने वाली अमेरिकी डिजिटल फोरेंसिक कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग को अदालत के आदेश के बिना अपनी राय देने का अधिकार नहीं है।

राज्य सरकार ने एक जुलाई को अदालत में दाखिल एक हलफनामे में यह दलील दी। इस हलफनामे को मंगलवार को रिकार्ड में लिया गया। यह हलफनामा मामले में एक आरोपित रोना विल्सन की रिट याचिका के विरोध में सौंपा गया है। आरोपित ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र रद करने का आग्रह किया है।

इस साल के शुरू में जारी आर्सेनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, विल्सन के कंप्यूटर में अपराध का संकेत देने वाला पत्र 'डाला' गया था। राज्य सरकार ने कहा है कि विल्सन को पुलिस ने निशाना नहीं बनाया है। विल्सन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि किसी ने उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया और अपराध संकेती सामग्री डाल दी।

सौरव गांगुली पर बनेगी बायोपिक, रणबीर कपूर कर सकते हैं भूमिका

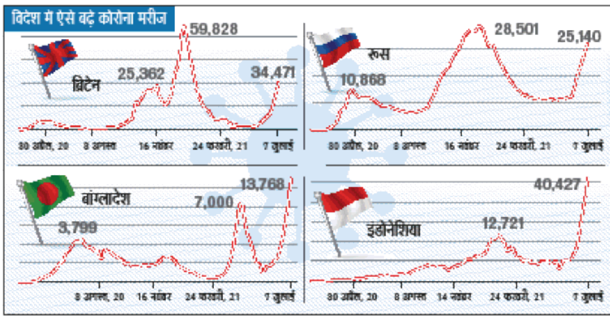
राज्य ब्यूरो, कोलकाता

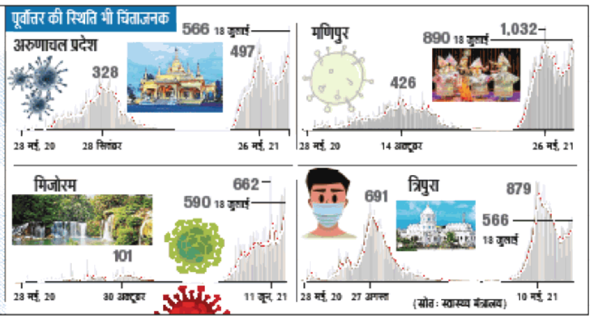
सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरूद्दीन और महेंद्र सिंह धौनी के बाद अब सौरव गांगुली पर बायोपिक बनने जा रही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के अध्यक्ष सौरव के किरदार में बालीवुड के मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं। सौरव ने अपने करीबियों को बायोपिक के बारे में जानकारी दी है। 200 से 250 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस फिल्म में सौरव के लार्ड्स टेस्ट में शतकीय पदार्पण से लेकर बीसीसीआइ अध्यक्ष बनने तक के सफर को रुपहले परदे पर दर्शाया जाएगा।

सौरव के किरदार के लिए पहले अभिनेता ऋतिक रोशन के नाम पर काफी चर्चा हुई थी लेकिन रणबीर कपूर सौरव की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। दो और अभिनेताओं पर भी विचार किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक के नाम अभी सामने नहीं आया है।

गांगुली ने दो कंपनियों के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में किया मुकदमा

सौरव गांगुली ने 35 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर दो कंपनियों के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में मुकदमा किया है। ये दोनों अतीत में सौरव की मैनेजमेंट कंपनियां रही हैं। 2018 में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड और परसेप्ट डी मार्क (इंडिया) लिमिटेड नामक इन कंपनियों को सौरव को क्षतिपूर्ति के तौर पर रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।





अमरोहा में ट्रायल के दौरान आक्सीजन प्लांट का एयर कंटेनर फटा

जासं, अमरोहा: जिला अस्पताल में ट्रायल के दौरान आक्सीजन प्लांट का एयर कंटेनर धमाके के साथ फट गया। इससे अफरातफरी मच गई। कुछ दूरी पर खड़ा आपरेटर बाल-बाल बच गया। हादसे की वजह की जांच-पड़ताल की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन को लेकर मारामारी हो गई थी। आक्सीजन प्लांट बनाने के लिए नोएडा की डीएलएस एनवायरमेंट टेक कंपनी को ठेका दिया गया था। कंपनी मई माह से अस्पताल में आक्सीजन प्लांट तैयार कर रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया।

देश की पहली कोरोना मरीज फिर संक्रमित

आफत और राहत ▸ मेडिकल की छात्रा पिछले साल 30 जनवरी को पाई गई थी पाजिटिव, देशभर में मामले घटे

त्रिसूर, प्रेट्र : देश की पहली कोरोना मरीज फिर से संक्रमित पाई गई है। मेडिकल की इस छात्रा को पिछले साल 30 जनवरी को कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया था, तब वह चीन के वुहान शहर से लौटी थी, जहां से पूरे विश्व में यह महामारी फैली है।

केरल के त्रिसूर की जिला चिकित्सा अधिकारी डा. केजे रीना ने बताया कि महिला को दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। उसकी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पाजिटिव आई है, जबकि एंटीजेन टेस्ट निगेटिव है। हालांकि, उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं।

डा. रीना ने बताया कि महिला मरीज फिलहाल घर में क्वारंटाइन है और उसकी स्थिति ठीक है। महिला को पिछले साल 30 जनवरी को चीन के वुहान शहर से लौटने पर कोरोना पाजिटिव पाया गया था। वह वुहान में मेडिकल के तीसरे साल की छात्रा थी और सेमेस्टर परीक्षा के बाद घर लौटी थी। संक्रमित पाए जाने के तुरंत बाद उसे त्रिसूर मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच उसका कई बार टेस्ट किया गया है और लगातार दूसरी बार जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसे 20 फरवरी, 2020 को अस्पताल से छुट्टी मिली थी।


किस काम की तैयारी...बिहार के शेखपुरा जिले में कोरोना मरीजों के लिए आए 40 रिवाल्विंग बेड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे फेंक दिए गए हैं। इनमें खर-पतवार और फूल उग आए हैं। अरुण साथी

मां की मौत, नवजात ने 21 दिन में जीती जंग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

वह जब गर्भ में थी, उसी समय उसकी मां को कोरोना हो गया था। मां की हालत बिगड़ी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। मां के बचने की उम्मीद नहीं थी इसलिए डाक्टरों ने सी-सेक्शन से प्रसव कराया। प्री-मेच्योर बच्ची के दुनिया में आने के कुछ घंटे बाद मां की मौत हो गई। बच्ची की हालत भी गंभीर थी, लेकिन 21 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब बच्ची पूरी तरह से ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब वह अपने पिता, 10 साल के भाई और दादा-दादी के साथ रहेगी। 12 जून को मेडिकल कालेज अस्पताल में 31 वर्षीया राखी मंडल बिश्वास को भर्ती कराया गया था। उन्हें गंभीर कोविड न्यूमोनिटिस था। बनगांव की रहने वाली राखी के गर्भ में 32 सप्ताह का भ्रूण था और आक्सीजन लेवल 60 तक गिर गया था। एमसीएच में स्त्री रोग प्रमुख पार्थ मुखर्जी ने कहा, अगर हम इमरजेंसी सी-सेक्शन नहीं करते तो बच्ची की भी जान चली जाती।

चार महीने बाद सबसे कम केस

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 118 दिन बाद मंगलवार को संक्रमण के सबसे कम 31,443 नए मामले पाए गए हैं। इस दौरान 2,020 लोगों की मौत भी हुई, लेकिन इनमें मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुईं 1,478 मौतें भी शामिल हैं, जिन्हें पहले कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में शामिल नहीं किया गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर देश के अन्य भागों में हालात नियंत्रण में हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मामले बढ़ नहीं रहे हैं तो कम भी नहीं हो रहे हैं। हालांकि, नए मामलों से ज्यादा मरीजों के ठीक होने का सिलसिला बना हुआ है और इसके चलते सक्रिय मामलों सवा चार लाख के करीब आ गए हैं।

देश में कोरोना की स्थिति

भारत	
24 घंटे में नए मामले	31,443
कुल सक्रिय मामले	4,31,315
24 घंटे में टीकाकरण	40 .65 लाख
कुल टीकाकरण	38 .14 करोड़

सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	31,443
कुल मामले	3,09,05,819
मौतें	2,020 (इसमें मध्य प्रदेश में पहले हुईं 1,478 मौतें शामिल)
कुल मौते	4,10,784
कुल सक्रिय मामले	4,31,315
कुल स्वस्थ	3,00,63,720
ठीक होने की दर	97 .28 फीसद
पाजिटिविटी दर	1.81 फीसद
मृत्यु दर	1.32 फीसद
जांचें (सोमवार)	17,40,325
कुल जांचें	43,40,58,138

उप्र में कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी निगेटिव रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कांवड़ यात्रा के साथ ही उप्र की योगी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर भी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें और दिशा-निर्देश जारी करें।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न बिंदुओं के साथ ही 25 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा की। योगी ने निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा से किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के सक्षम अधिकारियों से बात कर ली जाए और समन्वय बनाते हुए यात्रा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। कांवड़ यात्रा के लिए अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू करने पर भी विचार विमर्श करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि संक्रमण के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा भविष्य के आकलन को ध्यान में रखते हुए कांवड़ संघों से अनुरोध कर लें कि कांवड़ यात्रा में कम से कम श्रद्धालु शामिल हों।

उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा की स्थगित

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा असमंजस दूर कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट की पुष्टि होने और संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। आमजन का जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय 30 जून को ले लिया था। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए थे। यात्रा पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से वार्ता भी हुई। इसके बाद प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। इसी बीच उप्र के मुख्यमंत्री योगी ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने की बात कही। कांवड़ यात्रा में कई राज्यों से श्रद्धालु गंगाजल लेने हरिद्वार आते हैं, इसलिए प्रदेश सरकार के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई।

बुखार भी जरूरी है, इसे दबाएं नहीं

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी

वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण के दौरान होने वाला ज्वर (बुखार) रोग उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि बुखार को लेकर फैली भ्रांतियों के कारण लोग इसे दबाने वाली दवाएं ले लेते हैं। विशेष रूप से कोरोना काल में लोगों ने हल्के बुखार में भी दवाओं का जमकर सेवन किया। यह सही नहीं है।

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू स्थित सीईएमएस (प्रायोगिक औषध एवं शल्य अनुसंधान केंद्र) में असिस्टेंट प्रोफेसर डा. समर सिंह का कहना है कि ज्वर रोगाणुओं से लड़ने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। इस संदर्भ में उन्होंने डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को पत्र लिखा है।

दवा लेने के डब्ल्यूएचओ के पैरामीटर को घटाया: डा. समर ने पत्र में चिंता जताई है कि भारत में डाक्टरों और मेडिकल स्टाफ में भी इसे लेकर पर्याप्त जानकारी की कमी है। कोरोना की दूसरी लहर में कुछ स्वास्थ्य एजेंसियों ने बुखार में दवा लेने के डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित 39 डिग्री सेल्सियस (102 डिग्री फारेनहाइट) तापमान के पैरामीटर को घटाकर 37.8-39 डिग्री कर दिया। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने हल्के बुखार में खूब दवाएं खाईं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने भी 2019 में 103 डि. फारेनहाइट के ऊपर होने पर ही ज्वर के उपचार की जरूरत बताई है।

बुखार दबाने पर 200 गुना तक बढ़ जाते हैं वायरस : बुखार में शरीर का तापमान बढ़ जाने से वायरस के हमले से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। शुरू में ही दवा लेकर बुखार को दबा दिया जाए तो तीन दिन में वायरस की संख्या 100 से 200 गुना तक बढ़ जाती है। डा. समर ने कहा कि हमें किसी भी महामारी में रोगाणु जनित बुखार को रोकने की कोशिश नहीं कर उस कारण का निदान करना चाहिए, जिससे बुखार हुआ है।

बच्चों को लेकर भ्रांतियां : क सर्वे के अनुसार न्यूयार्क में 65 फीसद बाल विशेषज्ञों में भ्रांति है कि ज्वर से मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। वहीं, 95 फीसद अभिभावक मानते हैं कि ज्वर से बच्चों के दिमाग के विकास पर असर पड़ता है।

40 करोड़ वर्ष से हमारे साथ है बुखार

डा. समर के अनुसार बुखार 40 करोड़ से भी अधिक वर्षों से हमारे साथ है। यह जानवरों में भी सहायक चिकित्सक की भूमिका निभाता है। खरगोश पर एक अध्ययन में पाया गया कि उनमें ज्वर नहीं आने दिया गया तो 66 फीसद खरगोश रोगाणुजनित रोगों के कारण मर गए। वहीं, नैसर्गिक रूप से बुखार आने दिया गया तो किसी खरगोश की मौत नहीं हुई। यह बताता है कि बुखार हमारे लिए कितना जरूरी है।

संक्रमण बढ़ाने वाले राज्यों से आने वालों पर प्रतिबंध जरूरी : महांति

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : डाइरेक्टरेट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डीएमइटी) सीबीके महांति ने कहा कि राज्य में संक्रमण कम हो रहा है। विगत कुछ दिनों के संक्रमण मामलों की तुलना करें, तो वर्तमान में नए मामले काफी कम आ रहे हैं।

डीएमईटी महांति ने मंगलवार को कहा कि कटक एवं खुर्दा सहित कुछ जिलों में सुधार हुआ है। मगर अभी भी स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ऐसे में कटक, खुर्दा के साथ अधिक संक्रमण वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही संक्रमण बढ़ने वाले राज्यों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध भी जरूरी है। केंद्र सरकार को इस पर जरूरी कदम उठाना चाहिए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्वारंटाइन करने के साथ ही उन नजर रखी जाएगी। पहले भी प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों ने ही संक्रमण को बढ़ाया था। ऐसे में जागरुक रहना होगा।

कोरोना से उबरे मरीजों में हार्मोन असंतुलन का भी खतरा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

कोरोना वायरस शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर प्रभाव छोड़ रहा है। अब स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआइ) चंडीगढ़ की ओर से कराए गए ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है कि गंभीर संक्रमण से उबरे मरीजों के हार्मोन सिस्टम पर भी कोरोना का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे मरीजों के शरीर में हार्मोन असंतुलन जैसी स्थिति सामने आ रही है।

हर पहलू पर किया गया काम: पीजीआइ के एंडोक्रिनोलाजी विभाग की ओर से कराई गई रिसर्च के मुताबिक उन जिन्हें इलाज के दौरान हाई फ्लो में आक्सीजन लगी थी। ज्यादातर वह मरीज हैं जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं। विभाग प्रमुख प्रो. संजय कुमार भडाड़ा ने बताया कि अध्ययन में कोरोना के हार्मोन पर असर को ध्यान में रखते हुए हर पहलू पर काम किया गया।

मरीजों को दो समूहों में बांटा गया: पीजीआइ में दाखिल कोरोना के 84 मरीजों पर यह अध्ययन किया गया। इसमें इन 84 मरीजों को 42-42 के दो अलग समूहों में बांटा गया। पहले 42 मरीज ऐसे थे, जिन्हें लो आक्सीजन सेचुरेशन की जरूरत थी। इन्हें ज्यादा गंभीर बीमारी और डायबिटीज, हायपरटेंशन जैसी बीमारियां भी नहीं थीं। स्टडी में सामने आया कि इस ग्रुप के हार्मोन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे समूह के मरीजों को हाई फ्लो आक्सीजन दी गई और उन्हें डायबिटीज और हायरपरटेंशन जैसी बीमारी भी थी। उनके हार्मोन क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह बात तीन से छह महीने बाद हार्मोन टेस्ट कराने पर सामने आई। इस स्टडी से साफ हुआ है कि कोरोना मरीजों के हार्मोन की तीन से छह महीने बाद जांच करना जरूरी है।

यहां कोरोनारोधी टीका लगवाइए, लंगर छकिए

जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ : लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए कमेटी ने एक अनूठी पहल की है। गुरुद्वारा नाका हिंडोला में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है यानी पहले टीका लगवाइए फिर लंगर छकिए। यहां हर दिन 300 से 400 लोग लंगर छकते हैं।

लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता सतपाल सिंह मीत ने बताया कि 13 जून से गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। सोमवार से शनिवार तक टीकाकरण चलता है। 18 से 44 और 45 के पार के लिए अलग-अलग शिविर लगा है। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक होने वाले टीकाकरण के दौरान दोपहर में चिकित्सकों और आम लोगों के लिए लंगर की सेवा की जाती है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पहले दिन 300 लोगों के लिए वैक्सीन एक सप्ताह में लगाने की अनुमति दी गई। इसे बढ़कर 800 कर दिया गया।

राष्ट्रीय फलक

भोले के दरबार में मिलता है 'आक्सीजन' का प्रसाद

मनकामेश्वर मंदिर

शरद द्विवेदी, प्रयागराज

यूं तो देवस्थलों (मंदिरों) में अनुष्ठान करने पर मिष्ठान-फल का प्रसाद मिलता है, लेकिन संगमनगरी में यमुना तीरे प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों को पर्यावरण संरक्षण की सीख दी जा रही है। मई से यहां रुद्राभिषेक, महाभिषेक करने वाले भक्तों को प्रसाद स्वरूप पौधा दिया जा रहा है। पौधा लेने वाले को संरक्षण का भी संकल्प दिलाया जाता है। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण।

मंदिर प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में आक्सीजन के अभाव में हुई जनहानि को देखते हुए पौधारोपण के प्रति प्रेरित करने की मुहिम शुरू की है। मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज का प्राचीन शिवालय है। मान्यता है कि त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्रीराम ने इस शिवलिंग को स्थापित किया था। मंदिर में श्रावण में तो भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर के प्रभारी ब्रह्मचारी श्रीधरानंद रुद्राभिषेक, महाभिषेक करने वाले भक्त को आशीर्वाद स्वरूप पौधा भेंट करके उसकी रक्षा करने का संकल्प दिलाते हैं।

इसलिए देते हैं पौधा: ब्रह्मचारी श्रीधरानंद बताते हैं कि पौधा लगाने से व्यक्ति का वर्तमान व भविष्य समृद्ध होता है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, लेकिन मौजूदा पीढ़ी इस ज्ञान से अनभिज्ञ है। इसी कारण कोरोना जैसी महामारी में लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं। वह कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की बात तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन पौधा कोई नहीं लगाना चाहता।

'मंदिर में रुद्राभिषेक कराने के बाद ब्रह्मचारी श्रीधरानंद महाराज ने पीपल का पौधा दिया। कहा कि इसकी देखरेख घर के सदस्य की तरह करना, सुख-समृद्धि आएगी। मैं वैसा ही कर रहा हूं।'

-विजय शास्त्री दारागंज

'मुझे मनकामेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक करने के बाद आशीर्वाद स्वरूप पौधा मिला है। यह मेरे लिए भोलेनाथ का अमूल्य प्रसाद है, इसकी रक्षा मैं आजीवन सपरिवार करूंगा।'

-रमेश मिश्र, अधिवक्ता

प्रसाद में आक्सीजन की प्रचुरता वाले पौधे

मनकामेश्वर मंदिर में अधिक आक्सीजन देने वाले पौधे जैसे पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, गूलर, जामुन का वितरण ज्यादातर होता है। नवग्रह, तुलसी, रुद्राक्ष, बेल, शमी, आम आदि का पौधा भी उपलब्धता के अनुरूप दिया जाता है। यह पौधे वन विभाग सुलभ कराता है।

एएसआइ ने शुरू की जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह की जांच

जासं, पुरी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की तकनीकी कमेटी ने मंगलवार से पुरी जगन्नाथ मंदिर के गर्भ गृह की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। जगमोहन में मंदिर के ऊपरी हिस्से तक जाकर मुआयना करने की व्यवस्था की जा रही है। विशेष टीम जगमोहन के तमाम हिस्सों की बारीकी से जांच करेगी। यदि कहीं

कोई दरार आदि दिखती है, तो उसकी तुरंत मरम्मत की जाएगी। जगन्नाथ मंदिर की तकनीकी कोर कमेटी व सेवकों को लेकर बनाई गई टीम द्वारा यह जांच की जाएगी। इधर, मंदिर प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद भोगमंडप, जगमोहन एवं नाट्यमंडप की लेजर से स्कैनिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंदिर के मुख्य प्रशासक किशन कुमार ने जानकारी दी कि लेजर स्कैनिंग के लिए सेवकों को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। एक दिन पहले ही रथ खींचने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद देर रात को नीलाद्री भक्त निवास से तीन द्वार के लिए छह स्टील फ्रेम तथा चांदी को जगन्नाथ मंदिर में लाया गया है। सभी दरवाजों का निर्माण हो गया है।

चोकसी को इलाज के लिए एंटीगुआ जाने को मिली है जमानत

नई दिल्ली, एएनआइ : भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि वह इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबूडा जाएगा और डाक्टरों द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद वापस लौट आएगा। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अग्रवाल ने कहा कि डोमिनिका में बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं होने के चलते चोकसी को इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबूडा जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा, 'चोकसी को त्रिनिदाद भेजने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन हमने अपनी पसंद के डाक्टर से दिखाने की दलील रखी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।' चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में आरोपित है। फिलहाल वह एंटीगुआ और बारबूडा का नागरिक है। अग्रवाल ने कहा कि डाक्टर उसे स्वस्थ बताएं तब वह वापस लौटेगा। तब तक डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में सुनवाई नहीं होगी। बता दें कि डोमिनिका हाई कोर्ट ने सिर्फ इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबूडा जाने की अनुमति दी है।

मेडिकल कालेज में न्यूड रैगिंग की शिकायत, जांच में जुटा प्रबंधन

जासं, अमृतसर: पंजाब के सरकारी मेडिकल कालेज अमृतसर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों की न्यूड रैगिंग की शिकायत नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के पास पहुंचने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नेशनल एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से इस मामले की जांच के आदेश मिलने पर मेडिकल कालेज के प्रोफेसरों की टीम दो दिन से जांच में जुटी हुई है। फिलहाल कालेज प्रबंधन इसे झूठी शिकायत ही मान रहा है, लेकिन अगले दो दिन तक जांच का काम जारी रखने की बात भी कही गई है। इसके बाद रिपोर्ट नेशनल एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपी जाएगी।

दरअसल, रविवार को मेडिकल कालेज में रैगिंग को लेकर एक गुमनाम शिकायत नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 18001805522 पर की गई थी। अज्ञात शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे कि कालेज में जूनियर छात्रों को नंगा कर रैगिंग की जा रही है। इस शिकायत पर कालेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने सोमवार और मंगलवार को फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों से पूछताछ की। किसी भी छात्र ने रैगिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। मंगलवार को फार्माकालोजी विभाग के प्रोफेसर डा. जगदेव सिंह कुलार और डा. जसप्रीत सिंह ने प्रिंसिपल डा. राजीव देवगण को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। डा. जगदेव सिंह के अनुसार, रैगिंग की घटना कालेज में नहीं हुई है। किसी ने गलत शिकायत की है।

वैक्सीन के बहाने अविवाहित की नसबंदी, अब पीड़ित ही कठघरे में

जागरण संवाददाता, एटा

कोरोना वैक्सीन के बहाने अविवाहित मूकबधिर की नसबंदी करने का मामला दो दिन बाद भी बेपर्दा नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग दोषियों का बचाव करते हुए पीड़ित को ही कठघरे में खड़ा कर रहा है। पुलिस भी जांच की गेंद स्वास्थ्य विभाग के पाले में डाल खामोश है, जिसके चलते अभी तक पीड़ित की एफआइआर भी दर्ज नहीं हुई है।

उप्र के एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव विशनपुर निवासी ध्रुव कुमार की नसबंदी 11 जुलाई को जिला चिकित्सालय में हुई थी। हालत बिगड़ने पर स्वजन ध्रुव को एसएन मेडिकल कालेज आगरा ले गए, जहां स्वस्थ होने पर उसे शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़ित के भाई अशोक कुमार ने वैक्सीन लगवाने के बहाने ले जाकर नसबंदी कराने का आरोप लगाते हुए आशा कार्यकर्ता नीलम के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। पीड़ित के भाई का कहना था कि आशा ने टीका लगवाने के 3500 रुपये मिलने की बात कह बहला-फुसलाकर ले जाकर नसबंदी करा दी, जबकि उनका भाई अविवाहित है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर स्वास्थ्य विभाग को सौंप जांच कर रिपोर्ट मांगी है। इस पर एसीएमओ डा. सुधीर कुमार ने गांव पहुंचकर मामले का फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल आने पर खुद पीड़ित ने नसबंदी के लिए फार्म पर हस्ताक्षर किए। डाक्टरों को इशारे से तीन बच्चे होने का संकेत दिया। पूरी प्रक्रिया में भी पीड़ित का कहीं विरोध नहीं दिखा। हालांकि अभी जांच जारी है। सवाल यह है कि आशा कार्यकर्ता को पता था कि ध्रुव अविवाहित है। प्रधान को भी पूरी जानकारी थी, फिर उसने आशा कार्यकर्ता को कैसे पत्र लिखकर दे दिया कि ध्रुव तीन बच्चों का पिता है।

15 दिन पहले आशा से किया संपर्क: आशा कार्यकर्ता नीलम का कहना है कि 15 दिन पहले पीड़ित के स्वजन ने संपर्क कर बताया था कि ध्रुव कुमार के तीन बच्चे हैं और वह उसकी नसबंदी कराना चाहते हैं। स्वजन के संज्ञान में ही वह लेकर गई और घर भी पहुंचाया।

शासनादेश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही एफआइआर दर्ज की जा सकती है। इसलिए पीड़ित के भाई द्वारा अवागढ़ थाने को दी गई तहरीर स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है।

-ओपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एटा

मामले की जांच चल रही है हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन परिवार की भी भूमिका सही नहीं लग रही। नसबंदी से आशा को कोई लाभ नहीं था। इस तरह जांच में अन्य कई पहलू भी शामिल किए जा रहे हैं।

- डा. सुधीर कुमार, एसीएमओ, परिवार नियोजन

रिश्तों में खटास के बावजूद भारत-चीन व्यापार बढ़ा

बीजिंग : सीमा पर तनाव के चलते द्विपक्षीय रिश्तों में खटास के बावजूद भारत-चीन के आपसी कारोबार में तेज उछाल आया है। चीन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही (जनवरी-जून, 2021) में द्विपक्षीय कारोबार पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 62.7 फीसद बढ़कर 57.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हाल के वर्षों का यह सर्वाधिक छमाही आंकड़ा है। (प्रेट्र)

कंपनी निवेश या रोजगार हरियाणा से गुजरात स्थानांतरित नहीं कर रही है। हरियाणा और गुजरात स्थित संयंत्रों का सामंजस्य बेहतर किया जा रहा है।

- आरसी भार्गव, चेयरमैन, मारुति सुजुकी



सूचकांक	मूल्य	बदलाव
सेंसेक्स	52,769.73	▲ 397.04
निफ्टी	15,812.35	▲ 119.75
सोना प्रति दस ग्राम	₹46,856	▲ ₹90
चांदी प्रति किलोग्राम	₹67,988	▲ ₹490
डॉलर	₹74.49	▼ ₹0.09
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 75.58	

पुष्प मसाले ने पेश किया क्विक फ्राई



नई दिल्ली, (वि): पुष्प मसाले ने 17 मसालों के मिश्रण से क्विक फ्राई के नाम से मसालों की नई रेंज पेश की है। इसके तहत कंपनी दाल तड़का, सब्जी मसाला, शाही सब्जी मसाला, दाल तड़का मसाला एवं सोया चंक्स मसाला लेकर आई है। कंपनी का कहना है नाम के अनुरूप सिर्फ एक मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर जल्द तैयार हो जाने वाले इनमें से किसी भी डिश का आनंद लिया जा सकता है। वहीं, क्विक फ्राई शाही सब्जी मसाला का उपयोग राजमा, दाल मखनी, आलू, छोले, परांठा, भजिये या कचौरी किसी में भी किया जा सकता है। पुष्प मसाले के डायरेक्टर सुरेंद्र सुराणा ने कहा कि जिस भोजन के लिए जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है, उसमें भरपूर आनंद मिलना बेहद जरूरी है। क्विक फ्राई के उपयोग के बाद सब्जी में और मसाला डालने की जरूरत नहीं है। इन्हें सात ग्राम, 50 ग्राम, 100 व 200 ग्राम के पैक में पेश किया गया है।

पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी चोरी के आए 8,000 मामले, डीजीजीए ने पकड़ी

35,000 करोड़ की जीएसटी चोरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जीएसटी चोरी को लेकर सरकार की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते गत वित्त वर्ष (2020-21) में 35,000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 8,000 मामलों का भंडाफोड़ किया गया। सीजीएसटी जोन और जीएसटी इंटेलीजेंस डायरेक्टरेट के प्रयासों से इस चोरी को पकड़ने में कामयाबी मिली। जीएसटी की चोरी मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) प्रविधान के दुरुपयोग के तहत की जा रही थी। इस सख्ती की वजह से जीएसटी के संग्रह में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर इस वर्ष मई तक जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार रहा।

सीजीएसटी जोन और जीएसटी इंटेलीजेंस डायरेक्टरेट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी चोरी में सीए, वकील जैसे 14 पेशेवर सहित 426 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आइटीसी का फायदा लेने में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए नौ नवंबर, 2020 को फर्जी जीएसटी इनवॉयस के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया था जो अब तक जारी है।



इनपुट टैक्स क्रेडिट का हुआ सबसे ज्यादा दुरुपयोग ● फाइल फोटो

हालांकि, बीते दो-तीन महीनों के दौरान कोविड महामारी की वजह से यह अभियान सुस्त पड़ गया था। लेकिन धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने से राष्ट्रीय स्तर पर फिर से अभियान शुरू कर दिया है। इस महीने के दौरान सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले धोखेबाजों के खिलाफ जीएसटी इंटेलीजेंस डायरेक्टरेट और सभी केंद्रीय जीएसटी दलों की कार्रवाई तेज हो गई हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 500 से ज्यादा फर्जी मामलों का पता लगा है और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) अधिकारी धोखेबाजों को पकड़ने के लिए आधुनिक आईटी टूल, डिजिटल साक्ष्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अन्य सरकारी विभागों से सूचना भी जुटा रहे हैं। अभियान के दौरान कुछ जानी-मानी कंपनियों के खिलाफ फर्जी आइटीसी का लाभ लेने के मामले भी दर्ज किए गए। सरकारी खजाने को फर्जी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तलाश और उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द ही तेज होने की संभावना है।

हाल के कुछ प्रमुख मामलों में नागपुर जोन इकाई द्वारा तीन कंपनियों के खिलाफ दर्ज मामला शामिल है, जिसमें गलत तरीके से 214 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) पास करने और धोखाधड़ी से आईटीसी के रिफंड का दावा किया गया था। इन कंपनियों ने फर्जी किरायेनामा करार और फर्जी बिजली के बिल जमा किए थे, जबकि पंजीकृत व्यावसायिक पते सिर्फ कागजों पर मौजूद थे। ये कंपनियां पाइप और सिगरेट के लिए स्मोकिंग मिक्सचर जैसे एक सामान्य उत्पाद का निर्यात दिखा रही थीं जिन पर 28 फीसद जीएसटी लगता है।

एक अन्य मामले में चंडीगढ़ जोनल इकाई ने 115 करोड़ रुपये के अवैध आइटीसी को पास कराने के लिए फर्जी कंपनियों का संचालन करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। डीजीजीआइ सूरत जोन इकाई ने अवैध आइटीसी का एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें ऐसी कंपनियां इनवॉयस की आपूर्ति और 300 करोड़ रुपये का अवैध आईटीसी पास करने से जुड़ी थीं जिनका अस्तित्व ही नहीं था।

सीजीएसटी जयपुर जोन ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के फर्जी आइटीसी का लाभ लेने में शामिल कई फर्जी कंपनियों के शामिल होने के मामले का पता लगाया, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीजीएसटी दिल्ली जोन ने 551 करोड़ रुपये की फर्जी इनवॉयस तैयार करने और 91 करोड़ रुपये का अवैध आइटीसी पास करने में शामिल 23 इकाइयों के एक नेटवर्क का राजफाश किया था।

कच्छ में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएगी एनटीपीसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अगले 10 वर्षों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी गुजरात के कच्छ में 4,750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करेगी। कंपनी ने कहा है कि उसकी सहायक शाखा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी आरइएल) को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की इजाजत दे दी है।

हाल ही में निजी सेक्टर की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की थी। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में गुजरात गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े राज्य के तौर पर स्थापित होगा। इन दोनों कंपनियों के अलावा अदाणी ग्रुप भी गुजरात में तेजी से अपनी सोलर प्लांट क्षमता में विस्तार करने में जुटा है। रिलायंस की तरह एनटीपीसी ने भी कहा है कि स्थापित होने वाले सोलर प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर भी जोर देगी।


2032 तक गैर-पारंपरिक स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य ● फाइल

एनटीपीसी पिछले पांच वर्षों से छोटे-छोटे सोलर प्लांट लगा रही है। अभी सौर ऊर्जा व दूसरे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने की इसकी क्षमता 6,600 मेगावाट है। इसे वर्ष 2032 तक 60,000 मेगावाट पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका बड़ा हिस्सा गुजरात में होगा। कंपनी की 1,800 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि इसके लिए पूंजी का इंतजाम कैसे होगा। मोटे तौर पर प्रति मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने पर चार करोड़ की लागत आती है, इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को 2.40-2.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।

अदाणी ने मुंबई एयरपोर्ट के प्रबंधन का जिम्मा संभाला

जेएनएन, नई दिल्ली : अदाणी ग्रुप की सहायक शाखा अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआइएएल) का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है। एमआइएएल मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करती है। अब तक यह एयरपोर्ट जीवीके ग्रुप के पास था। अदाणी ने पिछले वर्ष अगस्त में मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके ग्रुप की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की थी। अदाणी ग्रुप ने जीवीके ग्रुप से एयरपोर्ट की 50.5 फीसद और एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका (एसीएसए) तथा बिडवेस्ट ग्रुप जैसे अन्य छोटे शेयरधारकों से 23.5% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके बाद इस एयरपोर्ट में ग्रुप की हिस्सेदारी 74 फीसद हो गई।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने ट्वीट में कहा, विश्वस्तरीय मुंबई एयरपोर्ट को भविष्य में कारोबार, मौज-मस्ती और मनोरंजन का बेहतरीन केंद्र बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट पर मुंबई गौरवान्वित महसूस करेगी और स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार सृजित होंगे।

भीम यूपीआइ से भूटान में भी कर सकेंगे भुगतान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत की भीम यूपीआइ भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला भूटान पहला देश बन गया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्योंगपो नेमगे शेरिंग ने भीम यूपीआइ को लांच किया। भारत इंटरफेस फार मनी (भीम) डिजिटल एप है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) के माध्यम से काम करता है। यूपीआइ भारत का रियल टाइम में तत्काल भुगतान करने वाला सिस्टम है, जो सैकड़ों बैंकों से जुड़ा है। भूटान में भारत के रुपे कार्ड का चलन पहले से है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, भूटान में भीम यूपीआइ शुरू होने से वहां जाने वाले भारतीय यात्रियों को भुगतान करने में काफी सहूलियत होगी। हर साल लगभग दो लाख पर्यटक भूटान जाते हैं। इससे दोनों देशों के बीच कारोबारी सुगमता भी बढ़ेगी। लांच करने के दौरान सीतारमण ने भूटान के स्टोर से भीम यूपीआइ के जरिये भुगतान कर खरीदारी भी की। भीम यूपीआइ के भूटान में चलन आरंभ करने के लिए भारत के नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने भूटान के सेंट्रल बैंक रॉयल मोनेट्री अथारिटी के साथ करार किया है। यूपीआइ से इस साल जून में 280.75 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेमगे शेरिंग के साथ किया लांच, भूटान में रुपे कार्ड का चलन पहले से है

एसएंडपी ने लगातार 14वें वर्ष नहीं सुधारी भारत की रेटिंग

नई दिल्ली, प्रेट्र : अग्रणी रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में लगातार 14वें वर्ष कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनी ने भारत को निवेश के लिहाज से सबसे निचली कैटेगरी की रेटिंग 'बीबीबी -' में बरकरार रखा है। हालांकि कंपनी ने पिछले वर्षों की ही तरह आउटलुक स्थिर बताया है। एसएंडपी के अनुसार भारत ने ऐसी व्यवस्था विकसित कर रखी है कि वह किसी भी वित्तीय चुनौती का सामना करने में सक्षम है। हालांकि सरकार को अगले 24 महीनों के दौरान बड़ी पूंजी की जरूरत बनी रहने वाली है। एजेंसी ने कहा, भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में लंबी अवधि के लिए औसत से ऊपर रियल जीडीपी विकास दर झलकती है। साथ ही मौद्रिक नीति के स्तर पर चीजें काफी सुधरती दिख रही हैं।

आगामी संसद सत्र में आएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार आगामी मानसून सत्र में डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लाने जा रही है। अगर इस बिल को संसद की मंजूरी मिल गई तो बैंक में जमा पांच लाख तक की राशि का इंश्योरेंस हो जाएगा। यानी अगर बैंक डूबता है तब भी ग्राहक को अपनी पांच लाख तक जमा रकम हर हाल में मिल जाएगी। अभी बैंक में ग्राहक की जमा रकम पर सिर्फ एक लाख का इंश्योरेंस है। आगामी 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी कर ली गई है। दो वर्ष पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से इंश्योर्ड एक लाख राशि की सीमा को पांच लाख तक बढ़ाने की घोषणा हुई थी, लेकिन इसे कानून का रूप नहीं दिया जा सका। पिछले वर्ष बजट में इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी।

बैंक में जमा राशि की इंश्योरेंस सीमा बढ़ाने से बैंक संचालित करने के जोखिम में भी कमी आएगी और ग्राहक भी खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। अभी सरकारी बैंक के अधिकतर जमाकर्ता यह समझते है कि बैंक में जमा उनकी राशि पूरी तरह से सुरक्षित है और उस राशि को दिलाने की गारंटी सरकार की है। जानकारों के मुताबिक जमा राशि की इंश्योरेंस सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख तक करने से अधिकतर जमाकर्ता पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि सीमा बढ़ने से इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ेगी, जिसका बोझ ग्राहकों पर डाला जा सकता है। वहीं, सरकार आगामी मानसून सत्र में क्रिप्टोकरेंसी के नियामन संबंधी कोई बिल नहीं लाने जा रही है।

जून में पाम ऑयल आयात 24% घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र: इस वर्ष जून में पाम ऑयल का आयात मई के मुकाबले 24 फीसद घटकर 5,87,467 टन रहा। उद्योग जगत के संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने कहा कि घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक रहने की वजह से जून के आयात में कमी आई। संगठन ने हाल ही में क्रूड पाम ऑयल (सीपीओ) तथा अन्य पाम ऑयल पर सितंबर तक आयात शुल्क घटाने को लेकर चिंता जताई। एसईए का कहना था कि इसके अलावा आरबीडी पामोलिन को भी दिसंबर तक आयात प्रतिबंध से मुक्त करने की वजह से घरेलू रिफाइनर और तिलहन उत्पादकों को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

इस वर्ष मई में 7,69,602 टन पाम ऑयल का आयात किया गया था। वहीं, पिछले वर्ष जून में आयातकों ने 5,64,839 टन पाम ऑयल मंगाया।

फ्लिपकार्ट ने जुटाए 26,800 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी रिटेलिंग दिग्गज वालमार्ट नियंत्रित फ्लिपकार्ट ने 3.6 अरब डॉलर (करीब 26,806 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। यह रकम वालमार्ट, सॉफ्टबैंक, सिंगापुर की जीआइसी पीटीई तथा कई अन्य सरकारी वेल्थ व पेंशन फंड से जुटाई गई है। इसके बाद कंपनी का मूल्य 37.6 अरब डॉलर (करीब 2,78,200 करोड़ रुपये) हो गया है। पिछले वर्ष जब कंपनी ने वालमार्ट से 1.2 अरब डॉलर जुटाए थे, तब उसका मूल्य लगभग 25 अरब डॉलर लगाया गया था। इस लिहाज से करीब एक वर्ष में कंपनी का मूल्य लगभग 50 फीसद बढ़ चुका है।

एक बयान में फ्लिपकार्ट ने कहा कि टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, ब्लैकस्टोन ग्रुप समर्थित अंतरा कैपिटल, अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड एडीक्यू, कतर इंवेस्टमेंट अथॉरिटी और कनाडा पेंशन प्लान इंवेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपी इंवेस्ट्स) ने कंपनी में निवेश किया है। आइपीओ लांच करने की प्रक्रिया में जुटी फ्लिपकार्ट में इस नवीनतम निवेश से कंपनी को अमेजन इंक, मुकेश अंबानी नियंत्रित जियोमार्ट और टाटा ग्रुप से स्पर्धा करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बीच, सूत्रों के अनुसार कंपनी अपने कर्मचारियों को इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन के तहत आवंटित शेयरों में से करीब 600 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बायबैक भी करेगी।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

फर्जी पासपोर्ट-वीजा बनवाने वाला गिरफ्तार

अहमदाबाद : गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सूरत शहर से फर्जी पासपोर्ट और वीजा के जरिये विदेश भेजने के मामले में आदम मुहम्मद इरफान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। (प्रेट्र)

कुत्ते का बच्चा खरीदने के चक्कर में गंवाए 66 लाख

देहरादून : एक महिला ने बेटी को जन्मदिन पर उपहार में देने के लिए आनलाइन कुत्ते का बच्चा मंगवाया था। एक साइबर ठग ने उन्हें झांसे में लेकर कुत्ते का बच्चा भेजने के नाम पर 66.39 लाख रुपये ठग लिए। (जासं)

इफको के एमडी से जुड़ी मनी लांड्रिंग जांच में सीए गिरफ्तार

नई दिल्ली: ईडी ने इफको के एमडी और सीईओ यूएस अवस्थी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सीए आलोक कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। (आइएएनएस)

श्रीराम के वंश चिह्न वाले सिक्के के नाम पर 39 लाख की ठगी

संवादसूत्र, अयोध्या

भगवान राम के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। श्रीराम की जन्मभूमि एवं वंश के चिह्न युक्त अष्टधातु का सिक्का दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से 39 लाख रुपये की ठगी की गई है।

जिले के इनायतनगर स्थित मजनाई निवासी प्रमोद कुमार यादव ने महाराष्ट्र के पुणे निवासी सुनील गुलाबराय को सिक्के की तस्वीर दिखाकर झांसे में लिया। सिक्के का दाम तय होने के बाद सुनील रामनगरी पहुंचे और यहां सिविल लाइंस क्षेत्र में 39 लाख रुपये उन्होंने प्रमोद को दे दिए। प्रमोद ने जल्द ही सिक्का उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। दाम लेने के बाद भी कई महीनों तक सिक्का न मिलने पर सुनील ने प्रमोद से संपर्क किया तो वह टालमटोल करने लगा। जिस करीबी के माध्यम से सुनील का संपर्क प्रमोद से हुआ था उसने भी अपना फोन स्विच आफ कर लिया। प्रमोद की तलाश में सुनील फिर रामनगरी पहुंचे। काफी दिनों तक भटकने के बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। कोतवाली नगर पुलिस ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली। एएसपी सिटी विजय पाल सिंह और एएसपी पलाश बंसल के नेतृत्व में टीम छानबीन में लगी थी। मंगलवार को पुलिस ने प्रमोद को दबोच लिया। कोतवाल सुरेश पांडेय ने बताया कि इस प्रकरण में बिचौलिये की तलाश की जा रही है।

रामनगरी में मुसीबत बने ठग

रामनगरी में ठगों का जाल बढ़ता जा रहा है। सुनील कोई पहला शिकार नहीं है। गत वर्ष जयपुर के सेक्टर पांच प्रभातनगर निवासी डा. राकेश केदावत को गाइड के वेश में घूम रहे एक युवक ने राममंदिर निर्माण के लिए चंदे का झांसा देकर 3300 रुपये एक मंदिर में पार कर दिए थे। सहयोग राशि की कोई रसीद और प्रमाण न मिलने पर राकेश ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो ठगे जाने का एहसास हुआ। राममंदिर ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बना कर भी ठगी का मामला सामने आ चुका है।

ठग बाबा के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की उच्च स्तरीय जांच

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने दिए गोपनीय जांच के निर्देश

महिला से जेवर ठगने के आरोप में गिरफ्तार फर्जी बाबा के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने और मुख्यमंत्री के हाथों पुस्तक का विमोचन कराने के मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वर्द्धन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। इसकी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है।

पुलिस ने दो दिन पहले पानीपत (हरियाणा) के योगी प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र उर्फ रोबिन खलीफा को ऋषिकेश की एक महिला से जेवर ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस साधु का रूप लिए ठग ने गिरफ्तारी से तीन दिन पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी पुस्तक मानस मोती का विमोचन कराया था। फर्जी बाबा की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री से उसकी मुलाकात अचानक चर्चा में आ गई। इससे सवाल उठने लगे की फर्जी बाबा की पृष्ठभूमि की बिना छानबीन किए आखिर कैसे मुख्यमंत्री से पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम तय हुआ। मामले के इंटरनेट मीडिया में चर्चा में आने पर मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसे लेकर सक्रिय हुआ। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश देते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंद वर्द्धन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई जा रही है। जांच कौन करेगा, यह अभी गोपनीय है।

'सोना तस्करी के आरोपितों की जमानत रद करने से इन्कार'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनआइए की तरफ से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें केरल सोना तस्करी के 12 आरोपितों की जमानत रद करने की मांग की गई थी। गत वर्ष पांच जुलाई को सीमा शुल्क विभाग ने तिरुअनंतपुरम हवाईअड्डे से राजनयिक चैनल के जरिये लाई जा रही 30 किलोग्राम सोने की खेप को जब्त किया था।

मामले में स्वप्ना सुरेश, सरित, संदीप नायर व फाजिल फरीद आदि पर मुकदमा दर्ज हुआ था। केरल हाई कोर्ट ने 12 आरोपितों को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले से पैदा हुए कानूनी सवालों के परीक्षण की सहमति दे दी, जिसमें कहा गया था कि सोना तस्करी का मामला सीमा शुल्क कानून के अंतर्गत आता है न कि गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के अंतर्गत। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना व जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा, 'वे (आरोपित) सरकारी कर्मचारी हैं। हम जमानत रद किए जाने के पहलू पर विचार नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम कानूनी पहलू को खुला रखेंगे।'

आयकर विभाग के खिलाफ सिद्धू पहुंचे हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू आयकर विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आयकर विभाग ने सिद्धू पर वित्त वर्ष 2016-17 की आय के गलत आकलन का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ सिद्धू ने आयकर विभाग के कमिश्नर के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे कमिश्नर ने रद कर दिया था। अब सिद्धू ने इन आदेशों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। जस्टिस अजय तिवारी एवं जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने सिद्धू की इस याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 की इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय 9,66,28,470 बताई थी रिटर्न जमा करने के बाद रसीद भी आ गई थी, लेकिन 13 मार्च, 2019 को बताया गया कि की आय 13,19,66,530 रुपये है।

अमरावती भूमि घोटाले पर सुनवाई 22 जुलाई को

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमरावती भूमि घोटाले को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। पूर्ववर्ती तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) सरकार के दौरान अमरावती में भूमि सौदों में हुई कथित अनियमितताओं की एसआइटी जांच पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ राज्य सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है कि मामले को वापस हाई कोर्ट में भेजा जाए। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि हाई कोर्ट में दायर रिट याचिका 'शासन के प्रतिशोध' का नतीजा है। पीठ ने कहा कि अगर दोनों पक्ष सुनवाई के पक्ष में है तो तो अदालत विवेक का इस्तेमाल कर सकती है।

बुलंदशहर में युवती को पेट्रोल डालकर जलाया, मौत

जासं, बुलंदशहर

बुलंदशहर में एक युवक ने युवती को पेट्रोल डालकर जला दिया। उसकी दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। युवती ने सीओ को दिए बयान में बताया है कि प्रेमी के भाई ने उस पर पेट्रोल डाला था। हालांकि युवती के पिता ने मुकदमें में प्रेम-प्रसंग का जिक्र नहीं किया है। पुलिस की मौजूदगी में मंगलवार को युवती के शव का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मुंडाखेड़ा गांव निवासी एक व्यक्ति ने खुर्जा कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में बताया है कि सोमवार को उनकी 22 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। उनके घर के पास ही आरोपित पवन का घेर है। आरोपित ने बेटी को गोबर उठाने के बहाने अपने घेर में बुलाया था और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिला अस्पताल से युवती को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। रात ढाई बजे उसकी मौत हो गई।

युवती के बयान के आधार पर प्रेमी के भाई पवन को गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि घटना के समय पवन की उपस्थिति कहीं और पाई जा रही है। प्रथमदृष्टया युवती के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है। गंभीरता से पूरे प्रकरण की छानबीन की जाएगी। अगर कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

युवती ने सीओ को यह दिए हैं बयान: पवन ने गोबर उठाने के लिए अपने घेर में बुलाया था। उसने पहले से ही पेट्रोल बोतल से पलटकर बाल्टी में रखा हुआ था। बाल्टी से पेट्रोल उसके ऊपर डाल कर आग लगा दी। पवन के भाई से उसकी बातचीत चल रही थी। वह ट्रेनिंग पर गया हुआ है। इसी वजह से पवन ने आग लगाई।

इंसाफ नहीं मिला तो उठाएंगे हथियार: युवती के भाई ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि उसके पापा बीडीसी का चुनाव जीते हैं।

कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी की पत्नी के साथ अनबन सामने आई

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता भरत सिंह सोलंकी ने अपनी पत्नी रेशमा पटेल से अनबन की बात सार्वजनिक करते हुए किसी प्रकार का आर्थिक लेनदेन नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रेशमा के साथ आर्थिक लेनदेन करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। पति-पत्नी करीब चार साल से अलग रह रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी ने सोमवार को गुजरात के समाचार पत्रों में अपने वकील केपी तपोधन के माध्यम से एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराया है। इसमें बताया गया है कि उनकी पत्नी रेशमा बेन पटेल पिछले चार साल से वडोदरा के अर्पिता पार्क में अपनी मर्जी से रह रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी के पुत्र और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके भरत सिंह गुजरात प्रदेश कांग्रेस को संभाल चुके हैं। एक बार फिर उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है।

असम मानवाधिकार आयोग ने दिए मुठभेड़ की जांच के आदेश

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम मानवाधिकार आयोग (एएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पुलिस मुठभेड़ों की परिस्थितियों की जांच कराने को कहा है। मुठभेड़ों में 12 आरोपित मारे गए। एएचआरसी के सदस्य नब कमाल बोरा ने आदेश में उल्लेख किया है कि समाचारों के मुताबिक, सभी आरोपित निहत्थे थे और फायरिंग के समय हथकड़ियों में थे।

मंगलवार को आयोग ने राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं राजनीतिक विभाग को जांच गठित करने का निर्देश दिया है। उन परिस्थितियों और तथ्यों का पता लगाने के लिए कहा गया है जिनके कारण 12 आरोपितों की मौत हुई। प्रधान सचिव से 17 अगस्त तक जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इससे पहले असम निवासी वकील आरिफ ज्वादर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को असम पुलिस के खिलाफ शिकायत सौंप जांच कराने की मांग की थी।

सिलगेर फायरिंग मामले में सुकमा कलेक्टर व एसपी को मिला नोटिस

जगदलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सिलगेर में बीते 17 मई को सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे आदिवासियों पर फायरिंग का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पहुंच गया है। एनएचआरसी ने इस मामले में सुकमा कलेक्टर व एसपी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को रखी गई है। बता दें कि सिलगेर में कैंप का विरोध कर रही बेकाबू भीड़ पर हुई फायरिंग में तीन ग्रामीणों की मौत हो गई थी और 18 लोग घायल हुए थे। पुलिस का दावा है कि आदिवासियों की भीड़ की आड़ में सशस्त्र नक्सलियों ने फोर्स पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग की चपेट में ग्रामीण आ गए थे।

देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाली

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) 1860 की धारा 124-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। इस याचिका पर अब 27 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ के अनुसार अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने भारतीय संघ को नोटिस जारी कर 12 जुलाई तक प्रतिक्रिया मांगी थी। मणिपुर और छत्तीसगढ़ के दो पत्रकारों किरेचंद्र वांगखेमचा और कन्हैयालाल शुक्ला ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है।

दैनिक जागरण

ज्ञान का अभिमान हो जाना अज्ञान का सूचक है

तीसरी लहर की आशंका

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों एवं बाजारों में मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने में हीलाहवाली का परिचय दिए जाने पर जो चिंता व्यक्त की, उस पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यह जरूरत इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना से बचाव के उपायों की अनदेखी के चलते संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका गहराती जा रही है। एक आकलन तो यह भी है कि तीसरी लहर पहले ही शुरू हो चुकी है। पता नहीं यह आकलन कितना सटीक है, लेकिन यह चिंताजनक है कि महाराष्ट्र और केरल के हालात संतोषजनक नहीं दिख रहे हैं। इन दोनों राज्यों के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी न आना चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि लोग यह तो पूछ रहे हैं कि तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है, लेकिन इस पर गौर नहीं कर रहे कि इस लहर से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? निःसंदेह पर्यटन स्थलों में जाने की मनाही नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा गया कि इन स्थलों में किसी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रहे कि तीसरी लहर को रोकने अथवा उसे शिथिल करने में सफलता तब मिलेगी जब सरकारों को आम जनता का सहयोग मिलेगा।

यह ठीक है कि लाकडाउन में रियायत देने का सिलसिला कायम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। दुर्भाग्य से यही देखने को अधिक मिल रहा है। पर्यटन स्थलों से लेकर छोटे-बड़े शहरों के प्रमुख बाजारों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने के प्रति बिल्कुल बेपरवाह हैं। इस बेपरवाही को देखकर तो यही लगता है कि लोग यह मान बैठे हैं कि कोरोना का खतरा टल गया है। सच्चाई यह है कि अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है। अभी भी प्रतिदिन करीब 30 हजार से अधिक संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। बेशक संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन कोरोना अभी भी जानलेवा बना हुआ है। जहां लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, वहीं राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को भी इसके लिए सजगता बरतने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक स्थलों में भीड़-भाड़ न बढ़ने पाए। मौजूदा हालात में राज्य सरकारों को धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों को हरी झंडी देने से परहेज करना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों का दुस्साहस

तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध के नाम पर पंजाब में प्रदर्शनकारियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। पटियाला के राजपुरा में बंधक बनाए गए भाजपा नेताओं को करीब 11 घंटे बाद बेशक पुलिस ने मुक्त करा लिया, लेकिन पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की नाकामी साबित हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक न सुनी और सारी रात भाजपा नेता कमरे में बंद रहे। चूंकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन नेताओं को सुरक्षित निकालने का आदेश दिया था और पुलिस को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई उसकी उसकी मजबूरी बन गई थी। उम्मीद के विपरीत इस घटना के बाद प्रदेश भर में प्रदर्शनकारियों की मनमानी और बढ़ गई। सोमवार को भाजपा नेताओं को जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने से रोकने की कोशिश की गई। कुछ जिलों में तो पुलिस ने ही भाजपा नेताओं को रास्ते में रोक लिया, क्योंकि प्रदर्शनकारी पहले से ही जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंच गए थे। फतेहगढ़ साहिब के अमलोह में तो प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग के घर का घेराव कर दिया। डीएसपी की गाड़ी में उन्हें किसी तरह वहां से निकाला गया। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रदर्शनकारियों की मनमानी क्यों बढ़ती जा रही है? दरअसल राजपुरा की घटना से पहले प्रदेश में भाजपा नेताओं पर हमले और कार्यक्रमों में तोड़फोड़ की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर हमले के बाद भाजपा नेताओं ने राज्यपाल व डीजीपी से मुलाकात की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। अब मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन जिस तरह कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सियासत की जा रही है उसे देखते हुए ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। भाजपा नेता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं किसानों के नाम पर विरोधी दलों के कार्यकर्ता भी हमला करने और तोड़फोड़ में शामिल हैं। सरकार के अंदर अगर इच्छाशक्ति हो तो कोई कारण नहीं कि पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों की अराजकता पर लगाम न लगा सके। प्रदेश में अमन-चैन बरकरार रहना चाहिए। इस तरह की अराजकता से किसी का भला नहीं होने वाला है। यदि माहौल खराब होता है तो इसका असर उद्योग-व्यापार पर भी पड़ेगा और कुल मिलाकर नुकसान पंजाब व पंजाब के लोगों का ही होगा।

सत्ता के नशे में चूर शी चिनफिंग



विजय क्रांति

शी चिनफिंग का अहंकारी अंदाज लोगों को पूर्व सोवियत संघ की याद दिला रहा है, जब सर्वोच्च कम्युनिस्ट नेता निकिता ख्रुश्चेव ने पश्चिमी देशों को धमकाया था

खुद को जीवन भर के लिए चीन के सर्वोच्च पद पर नामित कराने पर आमादा शी चिनफिंग हताशा में कई ऐसे खतरनाक कदम उठा रहे हैं, जो सोवियत संघ की तर्ज पर चीन को टुकड़े-टुकड़े करने का कारण भी बन सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति सर्वोच्च शासक की गद्दी जीवनपर्यंत अपने नाम कर लेने के लिए इस हद तक उतावले हैं कि वह कई बार अवसर की शालीनता और अपने पद की गरिमा भी भूल जाते हैं। जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह के मौके पर चीन की जनता उनकी ओर मुखातिब थी और दुनिया भर के लोग उनकी बात सुनने को उत्सुक थे, तब उन्होंने धमकी दे डाली कि जो कोई भी चीन को दबाने की कोशिश करेगा उसका सिर कुचल कर लहूलुहान कर दिया जाएगा। चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत के बारे में जानने वालों को उम्मीद नहीं थी कि अपनी पार्टी के शताब्दी समारोह जैसे गरिमामयी मौके पर वह अपनी ताकत का ऐसे अहंकारी अंदाज में प्रदर्शन करेंगे। शी के इसी अहंकार ने लोगों को पिछली सदी के छठे दशक में सोवियत संघ की याद दिला दी, जब सर्वोच्च कम्युनिस्ट नेता निकिता ख्रुश्चेव ने ऐसे ही एक मौके पर दहाड़ते हुए सभी पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली थी, 'तुम्हें सुनकर अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच यह है कि इतिहास हमारे पक्ष में है। हम तुम सबको धरती में गाड़ देंगे।' इतिहास जानता है कि उसके बाद क्या हुआ? सोवियत संघ के 16 टुकड़े हो गए और पूर्वी यूरोप से कम्युनिज्म का सफाया हो गया।

चेयरमैन माओ के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में यह नियम बना दिया गया था कि चीनी राष्ट्रपति और पार्टी महासचिव पद पर कोई भी नेता पांच-पांच साल के लिए दो से अधिक बार नहीं चुना जाएगा, लेकिन 2012 में सत्ता में आए शी पर ताकत का नशा इस कदर सवार है कि उन्होंने 2018 में इस नियम को रद करा दिया। इससे पहले 2013 में पार्टी के भीतर जोड़तोड़ करके वह चीनी सेना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन यानी प्रधान सेनापति का पद भी हथिया चुके थे। इस साल अक्टूबर में होने जा रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 21वें अधिवेशन में वह ऐसा प्रस्ताव पारित कराने का माहौल बनाने में जुटे हैं कि उन्हें जीवन भर के लिए देश का सर्वोच्च नेता मान लिया जाए। जापान के सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करने से लेकर दक्षिणी चीन सागर में चीनी समुद्र तट से दो-तीन हजार किमी दूर के फिलीपींस और ब्रूनेई समेत दर्जन भर देशों के इलाकों को अपना बताने और हिंद-प्रशांत, हिंद महासागर तथा अरब सागर तक अपनी नौसेना को तैनात करने जैसे कई हेकड़ी भरे काम हैं, जिनके दम पर वह खुद को विश्व विजेता दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन यह शी की बदकिस्मती ही है कि उनका कोई दांव सीधा नहीं पड़ रहा। शी का सबसे बड़ा दांव लद्दाख पर हमला था। मदांध शी को भरोसा था कि लद्दाख में गलवन, पैंगांग झील, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा समेत कई स्थानों पर हमला करके वह पूर्वी लद्दाख में भारत की सेना को हरा देंगे और सियाचिन तथा दौलत बेग ओल्डी समेत पूरा पूर्वी लद्दाख चीन का हो जाएगा। शी यह मानकर बैठे थे कि हांगकांग पर बीजिंग की दादागीरी कायम होने के बाद लद्दाख में चीन की इस जीत से वह चीनी जनता के हीरो हो जाएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी उनके सिर पर सर्वोच्च नेता का नया ताज रख देगी, लेकिन गलवन में भारतीय सेना के हाथों चीनी सेना की दुर्गति ने उनके सपने को धूल में मिला दिया।



अवधेश राजपूत

भारत के हाथों शी की हाल में फिर से किरकिरी तब हुई जब मोदी सरकार ने न तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह के लिए अपने किसी नेता को भेजा और न ही शी को बधाई संदेश दिया। इसके पांच दिन बाद तिब्बत के निर्वासित शासक और धर्मगुरु दलाई लामा को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई देकर शी के जले पर नमक छिड़का। अमेरिका ने भी दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और तिब्बत तथा शिंजियांग के सवाल पर चीन की कड़ी आलोचना की। अक्टूबर अधिवेशन से पहले शी को यह सब नागवार गुजर रहा है। खिसियाई चीनी सत्ता ने पहले तो भारत और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला, फिर ग्लोबल टाइम्स भारत और चीन के बीच दोस्ताना संबंधों की दुहाई देने बैठ गया। एक जुलाई के अपने भाषण में शी ने ताइवान का नाम लेकर धमकी दी थी कि ताइवान के विलय को लेकर हमारा इरादा एकदम अडिग है, लेकिन उसी सप्ताह जब चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए उसके क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजे तो ताइवान ने उनका मुकाबला करने के लिए अपने विमानों को भेज दिया। इस अप्रत्याशित जवाब ने चीनी विमानों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया।

शी इससे बहुत परेशान हैं कि जबसे मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तबसे उनकी कई बार किरकिरी हो चुकी है। लद्दाख और डोकलाम में चीन की ईंट का जवाब पत्थर से देने के अलावा मोदी सरकार ने जिस तरह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को नया स्वरूप दिया और वियतनाम तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का साथ देना शुरू किया, वह चीन को रास नहीं आ रहा। चीन इसलिए भी मुश्किल में है, क्योंकि दुनिया यह मानने को मजबूर हो रही है कि कोरोना वायरस उसी ने फैलाया। ज्यादातर देश चीन के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं और आर्थिक-व्यापारिक क्षेत्र में इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। अब इसकी आशंका बढ़ रही है कि चीन का स्थायी शासक बनने की सनक में शी चिनफिंग अक्टूबर से पहले कहीं भारत, जापान, ताइवान या वियतनाम जैसे किसी देश के साथ कोई नया सैन्य टकराव न शुरू कर बैठें। अगर अपनी बौखलाहट में वह ऐसा करने की हिमाकत करते हैं तो उनका यह कदम चीन को उसी तरह महंगा पड़ सकता है जैसा पूर्व सोवियत संघ को पड़ा था। कहीं ऐसा न हो जाए कि दूसरे देशों की जमीन हड़पने के चक्कर में वह चीन को ही तुड़वा बैठें और तिब्बत, शिंजियांग, दक्षिणी मंगोलिया, मंचूरिया और हांगकांग गंवाकर चीन का हाल पूर्व सोवियत संघ जैसा हो जाए।

(लेखक तिब्बत एवं चीन मामलों के विशेषज्ञ और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

आतंकवाद की खुली–छिपी पैरवी



राजीव सचान

यदि अखिलेश अभी सत्ता में होते तो क्या लखनऊ से अंसार गजवातुल हिंद के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो पाती?

अंसार गजवातुल हिंद नाम वाले आतंकी संगठन के दो संदिग्ध आतंकियों मिनहाज और मसीरुद्दीन की लखनऊ से गिरफ्तारी पर सपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर वैसा ही बयान दिया, जैसा उन्होंने कोविड रोधी वैक्सीन को लेकर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें भाजपा की वैक्सीन पर भरोसा नहीं। अब दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर उनका कहना है कि उन्हें भाजपा सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या कहता है यह कथन? बस यही कि जिन्हें आतंकी कहकर गिरफ्तार किया गया, वे झूठे मामले में फंसाए गए हो सकते हैं। अखिलेश यादव का अनुसरण मायावती ने यह कहकर किया कि विधानसभा चुनाव करीब आने पर पुलिस की ऐसी कार्रवाई संदेह पैदा करती है। उन्होंने यह नसीहत भी दी कि सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे, जिससे जनता में बेचैनी बढ़े। यहां जनता से उनका आशय मुस्लिम समाज से है और इसलिए है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरह उन्हें भी मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं।

यह अच्छा हुआ कि किसी ने अखिलेश यादव और मायावती से यह नहीं पूछा कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा शामली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के बारे में उनके क्या विचार हैं, अन्यथा इस मामले में भी शायद उनकी ओर से वैसा ही कुछ कहा जाता, जैसा लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर कहा गया। आतंकियों की तरफदारी करने वाले अखिलेश यादव और मायावती के बयान ऐसे समय आए हैं, जब आज से दस वर्ष पहले इन्हीं दिनों (13 जुलाई) को मुंबई में झावेरी बाजार, दादर और ओपेरा हाउस में एक के बाद एक बम विस्फोट हुए थे। इनमें 26 लोग मारे गए थे और तमाम घायल हुए थे। यह वह दौर था जब देश में आए दिन कहीं न कहीं बम विस्फोट होते ही रहते थे। उत्तर प्रदेश भी ऐसी आतंकी घटनाओं से अछूता नहीं था। नवंबर, 2007 में फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ की कचहरी में बम विस्फोट हुए थे। इन धमाकों में 15 लोगों की जान गई थी और इससे दूने लोग घायल हुए थे। इसी वर्ष मई में गोरखपुर में भी बम धमाके हुए थे और दिसंबर में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला हुआ था, जिसमें सात जवानों की जान गई थी। ये सब भीषण आतंकी घटनाएं थीं। इन आतंकी घटनाओं के लिए कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए थे, लेकिन जब 2012 में अखिलेश सत्ता में आए तो उन्होंने इन संदिग्ध आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की पहल की। पहले स्थानीय अदालतों ने उनकी इस पहल पर पानी फेरा, फिर उच्च न्यायालय ने। इस खतरनाक पहल के बारे में पहले से अंदेशा था, क्योंकि सपा ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद 'निर्दोष' लोगों पर चल रहे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। पता नहीं सपा को कैसे पता चला कि जिन तत्वों को आतंकी घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया वे निर्दोष हैं? जैसे भी पता चला हो, यह गनीमत रही कि अदालतों ने सजगता दिखाई, अन्यथा कथित निर्दोष आतंकी छूट जाते। ऐसा होता तो अनर्थ होता।



आतंकियों से बरामद विस्फोटक के साथ एटीएस। फाइल

यह खास तौर पर गौर से पढ़ें कि अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री जिन आतंकियों के मुकदमे वापस लेना चाहते थे, उनमें से अनेक को बाद में उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हुई। एक क्षण के लिए कल्पना करें कि अगर अखिलेश सरकार की पहल पर ये आतंकी छूट जाते तो पुलिस-प्रशासन के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ता और आतंकियों का दुस्साहस कितना अधिक बढ़ जाता? कल्पना यह भी करें कि यदि अखिलेश यादव इस समय सत्ता में होते तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस लखनऊ से अंसार गजवातुल हिंद के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर पाता? वह अगर गिरफ्तार कर भी लेता तो शायद उसे सरकार के दबाव में यह कहकर उन्हें छोड़ना पड़ता कि उससे गलती हो गई और जिसे वह प्रेशर कुकर बम समझ रहा था, उसमें तो अधपकी दाल मिली। निःसंदेह जब तक कोई दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता और यह सिद्धांत आतंकियों पर भी लागू होता है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि संदिग्ध आतंकियों की वैसी खुली पैरवी की जाए, जैसी अखिलेश यादव ने की। यदि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं तो क्या वह अपनी सुरक्षा से पुलिस के जवान हटाने वाले हैं? मायावती से भी यह पूछा जाना चाहिए कि क्या अगर किसी राज्य में चुनाव करीब आ गए हों तो वहां की पुलिस को संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने के बजाय चुनाव खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? मायावती को यह भी बताना चाहिए कि आखिर वह कौन सी जनता है जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर बेचैन हुई जा रही है?

यह पहली बार नहीं जब संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश की तरह खुले और मायावती की तरह से छिपे तौर पर उनका बचाव किया जा रहा हो। सेक्युलरिज्म और पंथनिरपेक्षता के नाम पर ऐसा देशघाती तमाशा खूब होता आ रहा है। 2008 के बाटला हाउस कांड याद कीजिए। सलमान खुर्शीद की मानें तो यहां मारे गए आतंकियों की फोटो देखकर सोनिया गांधी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। बाटला हाउस मुठभेड़ को जिन नेताओं ने फर्जी करार दिया था, उनमें प्रमुख थे दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान मौके से भागे आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को अभी चार महीने पहले मौत की सजा सुनाई गई। जब यह सजा सुनाई गई तो सलमान खुर्शीद, केजरीवाल, दिग्विजय सिंह और ममता बनर्जी से कुछ बोलते नहीं बना। ये इसलिए कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि बुरी तरह बेनकाब हो चुके थे।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

बादल

एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है-संकट के बादल। जिस तरह बादल आते हैं और बरसकर चले जाते हैं, उसी तरह जीवन में संकट आते हैं और कोई सीख देकर चले जाते हैं। बादलों का आना, जाना या बरसना प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसी तरह जीवन में संकट आते हैं और चले जाते हैं। इनसे घबराने या निराश होने की आवश्यकता नहीं। बादल धरती और आकाश के बीच तापमान को संतुलित करने की भूमिका भी निभाते हैं। ठीक इसी प्रकार संकट मनुष्य के लिए प्रायः समस्याओं का रास्ता आसान करते हैं। घने व कालीघटा वाले बादल डराते तो हैं, लेकिन ये मनोरम परिदृश्य एवं वातावरण का सृजन भी करते हैं और मन में नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं। एक पथिक जब थक जाता है तो ऐसे बादल उसके हृदय में आनंद रस की वर्षा करते हैं। मनुष्य को संकटों का स्वागत भी इसी प्रकार करना चाहिए।

बादल यदाकदा क्रोध, अहंकार, मोह एवं लिप्सा के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। मनुष्य में इन बुराइयों का अल्पकालिक आगमन होता आया है। समय के अंतराल में इन बुराइयों का शमन होता है और मानव अपनी पवित्रता पुनः प्राप्त करता है। जल से वाष्प और वाष्प से फिर जल बनने का क्रम इन बादलों की अबूझ पहेली है। बादल से बरसने वाला जल यही संदेश देता है कि संकटों के बाद मनुष्य के पास अमूल्य अनुभव उसके जीवन में सफलता के सूत्र की तरह है। कवियों ने तो बादलों से अपनी कल्पनाओं को अनोखे रंगों से भरा है। संत महात्माओं ने बादल को एक पथिक की भांति बताया है। विरह की घड़ी में वियोग की वेदना ने ऊंचाई तक बादलों को स्पर्श किया। यादों की ज्वाला बादलों के पार चांद-तारों तक पहुंच जाती है। बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढककर अंधेरा उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह असत्य भी सत्य को कुछ समय के लिए ढक देता है। बादल जलवृष्टि करके स्वयं रिक्त हो जाते हैं। भद्र पुरुष भी दूसरों का कल्याण करके अपने को निस्पृह रखते हैं।

डॉ. राघवेंद्र शुक्ल

छात्र–शिक्षक अनुपात में संतुलन के मायने

सुधीर कुमार

छात्र–शिक्षक अनुपात जितना कम होगा, शिक्षा उतनी ही गुणवत्तापूर्ण होगी और छात्र बेहतर ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे

देश के लिए यह गौरव की बात है कि विद्यालयी शिक्षा के हरेक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात ने शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वर्ष 2019-20 के एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की ताजा रपट के मुताबिक देश में प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 26.5, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 18.5 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 26.1 है। 2009 के शिक्षा के अधिकार कानून में प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 निर्धारित है। इस हिसाब से देखा जाए तो सभी स्तरों पर छात्र-शिक्षक के राष्ट्रीय अनुपात ने निर्धारित मानक को हासिल कर लिया है। छात्र-शिक्षक के कम होते अनुपात से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का सहज आकलन किया जा सकता है।

दरअसल किसी भी प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक छात्र-शिक्षक अनुपात होता है। यह अनुपात जितना कम होगा, शिक्षा उतनी ही गुणवत्तापूर्ण होगी और छात्र उतना ही बेहतर ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। छात्र-शिक्षक अनुपात कम होने का तात्पर्य पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता से भी लगाया जाता है। सामान्यतः एक शिक्षक के कंधे पर जितने कम बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, वह उतना ही बेहतर ढंग से यह काम कर पाता है। हालांकि कुछ राज्यों में शिक्षकों के अभाव के कारण छात्र-शिक्षक अनुपात बेमेल है, जिसका असर उस राज्य की शैक्षिक गुणवत्ता पर भी पड़ा है। छात्र-शिक्षक अनुपात की रैंकिंग में सिक्किम पूरे देश में अव्वल है, जहां केवल सात छात्रों पर एक शिक्षक है। वहीं इस श्रेणी में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार है, जहां 55.4 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। प्राथमिक शिक्षा में बिहार के अलावा केवल दिल्ली, झारखंड और उत्तर प्रदेश ही आरटीई कानून की शर्तों की पूर्ति नहीं करते हैं। इन राज्यों में एक शिक्षक के ऊपर 30 से अधिक छात्रों का दायित्व है।

हालांकि प्राथमिक स्तर पर बिहार के अलावा देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश यूनेस्को द्वारा निर्धारित मानक का पालन करते हैं। यूनेस्को ने छात्र-शिक्षक के 40:1 अनुपात को आदर्श माना है। वहीं नई शिक्षा नीति-2020 में विद्यालयी शिक्षा के हरेक स्तर पर छात्र-शिक्षक के अनुपात को 30:1 करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसे कई क्षेत्रों में 25:1 भी किया जाना है। 1937 में महात्मा गांधी ने यही सुझाव नई तालीम के संदर्भ में देते हुए कहा था कि किसी कक्षा में बच्चों की संख्या करीब 25 होनी चाहिए। इसे 30 से ज्यादा किसी भी हाल में होना नहीं चाहिए। बहरहाल छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने का एकमात्र समाधान शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने पर निर्भर करता है।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

शंकालु रवैये से नहीं निकलेगा समाधान

'आर्थिक असंतुलन दूर करे सरकार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में भरत झुनझुनवाला ने कई मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन उनके मत कुछ पूर्वाग्रह से प्रेरित लगे। प्रतीत होता है कि बड़े उद्यमों से लेकर पूंजी बाजार को लेकर लेखक के मत व्यावहारिक नहीं हैं। निःसंदेह छोटे उद्यमों की समयानुकूल सहायता आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य है, लेकिन केवल इसी कारण अपनी अर्थव्यवस्था के दुधारु क्षेत्रों की अनदेखी भला कैसे की जा सकती है। इस वास्तविकता से इन्कार किया ही नहीं जा सकता है कि यदि घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए छोटे उद्यम महत्वपूर्ण हैं तो बड़े एवं संगठित उद्योग भी उतने ही आवश्यक हैं। लेखक यह क्यों भूल जाते हैं कि तमाम बड़े उद्यमों के लिए जो एक व्यापक आपूर्ति तंत्र और ईकोसिस्टम होता है, उसमें न जाने कितने वेंडर बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाले होते हैं। फिर बड़े उद्योगों द्वारा सृजित होने वाली संपदा देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने के साथ ही कर राजस्व से लेकर रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। यदि उनसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे तभी अन्य क्षेत्रों के लिए संसाधन जुटाने में सफलता मिल सकेगी। लेखक 'ट्रिकल डाउन थ्योरी' की उपादेयता को भी नकारते हुए लगते हैं। इसी प्रकार वह सेंसेक्स या पूंजी बाजार में तेजी के सिलसिले को भी आशंका की दृष्टि से देखते हैं। यदि हमारा शेयर बाजार कुलांचे भर रहा है और देसी-विदेशी निवेशक उसमें धन लगा रहे हैं तो तभी न जब उन्हें उसमें अपेक्षित मुनाफे की गुंजाइश दिख रही होगी। असल में शेयर बाजार में जारी तेजी हमारे पूंजी बाजारों की गहराई और परिपक्वता को ही दर्शाती है। उसे लेकर शंकालु बनने के बजाय अधिक से अधिक लोगों को उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना कहीं अधिक श्रेयस्कर होगा, क्योंकि अभी भी बहुत कम भारतीय शेयरों में निवेश करते हैं। इससे जहां उद्यमों के लिए पूंजी की किल्लत दूर होगी, वहीं शेयर बाजार को भी स्थायित्व मिलेगा। यह अर्थव्यवस्था के लिए 'विन-विन' यानी समग्र फायदे का सौदा सिद्ध होगा।

जयंत मिश्रा, लखनऊ

मेलबाक्स

चुनाव आयोग की परीक्षा

आगामी वर्ष 2022 चुनावी साल है। लगभग सात राज्यों में होने वाले चुनाव ने 2022 की अहमियत बढ़ा दी है। चुनाव को लेकर पार्टियों के सामने तो चुनौतियां हैं ही, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के सामने अपनी छवि सुधारने की चुनौती है। दरअसल कोरोना महामारी के समय बंगाल में चुनाव कराने के फैसले से आयोग की छवि को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच चुनाव को कराने या टालने का फैसला करना आयोग के लिए आसान नहीं होगा।

अभय मणि त्रिपाठी, दिल्ली विश्वविद्यालय

तुष्टीकरण की राजनीति

संपादकीय गैर जिम्मेदाराना राजनीति में अखिलेश यादव व मायावती द्वारा आतंकियों की तरफदारी का विवेचन किया गया है। अखिलेश यादव व मायावती दोनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके द्वारा आतंकवादियों का पक्ष लेना निहायत ही शर्मनाक है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें अब प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वे मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पुलिस पर भरोसा था। यदि तब भरोसा था तो सत्ता बदलते ही उनका पुलिस से विश्वास क्यों उठ गया। पुलिस तो तब भी यही थी। यदि सरकार की आलोचना ही करनी है तो वह सार्थक होनी चाहिए। इस तरह अनर्गल आरोप लगाने से तो वे जनमानस के बीच हास्य का पात्र बनते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी से आगामी चुनाव में लाभ उठाने की अवधारणा भी मूर्खतापूर्ण सोच है। जनमानस को आतंकवादियों से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ जब वोट की खातिर किसी समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करने लगते हैं तो निश्चय ही समाज में उसका गलत संदेश जाता है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, ... दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 ...



अभिषेक कुमार सिंह
एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

आजकल

आसमानी बिजली के आगे इतने बेबस क्यों

आकाश से गिरती बिजली के आगे इंसान आज भी बेबस है तो विज्ञान की तरक्की पर हैरानी होती है। सवाल उन प्रबंधों को लेकर भी उठते हैं, जो आकाशीय बिजली के प्रकोप को कम नहीं कर पाए हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से मौसम के पूर्वानुमानों में आकाशीय बिजली की जानकारी दी जाती है, पर वह इतनी पुख्ता ढंग से नहीं बताई जाती कि लोग इससे अपने बचाव के बारे में सोचें, जबकि हाल में बिजली गिरने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है। ऐसे में इसकी चेतावनी देने का मजबूत तंत्र बनाया जाना आवश्यक हो गया है



आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं रोकी तो नहीं जा सकती, लेकिन पूर्व सूचना की यदि कोई प्रणाली विकसित हो जाए तो नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। फाइल

हाल में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर उत्तर प्रदेश में 42, राजस्थान में 23 और मध्य प्रदेश में छह लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में करीब 250 पशुओं की मौत भी आसमानी बिजली गिरने से इसी दौरान हुई है। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का एलान किया गया है, लेकिन मुआवजे समस्या का समाधान तो नहीं करते। देखा जाए तो बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में साल-दर-साल आकाशीय बिजली गिरने और उससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। पश्चिमी देशों में आसमानी बिजली की चपेट में आकर इतनी मौतें नहीं होतीं। आखिर हमारे देश में ऐसी समस्या क्यों है?

बढ़ रहे बिजली गिरने के मामले: आकाश में बादलों के बीच टकराव होने से एक प्रकार का विद्युत आवेश पैदा होता है। तेज आवाज और रोशनी के साथ यह तेजी से धरती की ओर आता है। इस बीच इसके रास्ते में जो भी चीज आती है उसे जला देता है। इसे आसमानी बिजली या तड़ित कहते हैं। दुनिया भर में हर साल 2.5 करोड़ से अधिक बिजली गिरने की घटनाएं होती है। वैसे तो आकाशीय बिजली कहीं भी गिर सकती है, लेकिन हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र एवं समुद्र तट के पास के इलाकों में इसकी घटनाएं अधिक होती हैं। वहां नमी या आर्द्रता की अधिकता इसकी वजह होती है। शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा बिजली गिरने की वजह भी नमी ही होती है, क्योंकि वहां पेड़-पौधे ज्यादा होने से हरियाली ज्यादा होती है। सिंचाई के साधन भी वहां अधिक होते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि बढ़ता वायु प्रदूषण इन दिनों बिजली गिरने की संख्या को बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से हुए जलवायु परिवर्तन से भी बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह शोध भी सामने आया आ चुका है कि बारिश के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग जानलेवा साबित होता है। हमारे देश में मोबाइल फोनधारकों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस वजह से भी ज्यादा लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ रहे हैं।

पेड़ कटने से भी बढ़ी घटनाएं : आकाशीय बिजली से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी का एक कारण जंगलों और गांवों-कस्बों एवं शहरों में विकास कार्यों के चलते पेड़ों की बड़ी संख्या में हो रही कटाई को भी बताया जा रहा है। कई मौसम विज्ञानियों का इस बारे में मत है कि जब पेड़ों की संख्या अधिक थी तो आकाशीय बिजली ज्यादातर मामलों में नर्म जमीन और पेड़ों पर गिरती थी, लेकिन अब ऐसी जमीनें और पेड़ कम हो गए हैं। केरल जैसे राज्यों में ताड़ के वृक्षों की तेज कटाई के कारण हाल के वर्षों में वहां भी तड़ित-प्रहार से मौतों में भारी इजाफा हुआ है। इसके अलावा शेष विश्व की तुलना में भारत में मानसूनी वर्षा के दौरान बहुत सारे लोग खेती-किसानी के कामों के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में उनके बिजली की चपेट में आने की आशंका ज्यादा रहती है। समस्या यह है कि मानसून आने से पहले हमारे देश में कुछ विशेष तैयारियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। जैसे-पहले मानसून सीजन शुरू होने से पहले गांव-देहात में घरों की मरम्मत की जाती थी, बेतरतीब पेड़ों की कटाई-छंटाई कर दी जाती थी और खंभों पर बिजली के झूलते तारों को दुरुस्त कर दिया जाता था। अब इन सभी मामलों में लापरवाही बरती जाती है। लोगों में आसमानी बिजली को लेकर जागरूकता की भी भारी कमी है। बिजली गिरने वाले मौसम में खुद को कैसे बचाना है-इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। खुले इलाकों में जहां बिजली गिरने की ज्यादा आशंका होती है, वहां ऊंची इमारतों पर तड़िचालक (बिजली से बचाने वाले एंटीना) तक नहीं लगाए जाते। दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा मौतों की कई और वजहें हैं, जिनमें से एक यह है कि ब्रिटेन-अमेरिका आदि देशों में इसकी चेतावनी देने का मजबूत तंत्र बना हुआ है। वहां समय रहते लोगों को इस बारे में पुख्ता तौर पर चेता दिया जाता है कि किन इलाकों में मौसम खराब होने से बिजली गिरने की ज्यादा घटनाएं हो सकती हैं। भारत इस मामले में अभी पीछे है।

गरीबों पर पड़ती ज्यादा मार : वैसे तो भवनों के निर्माण के वक्त तड़ित अवशोषी इंतजाम करने की सलाह दी जाती रही है, पर सवाल यह है कि बस स्टैंड, खेतों में काम करते वक्त या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होने पर क्या कोई इंतजाम हमें आसमान से लपकती मौत से बचा सकता है? यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि गिरती बिजली सिर्फ उन्हें लीलती है, जो असहाय हैं, गरीब हैं और दो जून की रोटी के जुगाड़ में घनघोर बारिश में भी अपने काम-धंधे पर निकलते हैं। बीते एक दशक में हमारे देश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 25 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। यह एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है।

सिस्टम की खामी ने किया लाचार : आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं रोकी तो नहीं जा सकती, लेकिन पूर्व सूचना की यदि कोई प्रणाली विकसित हो जाए तो नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारे देश में मानसून के दौरान दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है और बिजली गिरती है, लेकिन जिन इलाकों में इन प्राकृतिक घटनाओं की भरमार है, वहां इस तरह के मौसमी बदलावों का पूर्वानुमान लगाने वाले यंत्रों की कमी है। हमारे विशाल देश में ऐसे रडारों की संख्या केवल 27 है। हालांकि पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने 2019 में करीब 50 सेंसर लगाकर एक नेटवर्क बनाया था, जो बिजली गिरने एवं आंधी तूफान की दिशा की जानकारी देता है। वहीं झारखंड में इमारत बनाने के लिए तड़ितचालक लगाना अनिवार्य किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी कम तीव्रता की आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान से बचने के लिए लाइटनिंग ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। केरल में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की इमारत में एक विशेष किस्म का पिंजरानुमा यंत्र लगाया गया है, जो आसमानी बिजली से उसकी रक्षा करता है। यह प्रणाली वहां हवाई अड्डों पर भी इस्तेमाल में लाई जाती है। शेष राज्यों में भी यदि ऐसी ही प्रणालियां विकसित की गई होतीं तो तड़ित से होने वाली मौतों की तादाद घटाई जा सकती थी। हालांकि दावा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है, जो बिजली गिरने के बारे में पहले से बता देगा। बताया गया है कि वर्ष 2020 में इससे संबंधित पहला पायलट प्रोजेक्ट देश के पांच शहरों नागपुर, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर और रायपुर में पूरा कर लिया गया है। अब इसका विस्तार 18 अन्य शहरों में किया जा रहा है। इसरो का यह लाइट डिटेक्टिंग सिस्टम 300 किलोमीटर के क्षेत्र में निगरानी करेगा। इसके अलावा देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मौसम विभाग ने भू-स्थिर उपग्रहों में लाइटनिंग डिटेक्टर लगाने का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि इससे बिजली गिरने का अनुमान तीन से चार घंटे पूर्व लगाया जा सकेगा। ऐसी प्रणाली अभी अमेरिका में काम कर रही है। इसमें ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ इमारतों पर तड़ितचालक लगाने को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आकाशीय बिजली से बचाव के जो प्रचलित तरीके हैं उनके बारे में भी लोगों को बताए जाने चाहिए। जैसे कि बारिश के दौरान पेड़ और ऊंची इमारतों के पास खड़े न रहें, बिजली और टेलीफोन के खंभों से दूरी बनाए रखें, जमीन पर उकड़ूं बैठ जाएं।

अभी तो विडंबना यही है कि हमारे देश में आधिकारिक तौर पर घोषित 12 प्राकृतिक आपदाओं की सूची में आसमानी बिजली गिरने को स्थान नहीं दिया गया है, जबकि हर साल औसतन तीन हजार मौतें इस कारण हमारे देश में हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले वर्ष 2018 में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक शख्स की आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत पर अपने फैसले में लिखा था कि ऐसी मृत्यु को प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के रूप में देखा जाए, न कि इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जाए। अदालत ने कहा था कि आकाशीय बिजली गिरना भूकंप और सुनामी आने जैसा ही है, इसलिए इसमें मुआवजे और उपचार की व्यवस्था प्राकृतिक आपदाओं की तरह ही की जाए। केंद्र सरकार को अब इस पर विचार करना चाहिए।

स्टोर क्यों नहीं कर लेते गिरती बिजली

इस पर दशकों से विचार होता रहा है कि क्या हम आसमान से गिरती बिजली को किसी तरह संग्रह कर सकते हैं। इस बारे में एक अनुमान वर्ष 2009 में लगाया गया था कि पूरी दुनिया में एक साल में 20 खरब किलोवाट बिजली का जो इस्तेमाल हुआ, वह आसमान से धरती पर गिरने वाली बिजली से 40 गुना ज्यादा थी। आकलन कहता है कि पूरे साल में धरती पर गिरने वाली आकाशीय बिजली को बिना किसी नुकसान के पकड़ा जा सके और उसे बिजली की लाइनों में स्थानांतरित कर उसका संग्रह किया जा सके तो भी यह बिजली चार खरब 90 अरब किलोवाट के बराबर ही होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर धरती तक पहुंचने वाली समूची आकाशीय बिजली को संग्रह करने में हमें सफलता मिल जाए तो भी पूरी दुनिया को उसकी जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल पाएगी। इस मामूली उत्पादन के लिए भी हमें भारी निवेश करना होगा और ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा।

इसका अंदाजा भी लगाया गया है कि धरती पर गिरती बिजली को पकड़ने एवं संग्रह करने के लिए पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक एक मील की दूरी पर एफिल टावर की ऊंचाई जितने ढेरों लंबे टावर लगाने होंगे और उन्हें आपस में जोड़कर एक ग्रिड बनाना होगा। इससे धरती की सतह का 20 करोड़ वर्गमीटर का इलाका ऐसे टावरों से ढक जाएगा। चूंकि आकाशीय बिजली को उसकी चमक और धरती तक पहुंचने के 30 मिलीसेकेंड के अंतराल में पकड़ना जरूरी है (अन्यथा वह धरती के भीतर चली जाएगी), इसलिए इसमें बहुत ऊंची क्षमता वाले इलेक्ट्रिक सर्किट, स्टोरेज सुपर कैपेसिटर और कंडक्शन राड लगाने होंगे। इन सारे प्रबंधों पर अनुमानित खर्च खरबों डॉलर के बराबर बैठता है। आकाशीय बिजली के क्षणिक सृजन-उत्पादन और इसके संग्रह की लागत को देखते हुए विशेषज्ञ सौर ऊर्जा को ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं, क्योंकि सूरज इसके लिए लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है।

खरी-खरी

ट्विटर के खेत उखाड़ते ट्रोल के टोही ट्रैक्टर्स!

राजेश सेन

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपनी बात कहने के भी हजार पंगे हैं, क्योंकि यह एक-साथ कई लोगों की अपनी-अपनी अभिव्यक्ति का मामला जो होता है। हरेक की अभिव्यक्ति उसकी नजर में उसका अपना प्राथमिक हक होती है। फिर चाहे कोई बवाल है तो कोई वाचाल है। शायद तभी तो सेलिब्रिटीज के लिए ट्विटर पर अपनी बात कहने से पहले सोच-समझने की बेहद दरकार होती है। और फिर, किसी सेलेब्रिटी की बात अकेली ट्विटर के रैंप पर मुक्त कैटवॉक करे तो आखिर कैसे करे? ट्रोलर्स के मनमौजी टोले यहां-वहां घूमते रहते हैं। जहां ट्विटर पर उन्हें कोई विवाद-कुंवारी पोस्ट दिखती है उसे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मुद्दा चाहे जो हो, उसे विवाद बनकर ट्रोल होते देर नहीं लगती। अब कोई बात ट्रोल होकर विवादास्पद बनती है या विवादित होकर ट्रोल हो जाती है, यह गहन शोध का विषय है।

खैर, सेलिब्रिटीज की बातें भी बाज-दफा कम चितचोर नहीं होतीं। उन्हें दीन-दुनिया की सभी जिज्ञासाओं का हल अपने ट्विटर हैंडल पर हाजिर होने को मांगता है। उनका हर सुख-दुख ट्विटर की उड़ती हुई चिड़िया की मुक्त परवाज से प्रत्यक्ष वाबस्ता होता है। जरा कुछ घटा नहीं कि वे फुर्र से उड़कर ट्विटर हैंडल के घौंसले में आ धमकते हैं। बात की मनचाही बीट करते हैं और लगे हाथ उसकी खाद से विवाद की अनचाही खरपतवार पैदा कर लेते हैं। तब फिर, देखते ही देखते ट्रोलर्स के टोही ट्रैक्टर्स उनके पीछे-पीछे ट्विटर के विवादित रकबे में घुस आते हैं। ट्विटर के खेत में उगाई गई अभिव्यक्ति की निजी खरपतवार को वे निर्ममता से तहस-नहस करने लगते हैं। अराजक होकर देखते ही देखते अभिव्यक्ति की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं।

ट्विटर के खेत-खलिहान में ट्रोलर्स के टोही ट्रैक्टर्स हरदम इसी टोह में खड़े रहते हैं कि कब कोई विवाद-अविवाद का बीज यहां अपनी जड़ें जमाए। तभी तो ट्रोलर्स के उत्पाती जंगजुओं से हर कोई सभ्य सेलिब्रिटी खौफ खाता है। वजह यह कि किसी सेलेब्रिटी का ट्रोल होना उसकी बात के साथ-साथ उसकी 'निज-श्री' की चमचमाती छवि के बिगड़ने का भी मामला होता है।

ट्वीट-ट्वीट

श्रीकृष्ण को खोजने भर से कोई अर्जुन नहीं बनता। जो अर्जुन बनता है उसे श्रीकृष्ण मिल ही जाते हैं। अरुण बोथरा@arunbothra

केरल मॉडल की बानगी देख लीजिए। यहां अभी भी कोरोना संक्रमण के रोजाना 14 हजार से अधिक मामले आ रहे हैं, लेकिन लिबरल खेमा चुप है। कल्पना कीजिए कि यही किसी भाजपा शासित राज्य में होता तो उनके मुताबिक अब तक आसमान फट पड़ता। तथ्य यही है कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल 60 प्रतिशत नए मामले केवल महाराष्ट्र और केरल में आ रहे हैं। आरोह वेलणकर@ArohWelankar



आम आदमी पार्टी की तारीफ में किया गया नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गल रही। नवीन कपूर@IamNaveenKapoor

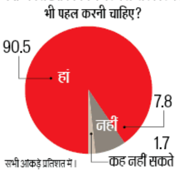
पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही किसान संगठनों में भी खलबली शुरू हो गई है। पंजाब में गुरनाम सिंह चढूनी चुनाव में उतरने की जरूरत बता रहे हैं जबकि अन्य कई नेता इस राय से असहमत हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और राकेश टिकैत में अभी तक तो एका दिखी है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। केसी सिंह@ambkcsingh

जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार के बयान में दम है। कानून के जरिये लोगों को दंडित करने के बजाय शिक्षा और जागरूकता के जरिये जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। संकेत उपाध्याय@sanket

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या तालिबान पर भरोसा न करने की भारत की नीति सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दुनियावालों देख लो दोनों आंखें खोल,
फिर अफगानिस्तान का होता डब्बा गोल।
होता डब्बा गोल पड़ें आतंकी भारी,
फिर से होते त्रस्त दिखें सारे नर-नारी।
नारकीय माहौल वहां पर था जो सालों,
अब उसका दोहराव रोक लो दुनियावालों!
- ओमप्रकाश तिवारी



अनुराग अग्रवाल
स्टेट ब्यूरो चीफ, हरियाणा

हरियाणा डायरी

आखिर सच साबित हुई आशंका



राकेश टिकैत, गुरनाम चढूनी और योगेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगजाहिर है। फाइल

केंद्र सरकार के तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे जिस आंदोलन के राजनीतिक होने की आशंका बहुत पहले से जाहिर की जा रही थी, आखिरकार वह सच साबित हो गई। आम आदमी पार्टी के टिकट पर अपनी पत्नी को शाहबाद से विधानसभा चुनाव लड़वा चुके भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे को पंजाब के विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकनी चाहिए। चढूनी ने यह बात बिल्कुल भी हलके ढंग से नहीं कही है। पहले उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने की वजह बताई, इसके पक्ष में दलील दी और सरकार तक बना लेने का सपना देखा। चढूनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराकर कोई फायदा नहीं होगा। पहले की सरकारों में भी किसानों की हालत खराब होती रही है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें किसान चुनाव लड़कर देश का पहला रोल मॉडल तैयार करें। चढूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा के सामने मिशन पंजाब का मॉडल तक रखा, जिसका रास्ता 2024 में हरियाणा तक पहुंचता है।

गुरनाम सिंह चढूनी की इस राय से किसान संगठनों, भोले-भाले किसानों और आंदोलन के रणनीतिकारों में खलबली मच गई है। अपने खेत में रहकर धान बोने की तैयारी कर रहे वास्तविक किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इससे पूरे देश में स्पष्ट संदेश गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ किसान संगठनों के आंदोलन को यूं ही राजनीतिक नहीं बताते रहे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक जकड़न में होने की वास्तविक तस्वीर सामने आ गई है। मोर्चा का नेतृत्व कर रहे अभी तक जितने भी लोग हैं, उनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक इच्छाएं हैं। भाकियू नेता राकेश टिकैत की जाट लीडरशिप पर निगाह है तो स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव दक्षिण हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपनी उपेक्षा का बदला लेने का इरादा रखते हैं।

आम आदमी पार्टी में सक्रिय रहे गुरनाम सिंह चढूनी की नजर तो मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर है। उन्हें 2022 में पंजाब में होने वाला चुनाव शॉर्टकट रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसमें वह पंजाब के किसान संगठनों के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ने का सपना पाल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चढूनी ने चुनाव लड़ने के अपने जिस राजनीतिक सोच को उजागर किया है, वह संयुक्त किसान मोर्चा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, ताकि एक व्यक्ति हां-हां करता रहे और दूसरा ना-ना करते हुए धीरे-धीरे पांव आगे बढ़ाता जाए, लेकिन यह रणनीति चढूनी ने थोड़ी जल्दी सार्वजनिक कर दी। एक टीवी चैनल पर राकेश टिकैत और पंजाब के किसान नेता दर्शनपाल तो यहां तक कहते सुनाई दिए कि संयुक्त मोर्चा का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन योगेंद्र यादव और गुरनाम चढूनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दबाने में कामयाब नहीं हो सके हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब चुनाव में कदम रखने और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के चुनावों पर निगाह होने के पीछे बड़े राजनीतिक मकसद हैं। चढूनी के पंजाब चुनाव में येन-केन-प्रकारेण अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के संकेत देने से इतना तो साफ हो गया है कि सब कुछ किसान हित में नहीं चल रहा है। किसान संगठनों का नेतृत्व करने वालों के अपने-अपने हित हैं। किसी का लक्ष्य सांसद बनने का है तो किसी का विधायक या राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करना है। कुछ सिर्फ सुर्खियों में रहकर राम-रहीम लेने-देने से काम चलाने वाले लोग हैं, जिनका राजनीति में तो क्या, बल्कि किसानों तक के बीच कोई जनाधार नहीं है।

यही वजह है कि जब किसान संगठनों के बाकी लोगों को इस आंदोलन के राजनीतिक होने का अहसास हुआ तो वे इससे धीरे-धीरे कन्नी काटकर अलग हो गए। शिवकुमार कक्का इनमें एक बड़ा नाम है। संयुक्त किसान मोर्चा हाल-फिलहाल कई फाड़ हो चुका है। कई टुकड़े होने अभी बाकी हैं। बहरहाल आंदोलनकारियों पर लाठी-डंडा चलाने के बजाय उन्हें घर में घुसने के लिए मजबूर कर देने की सरकार की रणनीति कामयाब होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बार-बार कहते रहे हैं कि यह आंदोलन किसानों का नहीं, बल्कि राजनेताओं का है। चढूनी के चुनाव लड़ने के बयान के बाद मुख्यमंत्री को भी यह कहने का मौका मिल गया कि देखिए, आखिर वही बात सामने आई, जिसकी आशंका हम पिछले आठ माह से जताते चले आ रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है कि सही क्या है और गलत कौन है?

पंजाब डायरी

मुफ्त बिजली के पीछे का अंधेरा



विजय गुप्ता
वरिष्ठ समाचार संपादक, पंजाब



जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, मुफ्त बिजली पर सियासत तेज होने लगी है। फाइल

'बादल साहब अब हमें कोई नहीं हरा सकता!' ये शब्द बलराम जी दास टंडन ने 1997 में कहे थे। तब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एवं भाजपा गठबंधन की सरकार थी। कैबिनेट की बैठक में जब किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला हुआ तो वरिष्ठ मंत्री टंडन ने यह भी कहा था, 'आपने गांवों के लोगों को अपने हक में कर लिया है, बाकी शहरी इलाकों में हम देख लेंगे।' लेकिन अगले ही साल यानी 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में गठबंधन एक भी सीट नहीं ले सका। मंथन हुआ कि आखिर मुफ्त बिजली देकर भी क्या हुआ? फिर टंडन ने ही प्रस्ताव रखा कि यह सब्सिडी बंद कर दी जाए, पर ऐसा करना तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के लिए आसान नहीं था। 2002 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की फिर हार हुई।

आज पंजाब में मुफ्त बिजली के साथ ही बिजली का संकट फिर सियासी मुद्दा है। मुफ्त बिजली के उजाले के पीछे का अंधेरा अब भी कायम है और सियासी फायदे के लिए उसे कोई देखना नहीं चाहता। अभी तक पंजाब में किसानों के अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिए बिजली मुफ्त है और छोटे उद्योगों के लिए पांच रुपये प्रति यूनिट। कांग्रेस सरकार ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी लोगों को दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का अपना वादा पूरा करने की कवायद शुरू ही की थी कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सरकार बनने पर तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया।

सवाल यह उठता है कि आखिर वोट बटोरने के लिए मुफ्त बिजली का यह शिगूफा राज्य को किस ओर ले जाएगा? राज्य में 1997 में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से शुरू हुई सब्सिडी अब साढ़े दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है। इस वित्त वर्ष में बिजली सब्सिडी के 17,800 करोड़ रुपये पंजाब सरकार पर बकाया हैं, जो उसे पावरकॉम को देने हैं। अब अगर दो सौ यूनिट सभी को मुफ्त देने की योजना लागू होती है तो सरकारी खजाने पर 7,768 करोड़ रुपये सब्सिडी का बोझ और पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर इससे माली हालत और बिगड़ेगी। पहले ही पंजाब 2.73 लाख करोड़ रुपये के कर्ज तले दबा हुआ है। एक सच्चाई यह भी है कि पंजाब में दी जा रही इस सब्सिडी का चालीस फीसद हिस्सा बिजली बिलों पर विभिन्न शुल्कों के रूप में उन लोगों से ही वसूला जा रहा है, जो सब्सिडी के दायरे में नहीं आते। यानी घरेलू उपभोक्ता एवं दुकानदार। कोई भी पार्टी यह शुल्क लगाने का विरोध नहीं करती। यही नहीं, पंजाब में आम जनता के लिए बिजली पड़ोसी राज्यों से कहीं महंगी है।

अब ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, मुफ्त बिजली पर सियासत तेज हो रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ही नहीं, बल्कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के भी निशाने पर है। सभी ने उसके दिल्ली मॉडल की 'असलियत' बताने की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में बिजली की दरें ही नहीं, फिक्स चार्ज भी देश भर में सबसे ज्यादा है। उद्योगों के लिए भी बिजली दरें ज्यादा हैं और गांवों के लोगों को सस्ती या मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। कांग्रेस सरकार आप के इस चुनावी पैंतरे का तो बाखूबी जवाब दे रही है, लेकिन बिजली संकट और निजी थर्मल प्लांटों को लेकर हुए समझौतों के मसले पर उसके पास कोई ठोस तर्क नहीं है। संकट ऐसा है जैसा करीब एक दशक पहले तक होता था। घंटों बिजली काटी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने पावर सरप्लस स्टेट को पावर क्राइसिस स्टेट बना दिया है। सरकार शायद इसी मुगालते में रही कि उसके पास सरप्लस बिजली है। अगर उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि हर साल करीब 900 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और उत्पादन या बाहर के राज्यों से बिजली लेने की क्षमता बढ़ नहीं रही है तो इसे उसकी अदूरदर्शिता और कुप्रबंधन ही कहा जाएगा। दूसरी ओर सरकार ने कई प्लांटों को बंद कर दिया। इससे बिजली उत्पादन में 25 फीसद की कमी आ गई। नतीजा बिजली का घोर संकट।

इस मामले में कांग्रेस सरकार का सियासी गणित गड़बड़ाया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के समय में हुए निजी कंपनियों से बिजली समझौतों को रद करने का वादा किया था, लेकिन साढ़े चार साल इस दिशा में किया कुछ नहीं। सरकार इन समझौतों पर अब कानूनी राय लेने जा रही है, लेकिन बचे हुए पांच-छह माह में कोई फैसला हो सकेगा, कहना मुश्किल है। बिजली के इस संकट ने अकाली दल को ऊर्जा दे दी है। वह अब सरकार को चुनौती दे रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि लोगों को मुफ्त नहीं, बल्कि 24 घंटे बिजली चाहिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा कहते हैं कि कैप्टन ने ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता बढ़ाने या उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। सरकार की इस नाकामी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।

बहरहाल अब सक्रिय हो चुके मानसून से पंजाब में बिजली की मांग कम होने और निर्बाध आपूर्ति बहाल होने की सरकार को उम्मीद है, लेकिन इस बार उत्पन्न संकट और मुफ्त बिजली का मुद्दा विधानसभा चुनाव तक सियासी माहौल को गरमाए रखेगा। जरूरत यह है कि प्रदेश सरकार इस बार उत्पन्न संकट से सबक ले, ताकि जनता त्रस्त न हो। 'मुफ्त की सियासत' का बोझ राज्य की रीढ़ को नुकसान न पहुंचाए। मुफ्त बिजली के पीछे के इस अंधेरे को दूर करना जरूरी होगा।

675 गैरजरूरी कानूनों को खत्म किया जाएगा उत्तर प्रदेश के करीब दो दर्जन विभागों में। संबंधित विभागों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय समाधान के लिए चल रही कार्यवाही की मानीटरिंग करेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 14 जुलाई, 2021

बंगाल

जेएमबी आतंकियों का संजाल

सात साल पहले बाग्लादेशी आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (जेएमबी) के बंगाल माड्यूल का खागड़ागढ़ विस्फोट के बाद भंडाफोड़ हुआ था। इसके बाद जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने जांच शुरू की और बंगाल, असम, झारखंड, बिहार समेत कई और राज्यों से तीस से अधिक जेएमबी आतंकियों को गिरफ्तार किया तो लगा कि इस संगठन का समूल नष्ट हो जाएगा। परंतु 2014 के धमाके के बाद जिस तरह से लगातार अब तक एक के बाद एक जेएमबी आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है उससे साफ हो जाता है कि प्रदेश में इनका संजाल बहुत गहरा है। इन आतंकियों को सिर्फ बंगाल या कोलकाता में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी आसानी से पनाह मिल जा रही है और वे वहां से अपनी जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बंगाल, असम, झारंखड, बिहार ही नहीं, चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक से जेएमबी आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी रविवार को महानगर के हरिदेवपुर से गिरफ्तार किए गए तीन जेएमबी आतंकियों से पूछताछ के बाद पुलिस को दो और लोगों के नाम का पता चला है, जिन्होंने इन लोगों के रहने के लिए घर से लेकर आधार कार्ड समेत कई और सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद की थी। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को जेएमबी आतंकियों के मददगार शेख शकील और सलीम मुंशी के बारे में जो जानकारी मिली है वह काफी चौंकने वाली है। सलीम मुंशी पकड़े गए आतंकियों के लिंकमैन के तौर पर काम कर रहा था और वह उसी इलाका का बाशिंदा है। आतंकियों ने हरिदेवपुर में दो मकान किराए पर लिए थे और मकान खोजने में मुंशी ने ही अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरी ओर इन तीनों बांग्लादेशी आतंकी के लिए शेख शकील ने आधार कार्ड बनवाए थे। शकील ने ही तीनों को मुंशी से मिलाया था। अब एसटीएफ इन दोनों फरार मददगारों को तलाश रही है। अब तक जेएमबी के आतंकी सीमावर्ती मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर एवं दक्षिण चौबीस परगना, बीरभूम, पूर्व एवं पश्चिम बर्द्धमान जिले में पनाह लेते थे, लेकिन पहली बार कोलकाता में इनके अड्डे का पता चला है। यह बंगाल ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए चिंता विषय है। क्योंकि जेएमबी का अलकायदा से लेकर आइएसआइएस तक से संबंध होने की कई पुख्ता जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी और अलकायदा एवं आइएसआइएस के कई आतंकियों की बंगाल से गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि जेएमबी की जड़ों को तलाश कर उन्हें खत्म किया जाए। नहीं तो हालात गंभीर हो सकते हैं।

> 2014 के धमाके के बाद जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जेएमबी आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है उससे साफ हो जाता है कि राज्य में इसका संजाल बहुत गहरा है

बिहार

जनता दरबार की सफलता


सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार से व्यवस्था में सुधार की उम्मीदें जगी हैं। फाइल

> जनता दरबार में आई शिकायतों पर सीएम हैरान होते हैं तो इसका तात्पर्य यही समझ में आता है कि वे विभागों को कामकाज की कसौटी पर खरा देखना चाहते हैं

पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने आवास पर आयोजित जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनीं। आवेदनों पर संबंधित विभाग के आला अफसरों को कार्रवाई करने का आदेश दिया। दरअसल जनता दरबार का आयोजन सीएम के लिए व्यवस्था को देखने का आईना है तो आम-अवाम के लिए यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपनी शिकायत के निवारण के साथ मुख्यमंत्री को देखने की हसरत पूरी हो जाती है। किसी की कोई खास शिकायत है तो मीडिया में खास चर्चा में आ जाती है। ऐसे में उसके समाधान की काफी हद तक गुंजाइश हो जाती है। नीतीश कुमार ने तकरीबन पांच साल बाद अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया। इस बीच डेढ़ साल से ज्यादा वक्त तो कोरोना संक्रमण में बीत गया जिससे आयोजन संभव नहीं था। कोरोना का खतरा तो अब भी बना हुआ है, परंतु वैक्सीनेशन की तेज गति से संक्रमण का दायरा घटता जा रहा है जिससे सामाजिक गतिविधियां सामान्य हुई हैं। सीएम के जनता दरबार के आयोजन के लिए काफी एहतियात बरता गया। जिलों में पखवारे भर से शिकायतों को इकट्ठा कर जिसे उपयुक्त समझा गया उसे कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए पटना लाया गया। जनता दरबार में शिकायतों पर सीएम द्वारा हैरानी जताना यह संकेत देता है कि व्यवस्था के छेद भरने जरूरी हैं। जनता दरबार में शिकायतों का ट्रेंड देखकर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि यह सब गलत है। अच्छा हुआ कि जनता दरबार फिर शुरू कर दिया। एक-एक चीज पता चल रही। वे तकरीबन पांच घंटे लोगों की शिकायतों को सुनते रहे। उनके समक्ष समाज कल्याण विभाग की ऐसी शिकायतें आईं कि अपर मुख्य सचिव को फोन करना पड़ा। शिक्षा विभाग से जुड़े मसले पर भी हैरान हुए। खुद शिक्षा मंत्री को फोन लगाया और कार्रवाई करने की बात कही। जनता दरबार की प्रासंगिकता पर गौर करें तो राजा-महाराजा के दौर में नियमित दरबार लगाकर प्रजा की समस्याओं पर मंथन कर उसे न्याय दिया जाता था। चतुर राजा तो वेश बदलकर रियासत में घूमते थे ताकि अपने आचार-व्यवहार तक का पता करते थे।

झारखंड

सराहनीय पहल

> झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति से बेहतरी के नए दरवाजे खुल सकते हैं


सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। फाइल

राज्य में नई औद्योगिक निवेश नीति के माध्यम से न सिर्फ उद्योगों को निवेश के अवसर दिए गए हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और बेहतरी के लिए नए दरवाजे भी खुले हैं। ऐसे ही क्षेत्रों में शिक्षा भी शुमार है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करने के साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में निवेश पर बेहतर रिटर्न का भरोसा भी दिलाया है। नीति के अनुसार योजनाएं धरातल पर उतरीं तो जाहिर तौर पर आनेवाले कुछ वर्षों में झारखंड में विश्वस्तरीय प्राइवेट विश्वविद्यालय खुलने की संभावनाए बनेंगी।

विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए बनी नैक की कमेटी से ए प्लस-प्लस रैंकिंग मिलने की स्थिति में सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को 12 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव दने की बात कही है। हालांकि इसके लिए कई शर्तें भी लगाई गई हैं। शर्तें पूरी हुईं तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि झारखंड में विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों के लिए भविष्य के द्वार खुलते दिखेंगे। नई औद्योगिक एवं निवेश नीति परंपरागत उद्योगों के साथ नए क्षेत्रों में निवेश के लिए भी उद्यमियों को आकर्षित करती दिख रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और उनकी लागत के हिसाब से उन्हें इंसेंटिव भी देने का भरोसा दिलाया गया है। कोरोना संक्रमण के बाद ऐसे अस्पतालों की आवश्यकता राज्य में बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव की प्रतियोगिता शिक्षा के नए युग का सूत्रपात कर सकती है। यह वक्त के साथ लिया गया अच्छा फैसला है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में कार्यरत बड़े औद्योगिक घरानों के लिए झारखंड में निवेश की संभावनाएं दिखाई गई हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सामान्य शिक्षण के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विशेषज्ञता के साथ मैदान में उतर सकती है। इससे आनेवाले दिनों में राज्य में प्राइवेट मेडिकल कालेज खुलने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। सरकार ने छोटे उद्यमियों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। यह कोशिश सफल हुई तो आने वाले दिनों में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है।

उत्तराखंड

प्राकृतिक आपदा से निपटने की चुनौती

प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून की चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं। रविवार को कुमाऊं में बारिश और भूस्खलन से चार की जान चली गई, जबकि दो पर्यटक लापता हैं। फिलहाल मौसम के मिजाज में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद भी नहीं है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में मलबा आने से कई जगह संपर्क मार्ग भी बंद हैं और बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ही चमोली व पिथौरागढ़ जिलों में चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्गों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यह सही है कि अभी चार धाम यात्रा पर रोक है, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। ऐसे में पर्यटक स्थलों में सुरक्षा के इंतजाम पर फोकस करना भी जरूरी है। जाहिर है इन हालात में आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में पिछले माह 13 जून को मानसून सक्रिय हो गया था। बीते एक माह के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो प्रदेश में इस अवधि में 277 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्यतौर पर यह आंकड़ा 252 मिमी होना चाहिए। इस तरह से प्रदेश में बारिश सामान्य से दस फीसद ज्यादा है। हालांकि दस फीसद बारिश का कम अथवा ज्यादा होना सामान्य ही माना जाता है, लेकिन इसी अवधि में जिलों की स्थिति पर गौर किया जाए तो हकीकत समझ में आ जाती है। प्रदेश में चमोली और बागेश्वर में सर्वाधिक बारिश रिकार्ड की गई। बीते एक माह में चमोली में 162 और बागेश्वर में 143 फीसद बारिश अधिक हुई है। यानी सामान्य से दोगुने से भी अधिक। इन्हीं दोनों जिलों में नुकसान भी सबसे अधिक देखने को मिला है। एक से सात जुलाई के बीच प्रदेश में बारिश का आंकड़ा बेहद कम रहा है। इस अवधि में 66 फीसद कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। हालांकि आपदा से निपटने के लिए सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक हेलीकाप्टर की तैनाती की है। इसके अलावा हर तरह की तैयारी का भी दावा किया जाता रहा है, लेकिन आमतौर पर देखने में आया है कि अधिकारियों की ओर से किए जाने वाले ये दावे धरातल पर खरे नहीं उतरते। हर बार मानसून से पहले सड़कों पर ब्लैक स्पाट और भूस्खलन जोन को चिह्नित करने की रवायत निभाई जाती है, लेकिन इनके ट्रीटमेंट को लेकर उदासीनता ही दिखाई देती है। इसी तरह भूस्खलन प्रभावित गांवों के विस्थापन को लेकर भी सरकारी स्तर पर बरती जा रही सुस्ती, आसन्न संकट को और गहरा कर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम कर इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है।

> मानसून सीजन के लिए तैयारियों को और पुख्ता करने की जरूरत है। विशेषकर सड़कों के किनारे उभरे भूस्खलन जोन का स्थायी उपचार किया जाना चाहिए

जागरण विशेष

ट्रैप क्राप से इल्लियों को दिया चकमा, हुआ दोगुना मुनाफा

इंदौर के सिमरोल गांव में किसान लेखराज पाटीदार ने फसल बचाने के लिए किया अनूठा उपाय

विपिन अवस्थी • इंदौर


ढेंचा के पौधों के किनारे एक फीट की दूरी पर लगे हल्दी के पौधे • सौ.- लेखराज

आमतौर पर किसान फसल को खरपतवार और इल्लियों (कैटरपिलर) से बचाने के लिए कई जतन करते हैं। सामान्य खेती में तो कीटनाशक इनसे छुटकारा दिला सकता है लेकिन जैविक खेती में इसका उपयोग नहीं होता। इंदौर के पास स्थित सिमरोल गांव के किसान लेखराज पाटीदार ने इल्लियों को चकमा देने के लिए अनूठा प्रयोग किया। हल्दी की फसल को इल्लियों से बचाने के लिए उन्होंने ट्रैप क्राप का सफल इस्तेमाल किया।

ट्रैप क्राप के तहत ढेंचा (एक तरह का खरपतवार) को पहले खेत में फसल की तरह लगाया और फिर उसके बीच हल्दी बोई। ढेंचा की पत्तियां काफी मुलायम होती हैं। इल्लियां इन्हें पसंद करती हैं और पास ही उगी कड़े पत्तों वाली हल्दी को छोड़ देती हैं। इस प्रयोग से लेखराज को एक एकड़ हल्दी की खेती में पहले के मुकाबले अधिक मुनाफा हुआ।

पहले हासिल की तकनीकी जानकारी: लेखराज ने बताया कि उन्होंने पहले एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा) से तकनीकी जानकारी हासिल की। जब ट्रैप क्राप तकनीक का पता चला तो इसका उपयोग किया। फसल को जैविक खाद दी गई। कृषि महाविद्यालय के विज्ञानी मुकेश सक्सेना ने बताया कि ढेंचा को ट्रैप क्राप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह इल्लियों व अन्य नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैज्ञानिक भी इसे जैविक खेती के लिए उपयोगी मानते हैं। सिर्फ हल्दी नहीं, परंपरागत फसलों में भी इस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। मसालों और सब्जी की फसल के लिए तो यह पद्धति वरदान से कम नहीं है। अब क्षेत्र के 50 अन्य किसानों ने भी इस पद्धति से खेती करने में रुचि दिखाई है।

खेत में ही होता है हरित खाद का उत्पादन: ढेंचा को हरित खाद के रूप में जाना जाता है। यह केंचुओं के लिए भी लाभदायक होता है। कीटनाशकों से इल्लियों के साथ फसल के लिए फायदेमंद कीट (मित्र कीट) भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ढेंचा का प्रयोग बेहतर है। मुकेश सक्सेना बताते हैं कि ढेंचा इल्लियों को भोजन उपलब्ध कराता है। उनकी संख्या बढ़ी तो संभव है कि वे ढेंचा को खत्म करने के बाद मुख्य फसल पर हमला कर दें। ऐसे में मित्र कीट उन्हें खाकर नियंत्रित करते हैं।

लागत कम, फायदा अधिक

किसान लेखराज को एक एकड़ में हल्दी की खेती में ट्रैप क्राप का प्रयोग करने से न केवल इल्लियों के प्रकोप से राहत मिली बल्कि कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिला। खेत तैयार करने और फसल लगाने में करीब 73 हजार रुपये की लागत आई। जैविक फसल की बिक्री के बाद उन्हें करीब एक लाख 64 हजार रुपये का मुनाफा हुआ। यह मुनाफा रासायनिक खेती के मुकाबले लगभग दोगुना रहा। दरअसल रासायनिक खेती में अनुमानित लागत भी अधिक होती है और फसल की बिक्री जैविक के मुकाबले आधी कीमत पर होती है।


लेखराज



लेखराज ने जिस तरह ट्रैप क्राप से हल्दी की खेती की है, वह अनूठा प्रयोग है। हल्दी के साथ ढेंचा का प्रयोग किसान ने पहली बार किया है, जो बहुत ही कारगर साबित हुआ। इससे खेती भी अच्छी हुई और उन्हें लाभ भी अधिक हुआ है।
शर्ली थामस, परियोजना संचालक, एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा) इंदौर

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

हत्या, लूट और ब्लास्ट के मामले को सुलझाने वाले विक्टर को गन सैल्यूट

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन


स्निफर डाग विक्टर की फाइल फोटो। सौ. पुलिस

वर्ष 2014 में जालंधर जिले में पीएपी फिल्लौर अकादमी से ट्रेनिंग के बाद तरनतारन में तैनात हुए डाग स्क्वायड विक्टर दुनिया को अलविदा कह गया। पिछले साढ़े सात साल से जिला तरनतारन में तैनात विक्टर ने कई मामलों की तफ्तीश में अहम भूमिका निभाई थी। विक्टर को पुष्प अर्पित करने के बाद पुलिस लाइन में दफनाया गया। पंजाब पुलिस के तीन जवानों ने हथियार उल्टे करके विक्टर को अंतिम विदाई दी।

साढ़े आठ वर्ष के एक्सप्लोसिव स्पेशलिस्ट स्निफर डाग विक्टर की दस से अधिक हत्याएं, 14 लूटमार व डकैती की वारदात को हल करवाने, सितंबर 2019 में गांव पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट के मामले को सुलझाने में अहम भूमिका रही थी। विक्टर एक वर्ष की आयु में 2014 में महाराजा रणजीत सिंह अकादमी फिल्लौर से ट्रेनिंग लेकर तरनतारन पुलिस के डाग स्क्वायड में शामिल हुआ था। तरनतारन में वीआइपी के अलावा मेला ड्यूटी में उसकी अहम भूमिका रह चुकी है। राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व डीजीपी समेत अन्य वीवीआइपी की आमद के मौके पर भी विक्टर अपनी जिम्मेदारी निभा चुका है। विक्टर के असाधारण कौशल के कारण उसके कार्यकाल के दौरान जिले में कोई आतंकी वारदात नहीं हुई। एसएसपी ध्रुमन एच निंबाले ने विक्टर को दफनाए जाने की वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करके उसकी साढ़े सात वर्ष के कार्यों को याद किया और श्रद्धांजलि भेंट की। एसएसपी निंबाले ने बताया कि विक्टर की सेवाओं को पंजाब पुलिस द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा।

जल संरक्षण ने डाली जान, पिस्टा गांव की सूखी धरती पर लहलहाया धान

शैलेंद्र शर्मा, बांदा


फार्म हाउस में धान की रोपाई कराते किसान विज्ञान शुक्ला। सौ. स्वयं

30 फीट से कम बोरिंग में हैंडपंपों से फूटती है जलधार, उगाते सब्जियां, पिस्टा गांव में नौ तालाब बचा रहे बूंद-बूंद पानी

2000 बीघा में होती है धान की खेती

4900 बीघा है गांव में कृषि क्षेत्र

जल सहेजने से पड़ने वाला फर्क देखना है तो बुंदेलखंड के बांदा जिले के बबेरू ब्लाक के पिस्टा गांव घूम जाइए। यहां कभी सूखी रहने वाली धरती पर अब धान की फसल लहलहा रही है। नौ तालाबों के बूंद-बूंद पानी बचाने से जलस्तर बढ़ा है। इससे 30 फीट से कम बोरिंग में ही हैंडपंपों की धार फूट पड़ती है। तमाम किसान सब्जियां उगाने लगे हैं।

बुंदेलखंड अब बदल रहा है। सूखे का दाग मिट रहा है। यहां जल संरक्षण की दिशा में काम से जल योद्धा उमाशंकर पांडेय के गांव जखनी ने देश भर में 'खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' की अलख जगाई तो बबेरू ब्लाक के पिस्टा गांव निवासी संकटा प्रसाद त्रिपाठी ने सूरत बदलने की ठानी। उनकी मुहिम में बांदा में महज 17 माह तैनात रहे तत्कालीन डीएम हीरालाल की प्रेरणा कारगर साबित हुई। उनके कुआं-तालाब जियाओ अभियान के तहत हैंडपंपों से बर्बाद होने वाले पानी को सहेजकर हर तरफ हरियाली लाई गई। 40 साल से जहां कभी धान की खेती नहीं हुई, लेकिन अब वह मुख्य उपज है। संकटा प्रसाद गांव के प्रधान बने, तभी जलसंरक्षण मुहिम से जुड़े। उन्होंने पानी से समृद्धि का मंत्र समझा। अब वह प्रधान भले ही नहीं हैं, लेकिन गांव की बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। वह बताते हैं, गांव में पूर्वजों के नाम पर तालाब थे, गंदगी थी, कुछ निष्प्रयोज्य होने के कगार पर थे। कुछ की श्रमदान तो बाकी की मनरेगा से सफाई कराई। सरकारी सहायता तो नहीं ली पर ग्राम पंचायत की आय जरूर बढ़ाई और गांव की बेहतरी के लिए जतन शुरू किया। इसी बीच 'कुआं-तालाब जियाओ' अभियान चलाया तो उससे लोग जुड़े। गांव के कुओं का पूजन और तालाबों की तस्वीर बदलनी तेज हो गई। वह बताते हैं कि हैंडपंपों के किनारे सोख्तापिट बनवाए तो पानी गड्ढों में जाने लगा। इससे गंदगी दूर हुई और जल संरक्षण से बेहतरी आने लगी।

पांच साल में नहीं कराना पड़ा कोई हैंडपंप री-बोर : संकटा बताते हैं, पांच साल की प्रधानी के दौरान पिस्टा गांव में एक भी हैंडपंप का री-बोर नहीं कराना पड़ा। वह भी तब, जब गांव में कुल 115 हैंडपंप हैं, जिनमें 62 सार्वजनिक स्थानों पर लगे हैं। गांव में सिद्धबाबा, बेचू, फकीर बाबा, हीरा, डेबरा, महेश्वरी देवी, पाठक, पोखरी व सुम्मा तालाब समेत नौ तालाब हैं। हीरा तालाब की सूरत श्रमदान से बदल गई। इलाहाबाद विवि के शोध छात्र रामबाबू तिवारी बताते हैं, कुआं तालाब-जियाओ अभियान में हैंडपंपों के पास गड्ढे खोदने से पानी की बर्बादी रुकी है। करीब आठ सौ तालाब खोदे गए। अब मुहिम को और तेज करने पर काम हो रहा है।

बुंदेलखंड के गांव होंगे मॉडल: वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एडिशनल डायरेक्टर आइएएस हीरालाल ने बांदा जिले में तैनाती के दौरान जल संरक्षण की दिशा में खूब काम किया। अब उन्होंने विलेज मेनीफेस्टो मॉडल तैयार किया है। इसके तीन उद्देश्य हैं। गांव और वहां के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीसी) के जरिए गांव को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि को कृषि व्यापार में बदलकर एफपीओ के जरिए किसानों का सपना साकार करना है। प्रत्येक गांव में पांच से 10 चेन एजेंट विकसित करने और कृषि को कृषि व्यापार में बदलने की सोच पर काम हो रहा है।

तन, मन और धन से राष्ट्र निर्माण में जुटें : भागवत

- व्यवस्था में लगे स्वयंसेवकों व डीआरआइ कार्यकर्ताओं को सेवाभाव की दी सीख
- मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे हुए रवाना, सतना से ट्रेन से पहुंचेंगे नागपुर

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में व्यवस्था संभालने में लगे स्वयंसेवकों से कहा कि तन, मन व धन से राष्ट्र निर्माण में जुटें। इसके बाद शाम साढ़े पांच बजे वह नागपुर के लिए रवाना हो गए। चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआइ) के प्रकल्प आरोग्यधाम में नौ से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का सोमवार को समापन हो गया। इसके बाद देर शाम संघ प्रमुख ने संतों से मुलाकात की थी। उस दौरान कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। चार दिन की बैठक का सार संघ के शताब्दी 2025 तक गांव-गांव तक शाखाओं को पहुंचाना रहा। इसको लेकर अखिल भारतीय कमेटी, क्षेत्र व प्रांत प्रचारकों के साथ भी मंथन हुआ। हालांकि, मुख्य फोकस संगठन रहा। मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे नागपुर रवाना होने से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक की व्यवस्था में लगे करीब 70 स्वयंसेवकों और डीआरआइ कार्यकर्ताओं को सेवाभाव का पाठ पढ़ाना नहीं भूले। दिन में 11 बजे स्वयंसेवकों के साथ परिचय बैठक की। करीब एक घंटे एक-एक स्वयंसेवक से विस्तार से परिचय लिया और उनकी समस्याएं जानी। शाम चार बजे डीआरआइ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी प्रचारक बन जाए तो राष्ट्र निर्माण को लेकर मिली जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करें।

रात में ही निकल गए संघ सरकार्यवाह: सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को मध्य क्षेत्र की होने वाली बैठक में 15 जुलाई तक यहां रुकना था, लेकिन अचानक काम आने से वह सोमवार की रात में ही क्षेत्र प्रचारक अनिल के साथ नागपुर चले गए।

ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों मे अब भी संस्कार जीवित : मोहन भागवत ने दीनदयाल शोध संस्थान के सभी प्रकल्पों के प्रभारियों व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन अभियान का काम देख रहे समाजशिल्पी दंपतियों को भी संबोधित किया। कहा कि ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में संस्कार जीवित हैं। उन्होंने वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदली परिस्थितियों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि कुछ तो समय बदलता है। उसके अनुसार सबको बदलना होता है। उन्होंने कहा कि काल की कसौटी पर जो आयुर्वेद में है, वह एलोपैथी में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि एलोपैथी ठीक नहीं, उसका भी महत्व है।

अब मध्य क्षेत्र के प्रांत व क्षेत्र प्रचारक मंथन के लिए चित्रकूट में जुटे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : चार दिन तक मंथन कर संघ के अखिल भारतीय टोली के पदाधिकारी, प्रांत व क्षेत्र प्रचारकों के लौटने के बाद अब चित्रकूट में मध्य क्षेत्र (महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्य भारत व मालवा प्रांत) के पदाधिकारी मंथन करने पहुंच गए हैं। पूर्व सरकार्यवाह भय्या जी जोशी व सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य इस बैठक में शामिल होकर उन्हें सीख देंगे। डीआरआइ के प्रकल्प आरोग्यधाम परिसर में 13 जुलाई को रात 10 बजे मध्य क्षेत्र के प्रांत व क्षेत्र प्रचारकों की पहली बैठक हुई। इसके बाद 15 जुलाई तक अलग-अलग समय होने वाली बैठकों में पदाधिकारी शामिल होंगे।

सेवा कार्य से निकलेगी संघ के विस्तार की राह

- सितंबर से ढाई लाख स्थानों तक पहुंचेंगी स्वयंसेवकों की टोलियां
- संघ के सेवार्थियों की मौजूदगी से बनेगी शाखाओं के लिए जमीन

राजीव द्विवेदी, चित्रकूट

प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में चार दिन तक चली प्रांत प्रचारक बैठक में संघ कोरोना महामारी के लिए चिंतित दिखा तो नए लक्ष्यों पर भी पैनी निगाह रही। वहीं, कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी में शताब्दी वर्ष से पहले देश के हर गांव तक संघ की पहुंच बनाने की राह भी निकाल ली। संभावित तीसरी लहर से पहले ही संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की टोलियां ढाई लाख गांवों और बस्तियों में पहुंचेंगी। संघ की देश में अभी 55 हजार से अधिक शाखाएं हैं, अब यह गतिविधियां ढाई लाख जगहों पर होंगी। इससे जाहिर है कि सेवा के साथ संघ के विस्तार की राह भी खुलेगी।

देश के करोड़ों लोगों से सीधा जुड़ाव रखने वाले संघ की बुनियाद उसकी शाखाएं हैं। खेल, योग, वंदना और सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा-परिचर्चा जैसी शाखा की सामान्य सी लगने वाली गतिविधियों से ही राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक तैयार होते हैं। चित्रकूट में चार दिन चली प्रांत प्रचारक बैठक में शाखाओं को शताब्दी वर्ष (27 सितंबर, 2025) तक गांव-गांव में पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कोरोना काल में संघ के सेवा कार्य की फिक्र भी की गई। वर्तमान हालात में संगठन का विस्तार और कोरोना महामारी में सेवा कार्य की तैयारी जैसे दोनों विषय भले अलग लगें, पर संघ को समझने वाले जान रहे हैं कि हर गांव तक पहुंच बनाने को संकल्पित संघ की दोनों विषयों को लेकर की जा रही फिक्र में संगठन के विस्तार का रास्ता भी है। वह समझ रहे हैं कि अपने सेवा कार्य से ही आकार पाते रहे संघ के स्वयंसेवक जब ढाई लाख गांव और बस्तियों तक पहुंचेंगे तो उनकी सामान्य दिनचर्या में शामिल शाखा का संचालन भी वहां होगा। संघ के निस्वार्थ सेवार्थियों को लोग समझेंगे तो शाखाओं का विस्तार भी तय है।

सितंबर से विस्तार की शुरुआत: कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए संघ के युवा स्वयंसेवकों का अगस्त में प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। उसके बाद सितंबर में उनकी टोलियां सही वक्त पर कोरोना से बचाव की जरूरी जानकारी देने को गांव और बस्तियों में पहुंचेंगी। संघ जनजागरण अभियान में कई स्वयंसेवी लोगों और संस्थाओं को भी जोड़ेगा। इससे संघ सितंबर में सेवा और संगठन विस्तार की बड़ी मुहिम की शुरुआत करेगा।

2015 से 2019 के बीच दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में रिसर्च पेपर (शोध-पत्र) का प्रकाशन 21 फीसद बढ़ा है। 28.6 फीसद के साथ यूरोपीय यूनियन सबसे आगे है।

भारत समर्थक देउबा ने संभाली नेपाल की कमान

सत्ता परिवर्तन

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया प्रधानमंत्री
- नवंबर में होने वाले संसदीय चुनाव को भी किया गया स्थगित
- 30 दिन के अंदर संसद में साबित करना होगा विश्वास मत


नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की फाइल फोटो। रायटर

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने देश की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उनको प्रधानमंत्री पद पर मंगलवार को नियुक्त कर दिया। देउबा की यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। पांचवीं बार नेपाल के पीएम बनने वाले देउबा को भारत समर्थक माना जाता है। इस बीच, इस हिमालयी देश के चुनाव आयोग ने 12 और 19 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनावों को स्थगित कर दिया।

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें गत 21 मई को उन्होंने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था। साथ ही 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी। कोर्ट ने संसद को बहाल करने के साथ विपक्षी नेता देउबा को मंगलवार तक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था। राष्ट्रपति भंडारी के निजी सचिव भेश राज अधिकारी ने पत्रकारों को बताया, 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत राष्ट्रपति ने देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।' 75 वर्षीय देउबा को संविधान के प्रविधानों के तहत संसद में 30 दिनों के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी का निचले सदन को भंग करने का फैसला असंवैधानिक था। पीठ ने 18 जुलाई को शाम पांच बजे तक प्रतिनिधि सभा का सत्र बुलाने का भी आदेश दिया है।

ओली ने दिया इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट पर लगाया आरोप : समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है।' हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट पर विपक्षी दलों के पक्ष में जानबूझकर फैसला सुनाने का आरोप भी लगाया। ओली ने कहा कि फैसले का दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।

संदेह दूर करने में मिली मदद : पूर्व में चार बार नेपाल के पीएम का पदभार संभाल चुके देउबा और उनके राजनीतिक दल को भारत का पुराना हितैषी माना जाता है। उन्होंने जब भी सत्ता संभाली है, तब दोनों देशों के रिश्तों में संदेह को दूर करने में काफी मदद मिली है। जबकि ओली की सरकार बनने के बाद नेपाल में चीन की सक्रियता और बढ़ गई।

चार बार रह चुके हैं पीएम

देउबा पिछली बार जून 2017 से फरवरी 2018 तक प्रधानमंत्री रहे। वह इस पद पर जून 2004 से फरवरी 2005, जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 और सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक भी रह चुके हैं।

फ्रांस में अमेरिकी कंपनी गूगल पर 4,400 करोड़ रुपये का जुर्माना

- समाचार प्रकाशकों के भुगतान विवाद में हुई यह कार्रवाई

पेरिस, एपी : फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने मंगलवार को गूगल पर 50 करोड़ यूरो (करीब 4,400 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाने का एलान किया। यह जुर्माना फ्रांसीसी प्रशासकों के साथ भुगतान विवाद में लगाया गया है। ये प्रकाशक चाहते हैं कि गूगल उनके समाचारों के इस्तेमाल के लिए भुगतान करे।

फ्रांसीसी प्राधिकरण ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर गूगल ने समाचार प्रकाशकों को भुगतान करने के संबंध में दो माह के भीतर प्रस्ताव पेश नहीं किया तो उस पर रोजाना नौ लाख यूरो (करीब आठ करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अमेरिका की इस दिग्गज कंपनी ने फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए एक बयान में कहा 'समाधान निकालने के लिए अच्छी नीयत के साथ बातचीत की जा रही है।


दिग्गज टेक कंपनी मुश्किल में। फाइल

कुछ प्रशासकों के साथ समझौते के करीब भी हैं।' प्राधिकरण ने इस वर्ष की शुरुआत में गूगल को आदेश दिया था कि वह समाचार प्रकाशकों के साथ तीन महीने के अंदर बातचीत शुरू करे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उस पर मंगलवार को यह जुर्माना लगाया गया।

जून में भी लगा था जुर्माना

फ्रांसीसी प्राधिकरण ने गत जून में भी गूगल पर 26.8 करोड़ डालर (करीब 1,950 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था। उस समय यह कार्रवाई आनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई थी

टेक कंपनियों पर बढ़ रहा दबाव

गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनियों पर इस बात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा है कि वे समाचार प्रकाशकों को भुगतान करें। प्रकाशकों को भुगतान को लेकर यूरोपीय यूनियन भी दबाव बना रही है।

न्यूज गैलरी

नेत्रहीन चीनी विद्रोही को मिली अमेरिकी नागरिकता

वाशिंगटन : वर्ष 2012 में चीन से भागकर अमेरिका पहुंचे नेत्रहीन चीनी विद्रोही चेन गुआंगचेन को अमेरिकी नागरिकता मिल गई है। अमेरिकी नागरिक बने चेन ने कहा, इस आजाद देश ने उनका स्वागत किया है, इसके लिए वह बेहद आभारी हैं। चेन के वकील व बेलाइज के पूर्व अमेरिकी राजदूत जार्ज ब्रूनो ने कहा, चीन में नजरबंदी से लेकर अमेरिकी नागरिक बनने तक का यह 15 सालों का लंबा सफर है। चीन की एक बच्चे की नीति के चलते चेन को अवैध रूप से बंदी रखा गया। जेल में चार साल काटने के बाद उस पर झूठे आरोप लगाए गए। वर्ष 2012 में वह सुरक्षा घेरा तोड़कर अपने घर से फरार हो गए और अमेरिकी राजनयिकों की शरण में चले गए। गत वर्ष चेन ने रिपब्लिकन नेशनल कंवेंशन को संबोधित किया था। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन की आक्रामक नीति को रोकने के अभियान का भी समर्थन किया था। (एपी)

चीन-अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता में ताइवान पर बढ़ रहा संकट

टोक्यो : जापान ने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्विता के कारण पूर्वी एशिया में सैन्य तनाव बढ़ने लगा है। इससे शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है। जापान के रक्षा क्षेत्र को लेकर जारी किए गए श्वेतपत्र में यह बात कही गई है। जापान ने कहा है कि इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। रक्षा समीक्षा को मंगलवार को जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपनी मंजूरी दी है। ज्ञात हो, ताइवान के आसपास के क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां जापान के लिए भी चिंता का कारण हैं। ताइवान जापानी द्वीपसमूह के पश्चिमी छोर पर स्थित ओकिनावा के बिल्कुल नजदीक है। (रायटर)

प्रदर्शनों के लिए अमेरिका जिम्मेदार : क्यूबा

हवाना : क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुइल डायज कैनल ने देश में सप्ताहांत हुए ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। कैनल ने कहा, अमेरिका उनके देश में सामाजिक अस्थिरता लाना चाहता है। साथ ही क्यूबा सरकार ने कुछ हाई प्रोफाइल विरोधियों समेत करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते हजारों क्यूबा नागरिकों ने वामपंथी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध-प्रदर्शन किया था। हवाना से लेकर सैंटियागो तक भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की थी। माना जाता है कि इंटरनेट मीडिया के जरिये ही इतने बड़े जमावड़े हो सके। देश में अब तक सौ से अधिक पत्रकारों, प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। (आइएएनएस)

काबुल एयरपोर्ट को लेकर तालिबान की तुर्की को धमकी

कंधार में मारकाट जारी, गजनी में जंग तेज, कब्जे की लड़ाई में कई नागरिक भी मारे गए

राजधानी काबुल में शक्तिशाली बम विस्फोट, चार नागरिकों की मौत

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान में तालिबान का गजनी और कंधार पर कब्जे के लिए सुरक्षा बलों से भीषण संघर्ष हो रहा है। इस बीच तालिबान ने काबुल में भी अफगान सुरक्षा बलों को कमजोर करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। उसने तुर्की को धमकी है कि यदि उसने अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के बाद काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा अपने हाथ में ली तो गंभीर खामियाजा भुगतेगा।

तुर्की अमेरिका के साथ वार्ता कर सेना वापसी के बाद काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा ले रहा है। इस मुद्दे पर तालिबान ने तुर्की को सीधे धमकाना शुरू कर दिया है। तालिबान चाहता है कि काबुल में वह बिना किसी विदेशी सेना के हस्तक्षेप के सीधे अफगान सुरक्षा बलों से मोर्चा ले।

इधर कंधार के ताजा हालात के संबंध में वहां के प्रांतीय परिषद के सदस्य अताउल्लाह अत्ता ने जानकारी दी है। कंधार में कब्जे को लेकर भीषण संघर्ष चल रहा है। यहां तालिबान ने जेल में घुसने की कोशिश की। उसे वहां से खदेड़ दिया गया। हिंसा के हालात से डरे सैकड़ों परिवार कंधार से भाग गए हैं। यहां पिछले 24 घंटों के दौरान आठ नागरिकों की मौत हो गई, तीस से ज्यादा घायल हो गए हैं।

गजनी के चारों तरफ तालिबानी आतंकी फैले हुए हैं। आतंकियों ने रात भर गजनी पर हमले किए। यहां भी मारकाट चल रही है। इधर एएनआइ के अनुसार काबुल में एक शक्तिशाली बम विस्फोट में चार नागरिकों की मौत हो गई। पांच लोग घायल हो गए।

हवाई हमलों में 29 तालिबानी आतंकी मारे गए : आइएएनएस के अनुसार जौजान प्रांत में तालिबान के छिपे हुए अड्डों पर हवाई हमले किए गए। हमले में 29 आतंकवादी मारे गए। आइएएनएस के अनुसार बदख्शान प्रांत के कुरान-वा-मुंताज जिले को सुरक्षा बलों ने तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया है।

अफगानिस्तान का विकास बजट अब खर्च होगा रक्षा पर : एएनआइ के अनुसार अफगानिस्तान में हिंसा के कारण राजस्व में भारी कमी के कारण वित्त मंत्रालय ने विकास कार्यों के लिए आवंटित बजट को रक्षा पर खर्च करने की सहमति दे दी है। पहचान पत्र, वीजा और सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने का काम जारी रहेगा। अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धन को अब रक्षा परियोजनाओं में लगाया जा रहा है। ज्ञात हो कि देश के कई हिस्सों पर तालिबान का विस्तार होने के बाद छह सीमा शुल्क कार्यालय भी उसके कब्जे में आ गए हैं।

पाकिस्तान के कहने पर चल रहा है तालिबान : एएनआइ के अनुसार अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान पाक सेना की विशेष यूनिट के इशारे पर हिंसा कर रहा है।

हिंसाग्रस्त देश मानवीय संकट के कगार पर : रायटर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों के हाई कमिश्नर (यूएनएचसीआर) के प्रवक्ता बाबर बलूच ने कहा कि शांति वार्ता के विफल होने से देश में शरणार्थियों के लिहाज से गंभीर समस्या होने वाली है। देश मानवीय संकट के कगार पर है।

कंधार में भारतीय दूतावास पर कब्जे का तालिबान का दावा झूठा : आइएएनएस के अनुसार कंधार में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कब्जे के संबंध में तालिबान ने झूठ फैलाया है। कंधार के गवर्नर के प्रवक्ता बहीर अहमदी ने टीवी चैनल को बताया कि कंधार में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य है। भारत का वाणिज्य दूतावास पूरी तरह सुरक्षित है और कार्य कर रहा है। उस पर तालिबान का कब्जा करने की बात निराधार है। भारतीय विदेश मंत्रालय सूत्रों के अनुसार दूतावास में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं जारी हैं।


कंधार में तालिबान का सामना कर रहे अफगान स्पेशल फोर्स के जवान अपने बेस कैंप में पानी से मुंह धोकर थकान मिटाने का प्रयास करते हुए। रायटर

घरों पर कब्जा और स्कूलों में आग लगा रहा तालिबान

एपी के अनुसार पिछले 15 दिनों में तालिबान ने पांच हजार से ज्यादा परिवारों को जिलों से खदेड़ दिया है। तालिबान उनके घरों पर कब्जा कर रहा है। यही नही तालिबान स्कूलों में भी आग लगा रहा है। हजारों परिवार अपने घरों से भागकर 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुली जगहों में रहने को मजबूर हैं।

काबुल में अमेरिकी राजनयिकों को तालिबान का कोई खौफ नहीं

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- आंतकी संगठन के बढ़ते प्रभाव के बीच दूतावास में चल रहा सामान्य कामकाज

वाशिंगटन : अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से विस्तार कर रहा है। एक के बाद एक जिले पर कब्जे के साथ ही अब उसने गजनी और कंधार पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में भी काबुल के अमेरिकी दूतावास में कोई खलबली और खौफ नहीं है। कामकाज पूरी तरह सामान्य रूप से चल रहा है। यहां दुभाषियों और अन्य अफगान सहयोगियों के वीजा जारी करने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया गया है।

रविवार से यहां के अधिकारियों ने वीजा संबंधी साक्षात्कार लेने की तैयारी कर ली है। यहां हर रोज वीजा पाने वाले दो सौ लोगों का साक्षात्कार लिया जाएगा। दूतावास में अधिकारियों की सामान्य बैठक भी शुरू हो गई हैं। अमेरिकी मिशन के सह-प्रमुख स्काट वेनहाल्ट ने बताया कि कुछ लोग मेरे पास आए और कहा कि क्या हमारी नौकरी अब भी चलती रहेगी। मैंने कहा, हम पक्के इरादे के साथ दूतावास खोले हैं और ठीक से चलाएंगे। वेनहोल्ड ने कहा कि यहां के अमेरिकी अधिकारियों को यह विकल्प दिया था कि वे जोखिम को लेकर अपना पद छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ऐसा नहीं किया।

अमेरिका की नब्बे फीसद से ज्यादा सेना यहां से जा चुकी है। सोमवार को यहां तैनात सेना के आखिरी जनरल स्काट मिलर ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। अमेरिका के काबुल दूतावास में 1400 अमेरिकी अधिकारी हैं और यहां चार हजार कर्मचारी काम करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए 650 से 1000 तक अमेरिकी सैनिक तैनात रहेंगे।

जुमा मामले में शॉपिंग मॉलों में लूट और भगदड़, 10 मरे

केपटाउन, रायटर : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के जेल जाने के विरोध में दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी क्रम में ग्वाटेंग प्रांत स्थित एक शॉपिंग मॉल में मंगलवार को जमकर लूटपाट व तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिस कार्रवाई के दौरान मची भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। इसी तरह डरबन के भी गोदामों और सुपर मार्केटों में प्रदर्शनकारियों ने भारी लूटपाट और तोड़फोड़ की है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी हिंसा पिछले कई सालों में नहीं हुई है।

दक्षिणी अफ्रीकी प्रांत ग्वाटेंग के प्रधानमंत्री डेविड मखुरा ने बताया कि स्वेटो शॉपिंग मॉल में सोमवार शाम को लूटपाट के दौरान भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई। अब तक दस लोगों के शव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा में अब तक कुल 45 लोग मारे जा चुके हैं। गरीबी और असमानता पर लोगों के गुस्से के चलते कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। सरकार के मंत्री भेकी सेले ने कहा, कोई कितना भी नाखुश हो या उसके निजी हालात कैसे भी हों, इससे उसे लूटपाट करने का हक नहीं मिल जाता है।

ज्ञात हो, पूर्व राष्ट्रपति जुमा को अदालत की अवमानना में जेल भेजा गया है। इसी के विरोध में हिंसा भड़क गई है। लोगों में कोविड-19 के चलते लगाए गए प्रतिबंधों को भी लेकर नाराजगी है क्योंकि उन्हें भारी आर्थिक हानि हुई है।

बीजिंग में रिकार्ड बारिश, पांच की मौत, 10 लापता

बीजिंग, एएनआइ : चीन की राजधानी बीजिंग में तूफानी बारिश हो रही है। भीषण बारिश से पांच लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हो गए हैं। महज 24 घंटे में 198.9 मिमी बरसात हो गई है।

बीजिंग में औसत बारिश 103.9 मिमी दर्ज की गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में औसत बारिश 114.8 मिमी है। एक साल में अब तक की सबसे अधिक बारिश के बाद खेल, सांस्कृतिक, अकादमिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण राजधानी बीजिंग में जनजीवन असामान्य हो गया है। सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऊंची इमारतों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों में ले जाया गया है। हजारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

चीन की राजधानी में रविवार की रात से लगातार बारिश हो रही है। बीजिंग के लोगों ने सोमवार की सुबह आंखें खोलीं तो पूरा शहर झमाझम बरसात में सराबोर था। यह बरसात मंगलवार तक लगातार जारी है।

दुनिया में तेजी से फैल रहा डेल्टा वैरिएंट : डब्ल्यूएचओ

104 देशों में पहुंचा कोरोना का यह वैरिएंट

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेबरेसस ने कहा कि कोरोना का डेल्टा वैरिएंट तेज गति से दुनिया में फैल रहा है। इसी के चलते नए मामलों और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह वैरिएंट 104 देशों में पहुंच चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि विश्वभर में जल्द ही डेल्टा हावी हो सकता है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार चौथे सप्ताह कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चिंता की बात यह है कि दस हफ्ते तक गिरावट के बाद मौत के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा, 'डेल्टा वैरिएंट तेजी से फैल रहा है और नए मामलों और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी का कारण बन रहा है। कोरोना का यह वैरिएंट 104 देशों में पहुंच चुका है और जल्द ही पूरी दुनिया में हावी हो सकता है।'

ब्रिटेन में मिले 34 हजार नए केस : समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, ब्रिटेन में 24 घंटे के दौरान 34 हजार 471 नए मामले पाए गए और छह पीड़ितों की मौत हुई। यह लगातार छठा दिन है, जब 30 हजार से अधिक नए मामले पाए गए। इस देश में डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ गया है।

अमेरिका के 40 प्रांतों में बढ़े मामले : आइएएनएस के मुताबिक, अमेरिका के 40 से ज्यादा प्रांतों में कोरोना के दैनिक मामले बढ़ गए हैं। इस देश में गत एक हफ्ते से रोजाना औसतन 19 हजार 455 मामले मिल रहे हैं। यहां भी डेल्टा वैरिएंट पांव पसार रहा है।

तुर्की में तीन गुना बढ़े डेल्टा के केस

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, तुर्की में भी डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ रहा है। यहां बीते सात दिनों में डेल्टा के मामले करीब तीन गुना बढ़ गए हैं। एक हफ्ते पहले 284 केस थे और अब बढ़कर 750 हो गए हैं।

आइएसआइ ने बलूच नेता का किया अगवा

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान में बलूचों के आए दिन गायब होने वाली वारदात में एक और घटना जुड़ गई है। पाक की राजधानी इस्लामाबाद से लौट रहे बलूच नेता व वकील शकीर का उनके मूल निवास तुरबत से अगवा कर लिया गया। इस घटना में आइएसआइ का हाथ बताया गया है। तमाम लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट डालते हुए पाक एजेंसियों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। बलूचिस्तान के मानवाधिकार संगठन का कहना है कि शकीर का आइएसआइ ने अपहरण किया है, क्योंकि वह मानवाधिकारों के संबंध में सेना के अत्याचार को लेकर मुखर थे। शकीर के परिवार का भी यही कहना है कि उनके अपहरण का कारण भी मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठाना है।

बलूचिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने दावा किया है कि अकेले जून माह में ही यहां 37 से ज्यादा मामले अपहरण के हैं, इनमें से 25 लोगों की हत्या किए जाने की जानकारी है। ज्ञात हो कि पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियां और सेना द्वारा लोगों का अपराधियों की तरह अपहरण किया जाता औप फिर उन पर अत्याचार किया जाता है। कई मामलों में ऐसे लोगों के शव सड़क किनारे पड़े मिले हैं।

इराक के अस्पताल में लगी आग, मृतकों की संख्या 66 पहुंची


दक्षिणी इराक स्थित नसिरियाह शहर के अल हुसैनी टीचिंग अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी आग के बाद एकत्र लोगों की भीड़। एएफपी

बगदाद, रायटर : दक्षिणी इराक के नसिरियाह शहर में स्थित कोविड अस्पताल (कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के लिए) में सोमवार को लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। 100 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं।

दो स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को नसिरियाह शहर के अल हुसैनी टीचिंग अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी आग में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक शार्टसर्किट से आग लगी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण आक्सीजन सिलेंडर का फटना है। बताया जाता है कि 70 बेडों वाले इस वार्ड को तीन महीने पहले ही शुरू किया गया था। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-काधिमी ने आपात बैठक की अध्यक्षता की और दि कार प्रांत के स्वास्थ्य निदेशक को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस मामले में सरकारी जांच भी शुरू हो गई है।

चीन में होटल ढहने से आठ की मौत, नौ लापता

- मलबा हटाने का काम जारी


जियांगसू प्रांत के सूझोऊ शहर में ढह गए होटल के मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मचारी रायटर

नानजिंग, एएनआइ : चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू के सूझोऊ शहर में सोमवार दोपहर एक होटल ढहने से आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। पांच लोगों को निकाल लिया गया है जबकि 23 अब भी फंसे हुए हैं। लोगों को मलबे से निकालने के लिए क्रेन, सीढ़ियों, मेटल कटर्स के साथ ही प्रशिक्षित कुत्तों की भी मदद ली जा रही है।

सिजी कैयुआन होटल सोमवार दोपहर गिर गया था। अधिकारियों ने शुरुआत में कहा कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन बाद में बताया गया कि अभी तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक इस होटल के ढहने की असल वजह सामने नहीं आ पाई है। ट्रैवल साइट सीट्रिप पर इसकी लिस्टिंग के अनुसार, सिजी कैयुआन होटल 2018 में लोगों के लिए खोला गया था और इसमें 54 कमरे हैं।

घटनास्थल से मिली तस्वीरों में नारंगी कपड़े पहने बचावकर्मियों को मलबे के बड़े-बड़े ढेरों पर खड़े हुए देखा जा सकता है। ये लोग मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं।

मानकों में कमी है हादसे की वजह : सूझोऊ की आबादी 1.2 करोड़ है और ये शंघाई के पश्चिम में 100 किलोमीटर दूर स्थित है। सूझोऊ शहर की पहचान इसकी नहरों और शताब्दी पुराने बगीचों के लिए होती है। पिछले मार्च में दक्षिणी चीन के क्वानझोउ शहर में एक क्वारंटाइन होटल के ढहने की वजह से 29 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बाद में पाया कि इमारत की मूल चार मंजिला संरचना में तीन मंजिलों को अवैध रूप से जोड़ा गया था।

गगनचुंबी इमारत को कराया गया खाली

अधिकारियों ने चीन के ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक, दक्षिणी शहर शेनझेन में स्थित एसईजी प्लाजा को मई में खाली करा दिया था। दरअसल एसईजी प्लाजा कई बार हिल गया था। पिछले साल चीन के शांक्सी प्रांत में एक इमारत के ढहने से से 17 लोगों की मौत हो गई थी। चीन में इस तरह के हादसों की एक लंबी लिस्ट है। हालांकि, हाल के समय में चीन की सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है।

हारून सराब ने कहा, हिंदू समुदाय को विश्वास में नहीं लिया गया

प्रथम पृष्ठ से आगे

खैबर पख्तूनख्वा के हिंदू अल्पसंख्यक विद्वान व मानवाधिकार कार्यकर्ता हारून सराब दियाल ने कहा, 'हम शांति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मामला वापस लेने के लिए जो तरीका अपनाया गया वह देश की जिरगा परंपरा के खिलाफ है।' उन्होंने कहा कि नेशनल एसेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अध्यक्ष डा. रमेश के. वांकवाणी के अलावा स्थानीय हिंदू समुदाय को विश्वास में नहीं लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से गलत संदेश गया है। इससे हिंदू समुदाय के वे लोग हतोत्साहित होंगे जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच वहां रहना चाहते हैं।

अमेरिकी डाक्टर निकला हैती के राष्ट्रपति की हत्या का मास्टरमाइंड

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- गिरफ्तार डाक्टर से एजेंसियां कर रहीं पूछताछ, मिली महत्वपूर्ण जानकारी
- राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे लोगों की भी हो रही जांच

बोगोटा : हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे की हत्या में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इस हत्या का मास्टरमाइंड हैती मूल का अमेरिकी डाक्टर 63 वर्षीय इमैनुएल सेनोन है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इमैनुएल ने ही फ्लोरिडा के एक समूह को हत्या का काम सौंपा था। इसके लिए उसने कुछ कोलंबियाई लोगों की भी भर्ती की थी।

हैती के पुलिस प्रमुख लियोन चार्ल्स ने बताया कि इमैनुएल जून में यहां निजी विमान से आया था और उसने पूरी साजिश रची। उसने यहां की एक कंपनी से भी संपर्क किया था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में यह भी देखना शुरू कर दिया है कि पूरी योजना में हैती के सुरक्षा बलों की तो कोई भूमिका नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि किसी सुरक्षाकर्मी को नुकसान पहुंचाए बिना राष्ट्रपति की हत्या और उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

राष्ट्रपति पर हमले के मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड इमैनुएल सेनोन के संबंध में अमेरिका की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां भी जांच कर रही हैं।

ऐसा लगता है कि हमले के लिए भाड़े पर लाए हत्यारों का इमैनुएल ने बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया था। इमैनुएल के साथ इस साजिश में शामिल और हैती में पुलिस आपरेशन में मारे गए मौरिसियो रिवेरो की पत्नी ने कहा है कि उनके पति के पास किसी का फोन आया था, जिसने उसे एक बेहतर काम में लगाने की पेशकश की थी।

महत्वाकांक्षी है हत्या का मास्टरमाइंड : एपी के अनुसार मास्टरमाइंड डाक्टर इमैनुएल सेनोन पादरी भी है। वह अति महत्वाकांक्षी है। इमैनुएल ने एक बार अपने देश का नेतृत्व करने की इच्छा जताई थी। इस संबंध में उसने यू ट्यूब पर एक वीडियो भी अपलोड किया था।

हैती में अमेरिकी सेना भेजने का निर्णय अभी खारिज नहीं : रायटर के अनुसार व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हैती के कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ के सेना भेजने के प्रस्ताव की अभी समीक्षा की जा रही है। प्रस्ताव को अभी खारिज नहीं किया गया है। हैती ने अमेरिका से प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के लिए सेना भेजने का आग्रह किया था।



ऐसी कई चीजें हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, विशेषकर बल्लेबाजी विभाग में। अगले सात महीने हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।
— स्मृति मंधाना, उप कप्तान, भारतीय महिला टी-20 टीम

अनुबंध विवाद पर मुरलीधरन ने अनुभवी क्रिकेटरों को फटकारा

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंकाई स्पिन दिग्गज मुथैया मुरलीधरन ने केंद्रीय अनुबंध विवाद के लिए चार सीनियर खिलाड़ियों को फटकार लगाई है। पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज और कुशल परेरा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ कई दूसरे खिलाड़ी भी केंद्रीय अनुबंधों को लेकर श्रीलंका क्रिकेट के साथ लंबे समय तक चले आ रहे विवाद में शामिल हैं। खिलाड़ियों ने पारदर्शिता के मुद्दों पर अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।



यशपाल की पारी ने रखी थी विश्व कप जीत की नींव

छाती पर मैल्कम मार्शल की गेंदों के निशान दिखाकर विश्व कप विजेता टीम के सदस्य शर्मा कहते थे, उनसे मेरा अजीब रिश्ता था

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अपने जज्बे और समर्पण के लिए भारतीय क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा टीम इंडिया के फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर के गवाह रहे। यशपाल 1979 विश्व कप की उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसे श्रीलंका के खिलाफ भी हार मिली, जबकि चार साल बाद कपिल देव की अगुआई में उनकी मौजूदगी वाली टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीता था।

भारतीय क्रिकेट ने मंगलवार को अपने सबसे समर्पित सैनिकों में से एक यशपाल को गंवा दिया। यशपाल के पास गावस्कर जैसी योग्यता, वेंगसरकर जैसा विवेक या विश्वनाथ जैसी कलात्मकता नहीं थी, लेकिन जो भी यश पाजी को जानता है उसे पता है कि उनके जैसा समर्पण, जज्बा व जुनून किसी में नहीं था। 1983 विश्व कप में कपिल, अमरनाथ और बिन्नी के प्रदर्शन को अधिक सुर्खियां मिलती हैं, लेकिन यशपाल की छाप किसी से कम नहीं थी। यशपाल ने कहा था, 'मैल्कम मार्शल के साथ मेरा अजीब रिश्ता था। मैं जब भी बल्लेबाजी के लिए जाता तो वह कम से कम दो बार गेंद मेरी छाती पर मारते।' मार्शल के बाउंसर व 145 किमी प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार की इनस्विंगर का सामना करने की बात गर्व से बताते हुए यशपाल कहते थे, 'मैंने 1983 में (विश्व कप से ठीक पहले) सबीना पार्क में 63 रन बनाए थे और सबसे आखिर में आउट हुआ। मैं ड्रेसिंग रूप गया, टी-शर्ट उतारी। वहां उनकी प्यार की निशानी (गेंद से लगी चोट) थी।'

उनके लिए जब दिलीप कुमार ने की डूंगरपुर से बात : यशपाल पंजाब के धाकड़ बल्लेबाज के रूप में 1970 के दौर में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हुए। हाल में दिलीप कुमार के निधन के बाद यशपाल ने बताया था कि कैसे यह दिग्गज अभिनेता उनके पास आए और उनसे कहा था कि वह किसी से बात करेंगे। बाद में उन्हें पता चला कि दिलीप ने उनके बारे में अपने मित्र राज सिंह डूंगरपुर को बताया जो भारतीय क्रिकेट में स्तंभों में से एक रहे।

जिन्हें माना अपने करियर की तीन यादगार पारियां : यशपाल की विश्व कप के भारत के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 89 रन की पारी थी जिसने भारत की सफलता का मंच तैयार किया था। भारत ने यह मैच 32 रन से जीता था। वह आस्ट्रेलिया के खिलाफ चेम्सफोर्ड में टीम के अंतिम ग्रुप मैच में भी शीर्ष स्कोरर थे, लेकिन जिस पारी ने उन्हें 1980 के क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में अमर कर दिया वह इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 61 रन की पारी थी। यशपाल की एक अन्य पारी जिसे भुला दिया गया वह 1980 में एडिलेड में न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। उन्होंने 72 रन बनाए।

यह अविश्वसनीय है। वह हम सभी में सबसे अधिक फिट थे। हम जब उस दिन (कुछ दिन पहले एक किताब के विमोचन के मौके पर) मिले थे तो मैंने उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा था। वह शाकाहारी थे। रात को खाने में सूप लेते थे और सुबह की सैर पर जरूर जाते थे। मैं सकते में हूं। **दिलीप वेंगसरकर**

वह उन मुख्य हीरो में शामिल थे जिन्होंने हमारे 1983 विश्व कप जीतने में मदद की। उनके साथ खेलने की मेरी शानदार यादें हैं। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। **क्रिस श्रीकांत**

स्तब्ध हूं, यह मेरे लिए सबसे बुरी खबर है। 1983 की टीम परिवार की तरह थी और ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य नहीं रहा, यह काफी स्तब्ध करने वाला है। **बलविंदर सिंह संधू**

जीवन में इतनी जल्दी विश्व कप जीत के एक साथी को खोने पर वास्तव में दुखी और स्तब्ध हूं। परिवार के प्रति संवेदना और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। **रवि शास्त्री**



वह 1983 विश्व कप में मेरे साथी विकेटकीपर थे। हम विश्व कप में किसी बैकअप विकेटकीपर के साथ नहीं गए थे। मैं प्रमुख विकेटकीपर था और वह मेरे सहयोगी। वह इस बड़े टूर्नामेंट के दौरान दूसरे विकेटकीपर की भूमिका निभाने वाले थे। यशपाल की सबसे बड़ी खूबी थी उनके अंदर का मोटिवेशन। पूरी टीम को हमेशा ही मोटिवेट किया करते थे। वह बेहद ही जिंदादिल इंसान थे जो हमेशा ही दूसरों को खुश रखना जानते थे। यशपाल के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। **सैयद किरमानी**

उस दिन जब हम मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा वजन कम हो गया। हमारे लिए यादगार दिन था। मुझे विश्व कप 1983 का पहला मैच याद है। हमारा सामना वेस्टइंडीज की मजबूत टीम से था जिसके पास तूफानी गेंदबाजों की फौज थी। यशपाल ने अपनी योजना बनाई और हम मैच जीत गए। **कीर्ति आजाद**

यशपाल हमें छोड़कर चले गए हैं इस पर यकीन नहीं होता। यशपाल टीम मैन होने के साथ-साथ अच्छे इंसान भी थे। **मदन लाल**

मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा : कपिल देव

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट जगत मंगलवार को 1983 विश्व कप के हीरो यशपाल शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए स्तब्ध था। विश्व कप में एतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीम के उनके पूर्व साथियों के लिए इस पूर्व बल्लेबाज को श्रद्धांजलि देते हुए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। विश्व कप 1983 की चैंपियन भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव से जब संपर्क किया तो वह काफी दुखी और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे और सिर्फ इतना ही बोल पाए, 'मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा।'

यशपाल शर्मा जी के निधन से स्तब्ध और बेहद दुखी हूं। उन्हें 1983 विश्व कप में बल्लेबाजी करते हुए देखने की अच्छी यादें मेरे जेहन में हैं। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। **सचिन तेंदुलकर**

यशपाल शर्मा का अंतरराष्ट्रीय करियर

प्रारूप	मैच	रन	औसत	सर्वश्रेष्ठ	शतक	अर्धशतक
टेस्ट	37	1606	33.45	140	2	9
वनडे	42	883	28.48	89	0	4

द हंड्रेड में पांच गेंद का होगा ओवर और 25 गेंद बाद पावरप्ले

लंदन, आइएएनएस : मैच की प्रत्येक पारी को 100 गेंदों तक समित रखने के अलावा द हंड्रेड के पहले सत्र में पांच गेंदों का ओवर होगा, जिसके पूरा होने पर अंपायर अपने पास मौजूद सफेद कार्ड को ऊपर उठाकर संकेत देंगे। इसके अलावा पावरप्ले 25 गेंदों को होगा, जिस दौरान सिर्फ दो खिलाड़ी 20 गज के घेरे के बाहर रह सकेंगे। इसके बाद क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम दो मिनट का स्ट्रैटेजिग टाइमआउट के लिए कह सकेंगी और पारी के दौरान कभी भी इसे ले सकेंगी। हालांकि, यह अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम इसके लिए नहीं कह सकेगी। वहीं, टास डीजे स्टैंड पर होगा। इंग्लैंड और क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को द हंड्रेड के आयोजन के लिए नियमों की जानकारी दी। साथ ही इंग्लैंड में पहली बार घरेलू क्रिकेट में डीआरएस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान एक गेंदबाज अधिकतम 20 गेंदें डाल सकेगा, जिसमें वह चार बार में पांच-पांच गेंदें फेंक सकेगा या फिर दो बार 10-10 गेंदें कर सकेगा। मैचों के दौरान दोनों पारियों में अलग-अलग सफेद कूकाबुरा गेंदों का इस्तेमाल होगा और एक छोर से एक बार में 10 गेंदें फेंकी जाएंगी, जिन्हें पांच-पांच के दो भागों में भी किया जा सकेगा।

26 साल बाद आस्ट्रेलिया से सीरीज जीता वेस्टइंडीज

सेंट लूसिया, एपी : क्रिस गेल की 38 गेंदों में धमाकेदार 67 रनों की पारी से वेस्टइंडीज ने आस्ट्रेलिया को तीसरे टी-20 में छह विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली। गेल ने चार चौके व सात छक्के जड़े। वेस्टइंडीज की आस्ट्रेलिया के खिलाफ यह किसी भी प्रारूप में 26 साल में पहली सीरीज जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने आस्ट्रेलिया को 1995 में वनडे सीरीज में 4-1 से हराया था।

आस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए मैथ्यू वेड (23), कप्तान आरोन फिंच (30) और मोइसेस हेनरिक्स (33) की पारियों की बदौलत 20 ओवरों में 6 विकेट पर 141 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने गेल के अर्धशतक व निकोलस पूरन के नाबाद 32 रनों की बदौलत 14.5 ओवरों में ही चार विकेट पर 142 रन बनाकर जीत हासिल की।

दक्षिण अफ्रीका पर आयरलैंड की पहली जीत : आयरलैंड ने मंगलवार को यहां दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 43 रन से हराकर इतिहास रच दिया। यह उसकी दक्षिण अफ्रीका पर पहली जीत है। तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान आयरलैंड ने पहले खेलते हुए कप्तान एंडी बालबर्नी (102 रन) की शतकीय पारी की बदौलत पांच विकेट पर 290 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 247 रन पर सिमट गई। सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते हो नहीं पाया था। इस जीत से आयरलैंड ने विश्व कप 2023 से पहले सुपर लीग में 10 जरूरी अंक हासिल किए हैं। हालांकि आयरलैंड अभी तक भारत, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमों को नहीं हरा सका है।

सीनियर खिलाड़ी नहीं होने के बावजूद टीम श्रीलंका पर रहेगी भारी : अगरकर

पूर्व भारतीय गेंदबाज अजित अगरकर का कहना है कि भले ही श्रीलंका में गई भारतीय टीम में सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं फिर भी वह श्रीलंकाई टीम पर भारी पड़ेगी। सोनी नेटवर्क के क्रिकेट एक्सपर्ट **अजित अगरकर** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने भारत-श्रीलंका सीरीज को लेकर विशेष बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :

साक्षात्कार



आपकी नजरें किन भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी?

-टी-20 विश्व कप की टीम के बारे में बात करें तो पहले ही 11-12 खिलाड़ी पक्के हो चुके हैं। ऐसे में तीन से चार स्थान बचते हैं उसके लिए दौड़ है या कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो मौका बन सकता है। मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव, इशान किशन, संजू सैमसन और मनीष पांडेय को मैं यहां पर एक बार मौका देना चाहूंगा। उन्हें भी इस सीरीज में खुद को साबित करना होगा। शिखर धवन को भी ओपनिंग में खुद को साबित करना होगा क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा है कि रोहित के साथ केएल राहुल और विराट कोहली भी ओपनिंग करने उतरे हैं। ऐसे में कप्तानी के दबाव के साथ धवन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार को फिटनेस साबित करनी होगी। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, और राहुल चाहर जैसे खिलाड़ी लाइन में है। इसके बाद आइपीएल का बाकी सीजन भी है तो अगर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया तो टी-20 विश्व कप में नजर आ सकते हैं।

● **बीसीसीआइ ने अब दो टीमें बनाई हैं। एक टीम इंग्लैंड में हैं और दूसरी युवाओं से भरी टीम श्रीलंका में सीरीज खेलने उतरेगी। इसे कैसे देखते हैं?**

-देखिए एक तो अच्छी चीज है कि भारत के पास इतने अच्छे युवा खिलाड़ी हैं कि दो टीमें बनाई जा सकती हैं। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि बीसीसीआइ ने यह जानबूझ कर किया है। अगर कोरोना न होता तो इंग्लैंड में खेलने वाले खिलाड़ी श्रीलंका आते और फिर से इंग्लैंड सीरीज खेलने चले जाते। अब देखना होगा कि महामारी की वजह से जो इस तरह की अजीब स्थिति सामने आई है, इसे आगे जारी रखते हैं या नहीं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हमेशा रहेगा। वहीं भारत के लिए श्रीलंका दौरे की बात करें तो कई नए युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण भी टीम में मौजूद है। यह एक अच्छा संकेत है कि सीमित ओवर के क्रिकेट में भारत के पास एक समय में दो टीमें बन सकती हैं।

● **श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने कहा था कि यह भारत की बी टीम है। उन्होंने इसके साथ खेलने पर श्रीलंका क्रिकेट संघ की आलोचना की थी?**

-अर्जुन रणतुंगा महान खिलाड़ी हैं और श्रीलंका के कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने श्रीलंका बोर्ड की आलोचना की थी। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। कोरोना की वजह से एक अजीब सी स्थिति हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं है कि 15 खिलाड़ी इंग्लैंड में आराम कर रहे हैं और दूसरे 15 खिलाड़ियों को श्रीलंका भेजा गया है। भारत की टीम जो श्रीलंका गई है वह कोई स्कूल की टीम नहीं है। मैदान में प्रदर्शन से सब पता चल जाएगा। मैं रणतुंगा के विचार से सहमत नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआइ ने सामने श्रीलंका की टीम देखी तो जानबूझकर ऐसा किया है।

● **श्रीलंकाई का हालिया प्रदर्शन इंग्लैंड में खराब रहा है। इसके अलावा कोरोना महामारी से भी टीम जूझ रही है। ऐसे में आप सीरीज के नतीजे क्या देखते हैं?**

-भले ही इस टीम में बुमराह, शमी और रोहित जैसे खिलाड़ी नहीं है, फिर भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। टीम को अच्छा क्रिकेट खेलना होगा क्योंकि श्रीलंका को घरेलू परिस्थितियों का भी फायदा मिल सकता है। माना कि भारत और श्रीलंका के हालत में ज्यादा अंतर नहीं है फिर भी घर में खेलने वाली टीम ज्यादा सहज होती है। दोनों टीमों की तुलना करें तो कागज पर भारत की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मगर उसके मुताबिक उन्हें प्रदर्शन करना होगा क्योंकि नए खिलाड़ी हैं और टी-20 विश्व कप आने वाला है। श्रीलंका की बात करें तो वह इंग्लैंड में हारकर आई है।

● **2019 विश्व कप के बाद से कुलदीप को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। ऐसे में कुलदीप के लिए इस सीरीज को कितने बड़े मौके के रूप में देखते हैं?**

-कुलदीप के पास बहुत बड़ा मौका है और उम्मीद करता हूं कि उन्हें सीरीज के सारे मैच खेलने को मिलेंगे। क्योंकि नेट्स में आप चाहें जितनी मर्जी गेंदबाजी कर ले लेकिन मैच में जब तक खेलने को नहीं मिलेगा तब तक आपका आत्मविश्वास वापस नहीं आएगा। इस लिहाज से वह मैच विनर फिर से बन सकते हैं। उम्मीद करूंगा की कुलदीप को मैच खेलने को मिले और वह शानदार गेंदबाजी करके अपना आत्मविश्वास वापस पाएं, जिससे टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर वह खरे उतरे और अपने लिए जगह पक्की करें।

पाठक जैसे अपराधी का ओलिंपिक जाना शर्मनाक : मित्तल

नई दिल्ली, एएनआइ : टोक्यो ओलिंपिक के लिए जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सूची में अंतिम समय में हुए कुछ बड़े बदलावों ने चौंका दिया है। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी मधुकांत पाठक को एथलेटिक्स टीम मैनेजर के रूप में भेजने का भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) के उपाध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कड़ा विरोध किया है। इसके अलावा तलवारबाज सीए भवानी देवी की मां सीए सुंदररमन रमानी को उनके साथ बतौर मैनेजर जबकि टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के व्यक्तिगत कोच सन्मय परांजपे को उनका मैनेजर नियुक्त करके ओलिंपिक भेजा जा रहा है।

मित्तल ने कहा, 'जहां तक मधुकांत पाठक का सवाल है तो लंबे समय से जेल में बंद व्यक्ति को एथलेटिक्स टीम का मैनेजर बनाकर भेजना अस्वीकार्य है। आप किस तरह का संदेश भेज रहे हैं कि खेल भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अब देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आइओए प्रमुख नरेंद्र बत्रा के कहने पर किया जा रहा है। बत्रा ने हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा कि ऐसे लोग न जाएं।' मधुकांत पाठक को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में आरोपित बनाया गया है। इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी ने मधुकांत पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित अन्य शर्तों पर मधुकांत पाठक को जमानत दिया था। तभी से उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा था। जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने ओलिंपिक में शामिल होने के लिए पासपोर्ट रिलीज कर दिया था लेकिन यह भी कहा था कि ओलिंपिक से आने के बाद उनका पासपोर्ट फिर से जब्त कर लिया जाएगा। मनिका के कोच सन्मय और भावनी देवी की मां रमानी को भेजे जाने के बारे में मित्तल ने कहा, 'देखिए नाम दो प्रकार से चुने जाते हैं एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो जाने वाले खिलाड़ियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। ये खिलाड़ी देश के लिए पदक की संभावनाएं हैं और ऐसे में उनके साथ पसंदीदा रिश्तेदार जैसे कि भवानी देवी को मां (सीए सुंदररमन रमानी) निजी स्टाफ के तौर पर ले जाने को मिल रहीं है। वह काफी लंबे समय से खिलाड़ी के साथ हैं और उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं। ऐसे लोगों को भेजना, मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए।'

ओलिंपिक में नहीं नजर आएंगे फेडरर

नई दिल्ली, जेएनएन : दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलिंपिक से हट गए है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। फेडरर ने लिखा, 'दुर्भाग्य से मैंने अपने घुटने में एक झटका सा महसूस किया है, जिसके बाद मैंने स्वीकार कर लिया है कि अब टोक्यो ओलिंपिक खेलों से मुझे हट जाना चाहिए।' फेडरर पहले टेनिस खिलाड़ी नहीं है, जिन्होंने टोक्यो ओलिंपिक में नहीं खेलने का फैसला किया है। इससे पहले स्पेन के राफेल नडाल, आस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम भी ओलिंपिक से हट चुके हैं।

यूरो कप की टीम में रोनाल्डो नहीं

फुटबॉल डायरी

स्विट्जरलैंड, एएनआइ : यूरोपीय फुटबाल संघ ने मंगलवार को यूरो कप की सर्वश्रेष्ठ एकादश की घोषणा की, जिसमें चैंपियन इटली के पांच तो खिताब से चूकने वाली इंग्लैंड के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है। हालांकि इस टीम में पुर्तगाल के सुपरस्टार स्ट्राइकर कप्तान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जगह नहीं मिली हैं। उन्होंने सर्वाधिक पांच गोल करके गोल्डन बूट हासिल किया था।

यूएफा यूरो कप 2020 टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम इस प्रकार है- जियानलुइगी डोनारूमा, लियोनार्डो बोनुची, लियोनार्डो स्पिनाजोला, जोर्जिन्हो, चिएसा (इटली), हैरी मैगुइरे, काइल वाकर, रहीम स्टर्लिंग (इंग्लैंड), पिएरे-एमिल होजबर्ज (डेनमार्क), पेड्रि (स्पेन) और रोमेलु लुकाकू (बेल्जियम)।

मेसी ने माराडोना को समर्पित किया कोपा अमेरिका खिताब

ब्यूनर्स आयर्स : लियोन मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने 28 साल बाद कोपा अमेरिका खिताब जीता। अर्जेंटीना ने इस खिताबी मुकाबले में ब्राजील को 1-0 से हराया, जो कि मेसी का अर्जेंटीना के लिए उनके 16 वर्षों के करियर में पहला बड़ा खिताब भी है। इसे मेसी ने अर्जेंटीना के नागरिकों और महान दिवंगत खिलाड़ी डिएगो माराडोना को समर्पित किया। अर्जेंटीना के दिग्गज माराडोना का देहांत पिछले साल हुआ था। माराडोना ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को 1986 फीफा विश्व कप भी जिताया था।

भारतीय हॉकी टीम ने जीता सोना

टोक्यो ओलिंपिक



09 दिन शेष

पेरिस में आयोजित ओलिंपिक ने इसे दुनिया भर में सबसे बड़े खेल महाकुंभ के रूप में स्थापित किया। एम्सटर्डम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक मशाल जली। यह तीसरा ओलिंपिक था जिसमें भारत ने भाग लिया।

पेरिस ओलिंपिक (1924)



04 मई से 27 जुलाई

3089 एथलीट | 44 देश | 17 खेल, 126 मुकाबले



इस बार 29 देशों से बढ़कर 44 देशों ने ओलंपिक में भाग किया। इस बार ज्यादा मुकाबले भी हुए जिसको कवर करने के लिए 1000 से ज्यादा पत्रकार पहुंचे।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	45	99
फिनलैंड	14	37
फ्रांस	13	38
ब्रिटेन	09	34
इटली	08	16

जबर्दस्त प्रदर्शन



फिनलैंड के एथलीट पावो नूर्मी ने अविस्मरणीय प्रदर्शन किया। उन्होंने आराम से 1500 मीटर रेस जीतने के 55 मिनट के भीतर ही 5000 मीटर रेस भी जीतकर कीर्तिमान बना दिया।



हॉलीवुड हीरो

अमेरिकी तैराक जॉनी वीसमुलर ने दो स्वर्ण जीते। अगले ओलंपिक में भी उन्होंने दो स्वर्ण जीते। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की टार्जन श्रृंखला की 12 फिल्मों में काम किया

ओलिंपिक गांव

पहली बार खिलाड़ियों के लिए ओलिंपिक गांव बनाया गया, जिसमें वे रहे।

समापन समारोह

समापन समारोह की परंपरा शुरू हुई। इसमें अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति, आयोजक देश और अगले मेजबान देश के झंडे लहराए जाने की शुरुआत हुई।

एम्सटर्डम ओलिंपिक (1928)



28 जुलाई से 12 अगस्त

2883 एथलीट | 46 देश | 14 खेल, 109 मुकाबले



एम्सटर्डम ने 1920 और 1924 ओलिंपिक के लिए भी बोली लगाई थी लेकिन उसे बाद में 1928 की मेजबानी मिली।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	22	56
जर्मनी	10	31
फिनलैंड	08	25
स्वीडन	07	25
इटली	07	19

महिलाओं का प्रदर्शन

जिम्नास्टिक्स और एथलेटिक्स में महिलाओं को भी अनुमति दी गई जिससे खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ। इटली की जिम्नास्ट लुइजीना जियावोटी सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली एथलीट बनीं। उन्होंने 11 साल, 302 दिन की उम्र में रजत पदक जीता।

भारतीय प्रदर्शन : 1928 से 56 तक लगातार छह ओलिंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने पीला तमगा जीतकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इसकी शुरुआत इन्हीं खेलों में स्वर्ण पदक जीतने से हुई। इन 24 मैचों में 178 गोल भारतीय टीम ने किए। यानी हर मैच में औसतन सात से ज्यादा गोल। मेजर ध्यानचंद अंतरराष्ट्रीय हॉकी जगत में स्टार बनकर उभरे। उनके दनादन गोलों को बस विरोधी टीमें देखती रही



प्रोटोकॉल : उद्घाटन समारोह में ग्रीस की टीम ने बाकी देशों की परेड टीम का नेतृत्व किया। मेजबान टीम सबसे पीछे रही। बाद में प्रोटोकॉल बन गया कि देशों की परेड में ग्रीस सबसे आगे और मेजबान पीछे रहेगा।

लॉस एंजिलिस (1932)



30 जुलाई से 14 अगस्त

1332 एथलीट | 37 देश | 14 खेल, 117 मुकाबले

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	41	103
इटली	12	36
फ्रांस	10	19
स्वीडन	09	23
जापान	07	18

1900-1928 के बीच कोई भी ओलंपिक 79 दिन से कम नहीं हुआ था। पहली बार यह आयोजन सिर्फ 16 दिन तक चला। उसके बाद से 15-18 दिन की परंपरा बन गई।



आर्थिक मंदी

भयानक आर्थिक मंदी और व्यवस्थित परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण 1904 के बाद से सबसे कम एथलीट इस आयोजन में पहुंचे। पहली बार ओलिंपिक में पदक विजेता पोडियम पर खड़े होने लगे और विजेता के देश के ध्वज फहराए जाने लगे।

हमारा प्रदर्शन

हाकी टीम ने अमेरिका के खिलाफ मैच में एक के मुकाबले 24 गोल दागकर इतिहास रच दिया। 11 अगस्त, 1932 को खेले गए इस मैच में रूप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 गोल दागे।

बर्लिन (1936)



एक अगस्त से 16 अगस्त

3963 एथलीट | 49 देश | 19 खेल, 129 मुकाबले

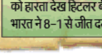


तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
जर्मनी	33	89
अमेरिका	24	56
हंगरी	10	16
इटली	08	22
फिनलैंड	07	19

ग्रीस के ओलंपिया से आयोजन स्थल तक के लिए टार्च रिले की शुरुआत हुई। बास्केटबाल, केनोइंग और फील्ड हैंडबाल की शुरुआत हुई।

हमारा प्रदर्शन : ध्यानचंद के नेतृत्व में हाकी टीम ने फाइनल तक के सफर में विरोधी टीमों को एक भी गोल नहीं करने दिया। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मुकाबले में एडोल्फ हिटलर समेत 40,000 दर्शक थे। जर्मनी को हारता देख हिटलर बीच में ही मैच छोड़कर चला गया। भारत ने 8-1 से जीत दर्ज कर पीला तमगा जीता।



दैनिक जागरण
सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का
बुधवार, 14 जुलाई, 2021

कोरोना से ठीक होने के दो महीने बाद लगवाएं टीका



संक्रमित होने के बाद लोगों के मन में यह सवाल बार-बार आता है कि वैक्सीन लगवाई जाए या नहीं। ऐसे लोगों को चाहिए कि कम से कम दो माह तक वैक्सीन न लगवाएं। ध्यान रहे कि आप डायबिटीज या हाई ब्लडप्रेशर जैसी किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों न हों, वैक्सीन जरूर लगवाएं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें टीका लगवाने से मना किया गया हो। कोरोना से संक्रमित लोग पाजिटिव आने के दिन से कम से कम दो महीने बाद टीका लगवाएं। जिन्हें पहला डोज लगने के बाद कोरोना हुआ है वे भी यही करें। टीका लगवाने के पहले यह देख लें कि बुखार, स्वाद या गंध नहीं आने समेत कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं हैं। यदि ऐसा है तो कोरोना की जांच कराने के बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वैक्सीन लगवाएं।

सतर्क रहें कोरोना संक्रमण के बाद के लक्षणों से

कोरोना को हराना है



इन दिनों



डा. अभिषेक गोयल
छाती व श्वास रोग विभाग
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल

कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद लोगों को कमजोरी, सांस फूलना, पैरों में सूजन, थकान और नींद न आने की समस्या हो रही है। दो से तीन माह में ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह की परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें...

कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। इनमें सबसे आम है थकान, कमजोरी और नींद नहीं आना। लोगों में कोरोना संक्रमण से उबरने के दो से तीन महीने तक इस तरह की तकलीफ देखने को मिल रही है। हालांकि पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। संक्रमित होने के बाद जिन लोगों को इस तरह की परेशानी हो रही है, वे घबराएं नहीं, क्योंकि अधिसंख्य मामलों में धीरे-धीरे इस तरह की परेशानी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे पोषक आहार लें, हल्का व्यायाम और योग करें। हां, सतर्कता रखना बेहद जरूरी है। यदि कुछ भी असामान्य लगता है तो चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। इसके अलावा यदि छाती में दर्द, सांस फूलना और पैरों में सूजन हो तो इसे भी गंभीरता से लें। ये समस्याएं खून का थक्का जमने की वजह से होती हैं। खून का थक्का किसी भी अंग में पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। ये थक्का फेफड़े, हार्ट और ब्रेन में पहुंचकर खून की आपूर्ति रोकता है, जो जानलेवा साबित होता है। कोरोना संक्रमण के बाद लकवा और हार्ट अटैक के भी खूब मामले प्रकाश में आ रहे हैं। कई बार खून का थक्का इस तरह का अवरोध पैदा करता है कि पैरों में गैंगरीन (खून की सप्लाई नहीं होने से वह हिस्सा खराब होना) और आंखों की रोशनी जाने का खतरा हो सकता है। हालांकि इसमें उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जो कोरोना संक्रमण के चलते गंभीर स्थिति में पहुंचे हों।

सही हो खानपान और दिनचर्या

कोरोना से उबर चुके मरीजों को अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित रखनी चाहिए। अधिक तेल-मसाले वाले खाने से परहेज करें और घर में बनी चीजों को प्राथमिकता दें। दिन में दो लीटर पानी अवश्य पिएं। वही खाना खाएं जो आसानी से पच जाए। नियमित रूप से हल्के व्यायाम करें। दो-तीन महीने ऐसे व्यायाम न करें, जिनमें अधिक मेहनत लगती है। कोरोना संक्रमित होने के बाद लोगों को नींद नहीं आने की भी समस्या हो रही है। यदि लगातार यह समस्य बनी रहे तो मनोचिकित्सक को दिखाएं। अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि शाम के बाद चाय-काफी न लें। सोने के एक घंटे पहले टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से दूरी बना लें।



म्यूकरमायकोसिस से भी रहें सतर्क: कोरोना से ठीक होने के बाद म्यूकरमायकोसिस के मरीज मिल रहे हैं। यह बीमारी उन लोगों को ज्यादा होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। यह सिर्फ परिकल्पना है कि कोरोना के दौरान जिन्हें स्टेरायड दिया गया उन्हें यह बीमारी हुई। म्यूकरमायकोसिस का असर नाक, आंख और ब्रेन में होता है, लेकिन कई बार यह संक्रमण फेफड़ों में भी पहुंच जाता है, जो बहुत दुर्लभ माना जाता है। एंटीफंगल इंजेक्शन और सर्जरी से ज्यादातर मरीजों में यह बीमारी ठीक हो जाती है। नाक बंद होना, चेहरे में सूजन, आंखें लाल होना और नाक से काला पानी आने की समस्या हो तो तत्काल चिकित्सक को दिखाएं।

किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं और कोरोना हुआ है तो ज्यादा सतर्क रहें: जिन मरीजों को पहले से कोई बीमारी थी और कोरोना की चपेट में आ गए तो उन्हें चाहिए कि पुरानी बीमारी की कोई भी दवा चिकित्सक की सलाह के बिना बंद न करें और न ही दवा का डोज खुद से बढ़ाएं। जिन लोगों के फेफड़े पहले से खराब हैं, दिल की बीमारी है या फिर दूसरी तकलीफ है, उन्हें दोबारा कोरोना होने पर ज्यादा परेशानी हो सकती है। इन्हें कोरोना से बचने के सारे उपाय अपनाते हुए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। फेफड़े की बीमारी वाले मरीजों को पहले भी एंफ्लूएंजा और निमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाई जाती थी।

शुगर का स्तर नियंत्रित रखें: डायबिटीज के मरीजों में कोरोना होने पर गंभीर होने का खतरा ज्यादा रहता है। कोरोना संक्रमण के बाद वे मरीज गंभीर स्थिति में आए, जिनका शुगर का स्तर नियंत्रित नहीं रहा है। इन्हें यही सलाह है कि दवाएं नियमित लें। कोरोना संक्रमण के दौरान स्टेरायड दिए जाने की वजह से भी कुछ मरीजों का शुगर का स्तर बढ़ता है, लेकिन एक-दो महीने में अपने आप ठीक भी हो जाता है। कोरोना संक्रमितों में देखा गया कि कुछ लोग ऐसे भी थे, जो डायबिटीज की पूर्व अवस्था (प्रीडायबिटिक) में थे। ये स्टेरायड दिए जाने से डायबिटीज मरीज की श्रेणी में आ गए।

मास्क अवश्य लगाएं: मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। अस्पताल या भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो एन-95 मास्क का प्रयोग करें। सामान्य भीड़ वाली जगह में सर्जिकल मास्क से भी काम चला सकते हैं। कपड़े का मास्क प्रयोग करें तो दोहरा मास्क लगाएं।

प्रस्तुतिः शशिकांत तिवारी

नजरअंदाज न करें पैरों का दर्द

हेल्थ फाइल



डा. के. के. पाण्डेय
सीनियर वैस्कुलर एवं कार्डियो सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली



पैरों में दर्द होने का कारण डायबिटीज, रक्त धमनियों की बीमारी, धूमपान या तंबाकू उत्पादों का सेवन हो सकता है। यदि दर्द लगातार रहता है तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि कई बार यह गंभीर समस्या बन जाता है...

उपचार

पैरों में लगातार दर्द की समस्या होने पर वैस्कुलर सर्जन से सलाह लें। इसके लिए कुछ जांचें, जैसे एम.आर. आरटीरियोग्राफी व एंजियोग्राफी के द्वारा रोग की सही स्थिति का पता लगाया जाता है।

कुछ लोगों के पैरों में दर्द चलने पर होता है और चलना बंद कर देने पर दर्द भी गायब हो जाता है, लेकिन दोबारा चलने पर फिर से दर्द होने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पैरों में दर्द चलने के दौरान कम हो जाता है, लेकिन लेटने पर इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अगर आप डायबिटीज के साथ जी रहे हैं या धूमपान व तंबाकू के शौकीन हैं तो पैरों व टांगों में हो रहे दर्द को लेकर सतर्क हो जाएं।

भविष्य में यह समस्या इस स्थिति में पहुंच सकती है कि आपको अपना पैर ही गंवाना पड़ जाए। लोगों को यह भ्रम रहता है कि डायबिटीज का पैरों से कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से धूमपान के आदी लोग यह समझते हैं कि धूमपान से सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और कैंसर हो सकता है, जबकि धूमपान और तंबाकू का सेवन करने वालों को गैंगरिन का खतरा हमेशा बना रहता है। मधुमेह व धूमपान दोनों मिलकर पैरों को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पैरों को स्वस्थ रखने के लिए धूमपान व तंबाकू सेवन से तौबा करना ही होगा।

क्यों होता है दर्द: पैरों में दर्द रक्त धमनियों की बीमारी से होता है। धमनियां पैरों को आक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं, जिससे पैर अपना कार्य सुचारु रूप से कर पाते हैं। जब धमनियां किसी वजह से शुद्ध रक्त की आवश्यक मात्रा पैरों में नहीं पहुंचा पातीं तो चलने में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि चलने से या पैरों का व्यायाम करने से शुद्ध आक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जो धमनियां पूरी नहीं कर पाती हैं।

डायबिटीज व धूमपान: पैरों की रक्त धमनी के ठीक से काम न करने के कई कारण होते हैं और इनमें से एक है डायबिटीज। डायबिटीज के कारण धमनी की दीवारों पर चर्बी व कैल्शियम जमा होने लगता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। इसी तरह धूमपान व तंबाकू का सेवन भी इस समस्या को बढ़ाने में कारक बनता है। तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, जो धमनियों में सिकुड़न ला देता है और पैरों तक जाने वाले रक्त प्रवाह को काफी कम कर देता है।

शिराएं भी हो जाती हैं परेशान: पैरों में दर्द का कारण वेन्स यानी शिरा का रोग भी है। जब धमनियों द्वारा पैरों तक पहुंचाया गया शुद्ध रक्त आक्सीजन देने के बाद अशुद्ध हो जाता है तो यही शिराएं दोबारा से उस अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती हैं तो यह अशुद्ध रक्त पैरों में इकट्ठा होकर पैरों में दर्द का कारण बनता है।

वेरिकोज वेन्स: पैरों में दर्द होने का एक और कारण वेरिकोज वेन्स है। ये मकड़ी के जालेनुमा और नीले रंग की आकृति के रूप में होते हैं। ये जांघों या घुटनों के पीछे बनते हैं। अगर समय रहते इनका उपचार न कराया जाए तो ये पैरों में गहरे काले निशान व लाइलाज घाव का रूप ले लेता है। इसलिए पैरों में दर्द हो रहा हो या नीले रंग की नसें दिखने लगें तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय वैस्कुलर सर्जन से परामर्श लेना चाहिए।

शिराओं में रक्त का जमाव: पैरों में दर्द होने का कारण शिराओं के अंदर रक्त के कतरे जमा हो जाना भी है। इसकी वजह से शिराओं का काफी हिस्सा पूरी तरह बंद हो जाता है और रक्त के ऊपर चढ़ने की क्रिया बाधित हो जाती है। इससे पैरों में लगातार दर्द बना रहता है।

कोरोना व बारिश के रोगों से बचाएगा आयुर्वेद

इसे भी जानें



डा. आर. अचल
एमडी (आयुर्वेद)



बारिश के मौसम में वायरस व बैक्टीरिया जनित रोगों के संक्रमण की तीव्रता बढ़ जाती है साथ ही कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है संयमित खानपान और सुव्यवस्थित जीवनशैली...

वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के खतरे से जूझ रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की गति धीमी पड़ गई है, पर खतरा अभी भी बना हुआ है। बरसात का मौसम चल रहा है। इसमें गर्मी, उमस, ठंड सभी कुछ एक साथ चलता है। इस मौसम में कीटाणुओं व विषाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। इसके कारण बीमार होने की संभावना अधिक रहती है। आजकल मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। इस मौसम में पीलिया, फ्लू, डायरिया, उल्टी व दाद, खाज जैसे चर्मरोग की भी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है।

कई रोगों का बढ़ता है खतरा: हमारा आहार शरीर की सारी क्रियाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए इन दिनों वात दोष का शमन करने वाले भोजन का प्रयोग करना चाहिए। बुजर्गों और वातजन्य रोगों के मरीजों जैसे गठिया, कमरदर्द, जोड़ों का दर्द, अपच आदि से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय पाचन शक्ति का कमजोर होना, शारीरिक कमजोरी, रक्तविकार, वायुदोष, जोड़ों में दर्द, सूजन, त्वचा विकार, कृमिरोग, ज्वर, मलेरिया, पेचिश तथा अन्य वायरस व जीवाणुजन्य रोग होने की संभावना अधिक रहती है।

परहेज योग्य आहार: आलू, अरबी जैसे कंदशाक, भिंडी, पत्ता गोभी, फूलगोभी आदि का सेवन सीमित करना चाहिए। खानपान में ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिनसे पित्त न बढ़े।

रोगों से बचाएंगी जड़ी-बूटियां: आयुर्वेद में बताए गए आहार व उपायों से बरसात के मौसम में स्वस्थ रहने में काफी मदद मिलती है। हरी गुर्च (गिलोय) या पुनर्नवामूल का स्वरस 50 मिली शहद के साथ मिलाकर पिएं या इन सूखी औषधियों का 20 ग्राम चूर्ण चार कप पानी में उबाल कर एक कप बचने पर छानकर पिएं। इससे महामारियों के संक्रमण से बचाव होगा। शतावरी, अश्वगंधा, मुलेठी में किसी एक का चूर्ण तीन ग्राम की मात्रा में दूध या गुनगुने जल से नियमित लें। बड़ी हरड़ का चूर्ण व चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर सादे पानी के साथ सेवन करना चाहिए। इससे पाचनतंत्र मजबूत होगा। इसी प्रकार शिलाजीत, गोखरु, ब्राह्मी, आंवला, तुलसी का प्रयोग भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इन औषधियों का सेवन किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लेकर ही करना चाहिए।

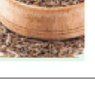
(संयोजक सदस्य, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस)



ये शरीर को पहुंचाएंगे फायदा



इन दिनों पुराने चावल, जौ, गेहूं आदि का सेवन करना चाहिए। घी व दूध अच्छी तरह पकाए गए हों और छौंक लगाने वाले भोजन में छौंक जरूर लगाएं। मूंग, उड़द से बने पदार्थ साथ ही अन्य दालें, पुराना शहद, आसव, अरिष्ट, काला नमक आदि को थाली का हिस्सा बनाएं। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलेगा। कद्दू, परवल, करेला, लौकी आदि व अदरक, जीरा, मेथी, लहसुन का सेवन सेहत के लिए अच्छा है। इस मौसम में छिलके वाली मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। जब बारिश हो रही हो या बादल घिरे हों तो खट्टे, नमकीन पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। नीबू का सेवन बरसात में होने वाली बीमारियों से बचाता है। शहद के सेवन से मंदाग्नि दूर होती है साथ ही भूख खुलकर लगती है। सीमित मात्रा में शहद के नियमित सेवन से अजीर्ण, थकान, कमजोरी और वायुजन्य रोगों से भी बचाव होता है। भोजन पकाने में तिल के तेल का इस्तेमाल करें, यह औषधि का काम करता है। इसमें वात रोगों के शमन का गुण होता है। हर मौसम में मौसमी फलों का सेवन लाभदायक रहता है।



आसान हुई स्पाइन सर्जरी

टेक्नोलाजी



डा. सुदीप जैन
स्पाइन सर्जन, दिल्ली

रीढ़ से संबंधित विभिन्न बीमारियों या विकारों को दूर करने में नवीनतम वेसलप्लास्टी तकनीक बहुत कारगर है। इस तकनीक में ओपन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती और एक छोटे से चीरे के जरिए इसे अंजाम दिया जाता है...

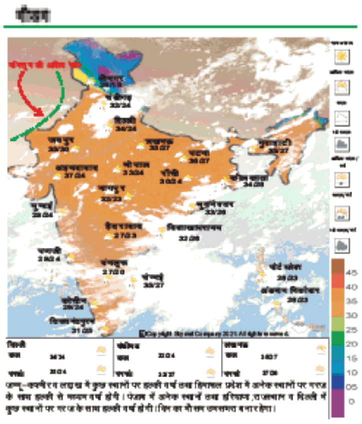


सर्जिकल व अन्य तकनीकों से रीढ़ की हड्डियों के विभिन्न रोगों और विकारों का इलाज तो पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन स्पाइनल कालम (रीढ़ की हड्डी की पूरी संरचना) और वर्टिब्रल बोन से संबंधित रोगों और विकारों को दूर करने में वेसलप्लास्टी नामक तकनीक ने बुनियादी बदलाव ला दिया है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां वर्टिब्रल बोन को नष्ट कर सकती हैं। इस कारण स्पाइनल कालम में विकृति आ जाती है। रीढ़ की हड्डी के क्षीण होने और इसमें विकार आने के कारण स्पाइनल कार्ड पर दवाब पड़ता है। जिससे स्पाइनल कार्ड की विभिन्न नाड़ियों (नर्व्स) में रक्त संचार सुचारु रूप से नहीं होता है। ऐसी गंभीर अवस्था में नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) की कार्य प्रणाली क्षीण व बाधित हो जाती है। नतीजतन किसी संवेदना को महसूस न करना, चलने में लड़खड़ाना और लकवा जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

क्या हैं कारण: ऊंचाई से गिरने या सड़क दुर्घटना में भी रीढ़ की हड्डी (वर्टिब्रल कालम) को क्षति पहुंच सकती है। आस्टियोपोरोसिस के कारण भी रीढ़ की हड्डियों में विकार आ जाता है। इसके साथ ही उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि बाथरूम में फिसलने या सीढ़ियों से गिरने या आघात लगने पर वे टूट जाती हैं। आस्टियोपोरोसिस से होने वाले फ्रैक्चर विभिन्न बोन्स या कालम को बहुत कमजोर व खोखला बना देते हैं। इसके कारण मरीज किसी भी वस्तु को उठाने में भी अक्षम हो जाता है। इन स्थितियों में मरीज चलने फिरने से वंचित हो जाता है और उसका समय बिस्तर पर ही बीतता है। हमारे देश में रीढ़ की हड्डी के विकारग्रस्त होने का प्रमुख कारण (बच्चों से लेकर वयस्कों तक) रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस या पाट्स स्पाइन नामक बीमारी है। पाट्स स्पाइन के कारण रीढ़ की हड्डी के प्रभावित भाग में पस पड़ जाता है और अन्य विकार पैदा हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डियों में विकृतियों का अन्य कारण बोन टी.बी. और बोन कैंसर है, जो रीढ़ की एक या एक से अधिक वर्टिब्रा को प्रभावित कर सकता है।

नई तकनीक की प्रक्रिया: वेसलप्लास्टी तकनीक से ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती। एक छोटे से चीरे के जरिए इसे अंजाम दिया जाता है। वेसलप्लास्टी तकनीक के अंतर्गत आपरेशन थियेटर में रोगग्रस्त वर्टिब्रल बोन के अंदर पीड़ित व्यक्ति को लोकल एनेस्थीसिया देकर उसके विकारग्रस्त वर्टिब्रल बोन में एक पतली नीडल (बोन नीडल) प्रवेश कराई जाती है। इसमें मानीटर पर किसी वीडियो की तरह एक्सरे इमेजेज और इस तकनीक से संबंधित हर प्रक्रिया दिखाई जाती है।

बोन नीडल में बैलून (गुब्बारा) लगा रहता है, जिसे वर्टिब्रल बोन के अंदर जाकर फुला दिया जाता है। इसके बाद इस बैलून या वैसल में बोन सीमेंट भरी जाती है। इस कारण वर्टिब्रल बोन का खोखलापन और अन्य विकार दूर हो जाते हैं। बोन सीमेंट बहुत थोड़े समय में विकारग्रस्त हड्डियों पर अपना प्रभाव दिखाती है। इस बोन सीमेंट का शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।





राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 14 जुलाई, 2021
आजकल
14
www.jagran.com

पहली बार मशीन से बनाई गई बर्फ

फ्लोरिडा के फिजिशियन जॉन गोरी ने वर्ष 1850 में आज की ही तारीख को पहली बार मशीन से बर्फ बनाई थी। गर्मी के दिनों में प्राकृतिक बर्फ के नहीं मिलने की दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने वर्ष 1840 में इस संबंध में प्रयास शुरू किए थे।





जब निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ फ्रांस में उठ खड़े हुए लोग

वर्ष 1789 में आज की ही तारीख को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके शुरू होने के पीछे की महत्वपूर्ण वजह लुई 16वें के शासन में निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार और जनता के प्रति राजा की उदासीनता थी। इस क्रांति के चलते प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की नींव पड़ी।

फिल्मों के शौकीन हैं एचसीएल के संस्थापक शिव नादर



सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनी एचसीएल के संस्थापक शिव नादर का जन्म आज की ही तारीख को 1945 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद डीसीएम में नौकरी की। 1967 में सात दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रोकॉम्प कंपनी बनाई, जिसे बाद में बेच दिया। 1976 में 1.87 लाख रुपये से एचसीएल की शुरुआत की। आज इसकी 46 देशों में शाखाएं हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। उनके पास चार हजार से ज्यादा फिल्मों का कलेक्शन है। 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

इधर-उधर की

जब ऊंट को पकड़ने के लिए दौड़ी पुलिस

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका के ओकलाहोमा शहर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक ऊंट को पकड़ने के लिए उसके पीछे-पीछे पुलिस भागती दिख रही है। पुलिस ने बयान में कहा कि कोलिंसविले पुलिस विभाग और टुल्सा काउंटी शेरिफ दफ्तर की ओर से ऊंट को पकड़ने में मदद मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और पकड़कर उसके मालिक को सौंप दिया। पुलिस द्वारा फेसबुक पर शेयर किया गया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में फ्लैश लाइट लेकर पुलिस ऊंट का पीछा करती दिख रही है। इंटरनेट मीडिया में कुछ लोगों ने शहरी क्षेत्र में ऊंट की मौजूदगी पर सवालिया निशान खड़ा किया है। हालांकि, ओकलाहोमा में ऊंट या जेब्रा को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर पाबंदी नहीं है।



ओकलाहोमा में ऊंट या जेब्रा को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर पाबंदी नहीं है। इंटरनेट मीडिया

नई दवाओं की खोज होगी आसान

मिलेगी मदद ▶ शोधकर्ताओं ने तलाशा प्रोटीन को बांधने वाली दवाओं की पहचान का तरीका

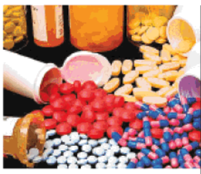
ब्रेस्ट कैंसर और पार्किंसन जैसी बीमारियों के उपचार में मिलेगी मदद

लंदन, एएनआइ : बीमारियों से लड़ने में दवाओं की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के विज्ञानी हर बीमारी के लिए बेहतर और ज्यादा असरदार दवा तैयार करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे दवा बनाने वालों को आसानी होगी। दरअसल, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका विकसित किया है, जिससे प्रोटीन को बांधने वाली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी।

केमिकल साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि इससे दवा बनाने वालों को दवाओं के यौगिकों की पहचान करने में आसानी होगी, जिससे कैंसर और पार्किंसन जैसे रोगों के नए उपचार खोजने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। मौलिक रूप से हमारी सभी कोशिकाएं जिस तरह से काम करती हैं, उसी तरीके से प्रोटीन परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। सही तरीके से अंतःक्रिया शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है और इसमें जरा सा भी बदलाव होने पर बीमारियां सामने आ जाती हैं। वर्तमान में ऐसी दवाओं की संख्या बहुत कम है जो अंतःक्रियाओं को तोड़कर बीमारियों को बढ़ने से रोकती हैं। हालांकि, कुछ बीमारियों में समस्या का कारण प्रोटीन का अंतःक्रिया न करना या सही तरीके से न करना होता है। यही वजह है कि नई दवाएं जो प्रोटीन बांधे रखने का काम करती हैं वे अत्यधिक प्रभावी होती हैं, लेकिन उन्हें खोजना आसान नहीं होता है।

इस शोध की प्रमुख लेखक डा. अनीका लेने के मुताबिक, एक स्वस्थ शरीर इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिकाओं के प्रोटीन कितने प्रभावी ढंग से संकेत करने में सक्षम हैं। कोई भी गलत संकेत बीमारी का कारण बन सकता है और यह गलत प्रोटीन के आपस में बंधने या चिपकने से हो सकता है। हम एक ऐसी दवा चाहते हैं जो इसे ठीक करे। हमारी इस नए शोध से यह पहचानने में आसानी होगी कि कौन से प्रोटीन आपस में बंधने से सही प्रतिक्रिया करते हैं। इसकी मदद से दवाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। चूंकि हमारे शोध से यह काम तेज होगा, इसलिए दवाओं की पहचान में तेजी आएगी, जिससे बीमारियों के उपचार में मदद मिल सकेगी।

ये आती हैं बाधाएं : इस शोध के अग्रणी लेखकों में से एक डा. रिचर्ड डोवेस्टन और उनकी टीम ने चिकित्सकीय यौगिकों पर विधि का परीक्षण करने के लिए लीसेस्टर विश्वविद्यालय में रासायनिक जीवविज्ञानियों के साथ काम किया। डा. रिचर्ड के मुताबिक, गोंद के रूप में काम करने वाले अणुओं की तलाश करना आसान नहीं है, क्योंकि दो प्रोटीन को आपस में मिलने से चीजें बेहद जटिल होती हैं। दवाओं को विकसित करने के शुरुआती स्तर पर ही हम अच्छे परिणाम चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो, यह जरूरी नहीं है। हमारे द्वारा विकसित किया गया नया तरीका इस काम में बेहद कारगर साबित होगा। इसके जरिये न केवल दवाओं को तैयार करने के लिए प्रोटीन का डाटा अधिक तेजी से जुटाया जा सकेगा, बल्कि नई दवाओं की जल्द पहचान कर बीमारियों से लड़ने में मदद भी मिलेगी।



केमिकल साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है शोध। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

इस तरह तैयार की प्रणाली

इस शोध में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के स्कूल आफ बायोसाइंसेज के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। इसकी मदद से प्रोटीन के जोड़ों के द्रव्यमान को मापा जाता है और पहचान की जाती है कि कौन से प्रोटीन आपस में सबसे अच्छी तरह से बंधे रह सकते हैं, ताकि बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए तरीका तलाशा जा सके।



विश्व का सबसे पुराना थिएटर...

दक्षिणी फ्रांस के ला सिओटैट में 'ईडन-थिएटर' के अंदर का दृश्य। यह दुनिया का सबसे पुराना थिएटर है। इसकी इसी खूबी के चलते इसका नाम गिनिज बुक में दर्ज हो गया है। खास बात यह है कि यह थिएटर अब भी चालू है। 1899 में यहां पहली फिल्म दिखाई गई थी। एएफपी

मारने से बिगड़ जाता है बच्चों का व्यवहार

लंदन, प्रेट्र : अक्सर जब बच्चे कोई बात नहीं मानते, पढ़ाई या खाने के लिए आनाकानी करते हैं तो माता-पिता को एक ही रास्ता दिखाई देता है, उनकी पिटाई कर देना। इस तरह से भले ही वे उस वक्त बात मान लें, लेकिन आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह बात यूनिवर्सिटी कालेज लंदन (यूसीएल) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय दल द्वारा 20 वर्ष तक किए शोध के विश्लेषण के आधार पर सामने आई है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक सजा देने से उनका व्यवहार सुधरता नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में और मुश्किल आती है।

लैंसेट नामक जर्नल में प्रकाशित समीक्षा में दुनिया भर में किए गए 69 अध्ययनों को देखा गया, जिसमें बच्चों को शारीरिक सजा देने से उन पर पड़े प्रभावों के डाटा का विश्लेषण किया गया। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि दुनिया भर में दो से चार साल की उम्र के दो तिहाई (63 फीसद) बच्चे (करीब 25 करोड़ बच्चे) माता-पिता या अभिभावक से निरंतर शारीरिक सजा पाते हैं। यूसीएल के डिपार्टमेंट आफ एपिडेमियोलाजी एंड पब्लिक में कार्यरत और इस समीक्षा की प्रमुख लेखक डा. अंजा हेइलमैन के मुताबिक, बच्चों को शारीरिक सजा देना न केवल व्यर्थ है, बल्कि हानिकारक भी है। इसका न तो बच्चों को और न ही परिवार को किसी प्रकार का लाभ होता है। हमने शारीरिक सजा और व्यवहार संबंधी समस्याओं के बीच एक सीधा संबंध देखा। हमने पाया कि बच्चों को लगातार शारीरिक सजा देने से उन्हें अपने व्यवहार को नियंत्रण करने में कठिनाई आती है। उनमें गुस्सा बढ़ता है, लेकिन वे सही से इसे बता नहीं सकते। डा. अंजा के मुताबिक, इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि शारीरिक सजा देने से उनमें हिंसा के अधिक गंभीर स्तर के शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। अब तक स्कॉटलैंड और वेल्स सहित 62 देशों में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

कई नुकसान देखने को मिले : अध्ययन की वरिष्ठ लेखक एलिजाबेथ गेर्शोफ के मुताबिक, माता-पिता बच्चों को शारीरिक सजा इसलिए देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके व्यवहार में सुधार आएगा, लेकिन हमारा अध्ययन स्पष्ट बताता है कि ऐसा करने से उनका व्यवहार सुधरने के बजाए और खराब होता है। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक, जितने भी अध्ययनों की समीक्षा की गई, उनमें से कोई भी इस बात की ओर संकेत नहीं करता कि शारीरिक सजा देने से कुछ भी सकारात्मक निकल कर आया हो। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि जिन बच्चों को शारीरिक सजा दी गई, समय के साथ उनका न केवल व्यवहार बिगड़ा, बल्कि उनमें तनाव में भी वृद्धि हुई।



बच्चों को मारना किसी समस्या का समाधान नहीं। फाइल /इंटरनेट मीडिया

पत्तों की फोटो से लगेगा आलू में झुलसा रोग का पता

हंसराज सैनी, मंडी : आलू की फसल में बीमारी लगी है या नहीं, देश के किसानों को इसका पता लगाने के लिए अब कृषि विभाग के कार्यालय या प्रयोगशाला के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब किसान पत्तों की फोटो मोबाइल फोन से खींचकर खुद बीमारी (झुलसा रोग) का पता लगा सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने आलू के पत्तों की तस्वीर से फसल में रोग का पता लगाने के लिए स्वचालित कंप्यूटेशनल माडल विकसित किया है। स्कूल आफ कंप्यूटिंग एवं इंलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. श्रीकांत श्रीनिवासन के मार्गदर्शन में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के सहयोग से यह एआइ आधारित तकनीक विकसित की गई है।

कोरोना संक्रमण के गंभीर प्रभावों से बचा सकता है फ्लू का टीका

अनुसंधान



75 हजार कोरोना पीड़ितों के डाटा के विश्लेषण के आधार पर निकाला है निष्कर्ष। फाइल

कोरोना वायरस (कोविड-19) से मुकाबले में मौजूदा दवाओं में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी कवायद में फ्लू टीके को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि यह टीका कोरोना के गंभीर प्रभावों से बचाव कर सकता है। बड़े पैमाने पर किए गए इस अध्ययन के अनुसार, इंफ्लुएंजा के खिलाफ टीका लगवाने वाले लोग कोरोना के कुछ गंभीर प्रभावों से आंशिक तौर पर सुरक्षित हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष करीब 75 हजार कोरोना पीड़ितों के डाटा के विश्लेषण के आधार पर निकाला है। उनका कहना है कि सालाना फ्लू का टीका लगवाने वाले कोरोना पीड़ितों में स्ट्रोक, सेप्सिस और रक्त का थक्का बनने का खतरा कम पाया गया है। फ्लू के खिलाफ टीका लगवाने वाले ऐसे कोरोना मरीजों को आइसीयू में भर्ती करने की जरूरत भी कम पाई गई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ मियामी मिलर स्कूल आफ मेडिसिन के प्रोफेसर देविंदर सिंह ने कहा, 'कोरोना महामारी के दौर में अध्ययन का यह नतीजा बेहद अहम है। हमारा यह अध्ययन दुनियाभर में बीमारी के बढ़ते दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।' शोधकर्ताओं के अनुसार, फ्लू का टीका नहीं लगवाने वाले कोरोना पीड़ितों को आइसीयू में भर्ती करने का खतरा 20 फीसद ज्यादा पाया गया है। इनमें स्ट्रोक का जोखिम 58 फीसद, सेप्सिस का खतरा 45 फीसद और रक्त का थक्का बनने का जोखिम 40 फीसद ज्यादा पाया गया है। कई हालिया अध्ययनों से भी यह बात सामने आ चुकी है कि फ्लू वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सुरक्षा मुहैया करा सकती है। -प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

मुझे कभी नहीं लगा कि मैं गलत पेशे में हूं : शायोनी

हर किसी को जीवन में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। बात करें जॉली एलएलबी 2 की अभिनेत्री शायोनी गुप्ता की तो वह जीवन में की गईं मशक्कतों को संघर्ष नहीं मानती हैं। वह यह शब्द ही नहीं पसंद करती हैं। अपने प्रशंसकों के साथ एक लाइव चैट के दौरान शायोनी ने कहा कि मैं हमेशा से जानती थी कि मुझमें वह बात है कि मैं एक्टर बनूं। मैंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया से एक्टिंग की पढ़ाई की है। ऐसे में अभिनय की पढ़ाई ने मुझे आत्मविश्वास दिया है। मुझे पता है कि मैं जीवन भर एक्टिंग ही करूंगी। मैं ऑडिशन देने खुशी-खुशी जाया करती थी। मुझे पता था कि यह बस वक्त का तकाजा है। मैं एक दिन अपनी जगह बना लूंगी। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी गलत पेशे में हूं। मैंने कभी अपने पेशे को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। मैंने कॉलेज से थिएटर करना शुरू किया था। सिर्फ स्टेज पर ही नहीं बैकस्टेज भी काफी काम किया करती थी। मैं चाहती हूं कि जिन तकनीशियन, निर्देशकों, कलाकारों को मैं पसंद करती हूं, उनके साथ काम करूं। इस दुनिया से जाने से पहले मैं अपने मन के सारे काम करना चाहती हूं। यही चाहती हूं कि लोग मुझे अच्छे इंसान और कलाकार के तौर पर याद रखें।

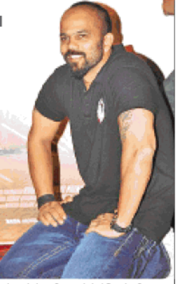


फोर मोर शॉट्स प्लीज ! सीजन 3 में नजर आएंगी शायोनी। इंस्टाग्राम

यह मुश्किल वक्त है, क्योंकि बहुत से पैसे फिल्म में लगे हैं। हालांकि मैं और मेरी टीम एकसाथ हैं।

सर्कस सिनेमा को बदलने वाली फिल्म नहीं है

वक्त भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसमें रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र रास्ता होता है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी का यही मानना है। बतौर निर्देशक और सह निर्माता उनकी फिल्म सूर्यवंशी पिछले डेढ़ साल से रिलीज का इंतजार कर रही है। बनी बनाई फिल्म को अगर रिलीज के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़े तो फिल्म से जुड़े लोगों का निराश होना लाजमी है, लेकिन रोहित इस वक्त में रुकने की बजाय काम करते रहने में यकीन रखते हैं। उन्होंने सूर्यवंशी की रिलीज रुकने के बावजूद अपनी आगामी फिल्म सर्कस पर काम शुरू कर दिया है। रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म की एडिटिंग पर काम शुरू हो चुका है। दैनिक जागरण से बातचीत में रोहित शेट्टी ने बताया कि यह मुश्किल वक्त रहा है, क्योंकि बहुत से पैसे फिल्म पर लगे हैं, लेकिन मैं और मेरी टीम इस मुश्किल वक्त में एकसाथ हैं। फिलहाल इस वक्त हर किसी की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए और कोरोना की तीसरी लहर के लिए सतर्क रहना चाहिए। रोहित ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि निर्माता होकर फिल्म को होल्ड करना आसान नहीं। उसके बाद भी सर्कस जैसी फिल्म बनाना, यह सोचकर की जो होगा, सो होगा, मुश्किल काम है। लेकिन काम करते रहना पड़ता है। इसलिए सर्कस बनाई, फिर खतरों के खिलाड़ी 11 शूट किया। रणवीर के साथ सर्कस में तीसरी बार काम कर रहा हूं। फिल्म में 18 कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जो परिवार की तरह हैं।



आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं रोहित शेट्टी • जागरण आर्काइव

कंगना रनोट ने कहा, अफवाहों से दूर रहें



थलाइवी फिल्म में जयललिता के किरदार में होंगी कंगना। इंस्टाग्राम

कोरोना की दूसरी लहर के बाद से बंद पड़े सिनेमाघर न सिर्फ पूरी क्षमता के साथ खुलने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि वे फिल्में जो बनकर तैयार हैं, वे भी रिलीज के इंतजार में हैं। ऐसे में कंगना रनोट अभिनीत फिल्म थलाइवी की रिलीज को लेकर पिछले दिनों से अलग-अलग खबरें आ रही थीं। अब कंगना ने इन खबरों को अफवाह बताया है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर बताया कि थलाइवी को लेकर अभी तक कोई भी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है। कृपया अफवाहों से बचें। हम फिल्म को तब रिलीज करेंगे जब देश के सभी सिनेमाघर खुल जाएंगे। इस फिल्म में कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभा रही हैं। पहले यह फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से थिएटर बंद हो गए और फिल्म की रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। अब कंगना ने खुद साफ कर दिया है कि जब तक देश भर के सभी सिनेमाघर नहीं खुल जाते हैं, तब तक फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। वहीं, भोपाल में अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिल्म डाक्टर जी की शूटिंग शुरू कर दी है।

अध्यात्म के साथ-साथ मैं कर्म में भी यकीन करता हूं : पंकज बेरी

अक्सर कहा जाता है कि इंसान को अध्यात्म और उसके कर्म के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। गुल गुलशन गुलफाम, पेशवा बाजीराव और तेनाली रामा जैसे धारावाहिकों के अभिनेता पंकज बेरी भी जीवन में अध्यात्म और कर्म के बीच संतुलन बनाकर चलने का प्रयास करते हैं। पंकज फिलहाल धारावाहिक मेरे साईं : श्रद्धा और सबुरी में आयकर विभाग के अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे जब भी बाबा (साईं बाबा) से जुड़ा कोई काम करने का मौका मिलता है, मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं। मैंने करीब 25 साल पहले बाबा के जीवन पर बने एक शो में काम किया था। उसके बाद उनसे जुड़े एक अन्य शो में काम किया। फिर करीब 10 साल पहले मैंने बाबा के जीवन से जुड़ी एक फिल्म में काम किया था। इस धारावाहिक में जब मुझे चौथी बार बाबा से जुड़े शो में काम करने का मौका मिला तो मैं झट से राजी हो गया।' वहीं, अध्यात्म को लेकर पंकज कहते हैं, 'मैं बहुत आध्यात्मिक इंसान हूं और ईश्वर में यकीन रखता हूं। मुझे लगता है कि मेरी एक-एक सांस ईश्वर की अमानत है और हर काम उनकी कृपा से ही हो रहा है। हालांकि, अध्यात्म के साथ-साथ मैं कर्म में भी यकीन रखता हूं, क्योंकि आप बिना कर्म किए हर चीज ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं।' पंकज आगामी दिनों में फिल्म देहाती डिस्को में नजर आएंगे।



धारावाहिक मेरे साईं : श्रद्धा और सबुरी में आयकर विभाग के अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं पंकज। सौ. सोनी टीवी

कॉमेडी करना आसान नहीं : प्रतीक

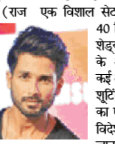
पिछले साल रिलीज हुई वेब सीरीज स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी से सुर्खियों में आए अभिनेता प्रतीक गांधी अब खुद को अलग-अलग जॉनर में आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में वह फिल्म वो लड़की है कहां? में अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ पहली बार कॉमेडी करते नजर आएंगे। फिल्म में तापसी जहां महिला पुलिस अधिकारी का किरदार निभाएंगी, वहीं प्रतीक का किरदार लड़ाई-झगड़ा करने वाले शख्स का होगा। इस फिल्म के बारे में दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे बातचीत में प्रतीक ने बताया, वो लड़की है कहां? समाज पर व्यंग्य करती फिल्म है। इस फिल्म में काफी कॉमेडी है, जिसे लेकर मैं रोमांचित होने के साथ-साथ नर्वस भी हूं। मैंने इससे पहले थिएटर में काफी कॉमेडी की है, लेकिन स्क्रीन पर मेरे लिए यह पहला मौका होगा। कॉमेडी करना आसान नहीं है। इसमें कलाकार को त्वरित प्रतिक्रिया देने के साथ-साथ स्क्रिप्ट के बहाव के साथ आगे बढ़ना होता है। थिएटर में मेरे निर्देशकों ने मुझसे कहा था कि मेरी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, लिहाजा उम्मीद है कि मैं इसमें सही परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत से शुरू करने की योजना है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए काफी अनिश्चितता है। हम कुछ महीनों में ही फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू करेंगे। सिद्धार्थ रॉय कपूर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म को अरशद सईद निर्देशित करेंगे।



पहली बार कॉमेडी करने के लिए तैयार हैं प्रतीक गांधी • इंटरनेट मीडिया

शाहिद की वेब सीरीज के लिए लगाया गया बाजार का सेट

अभिनेता शाहिद कपूर ने भी मुंबई में अपनी पहली वेब सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी है। निर्देशक जोड़ी राज निदिमोरू और कृष्णा डीके (राज एंड डीके) के निर्देशन में बन रहे इस अनाम शो के पहले शेड्यूल की शूटिंग गत जनवरी में गोवा में शुरू हुई थी। उसके बाद गोवा में ही अप्रैल महीने में इस शो के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग की गई। उसके अगले महीने में शो के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से योजना रद करनी पड़ी। अब खबर है कि राज एंड डीके ने शाहिद के साथ तीन-चार दिन पहले ही मुंबई की फिल्म सिटी में शो के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है। शो की शूटिंग के लिए फिल्मसिटी में चहल-पहल से भरे बाजार का एक विशाल सेट लगाया गया है। 40 दिनों के इस तीसरे शेड्यूल में फिल्म सिटी के अलावा मुंबई के कई अन्य स्थानों पर भी शूटिंग होगी। इस शो का एक अन्य शेड्यूल विदेश में भी शूट किया जाना है। उस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शो की शूटिंग खत्म होगी। निर्माताओं की योजना जून तक इसकी शूटिंग पूरी कर लेने की थी, लेकिन दूसरी लहर की वजह से यह संभव नहीं हो सका। दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री राशी खन्ना इस शो में शाहिद के साथ अहम भूमिका में हैं।



शाहिद ने मुंबई में शुरू की अपनी डेब्यू वेब सीरीज की शूटिंग • जागरण आर्काइव

'चुट्जपाह की सबसे बड़ी चुनौती थी कि कहीं यह बोरिंग न हो जाए'

कहानी और परिस्थितियों के अनुसार प्रोजेक्ट को दिलचस्प बनाए रखने के लिए निर्देशकों के सामने अलग-अलग चुनौतियां होती हैं। वरुण शर्मा, मनजोत सिंह और तान्या मानिकतला अभिनीत आगामी वेब सीरीज चुट्जपाह की शूटिंग के दौरान निर्देशक सिमरप्रीत सिंह के सामने भी कुछ ऐसी ही चुनौतियां थीं। दैनिक जागरण से बातचीत में सिमरप्रीत ने शो को लेकर अपनी मुख्य चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा, 'इस शो के ज्यादातर हिस्सों में किरदारों की बातचीत सिर्फ कंप्यूटर या फोन की स्क्रीन के माध्यम से हो रही है। स्क्रिप्ट पढ़ने में तो काफी दिलचस्प थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इसे फिल्माएंगे कैसे? सभी किरदार अपने कमरे में बैठे होते हैं तो मुझे डर था कि कहीं यह नीरस और बोरिंग न हो जाए। फिर हमने आपस में बैठकर चर्चा की कि किस तरह से एक ही कमरे में बैठे इंसान को अलग-अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है। इसके लिए हमने अलग-अलग एंगल से शूट किया, जिससे पता चले कि एक ही जगह बैठने पर भी बंदे की जिंदगी कैसे बदलती जा रही है। हमारे सिनेमेटोग्राफर ने एक थ्री डी मॉडल बनाकर वीडियो कॉल पर हमें समझाया कि कमरे की डिजाइन कैसी होगी और वहां पर किरदारों को कहां रखना है। हमने इस शो के 80 प्रतिशत हिस्से की शूटिंग मुंबई में की, जहां पर हमने सभी किरदारों के अलग-अलग सेट बनाए थे। बाकी 20 प्रतिशत हिस्से की शूटिंग गोवा में की गई।' चुट्जपाह 23 जुलाई से डिजिटल प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी।



सिमरप्रीत ने किया है चुट्जपाह का निर्देशन। सौ. पीआर टीम

शादी के बाद यामी गौतम की नई फिल्म का एलान

पिछले महीने शादी करने के बाद अभिनेत्री यामी गौतम काम पर लौट चुकी हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी फिल्म ए थर्सडे की शूटिंग पूरी की है। अब उन्होंने अपनी आगामी फिल्म लॉस्ट का एलान कर दिया है। लॉस्ट इनवेस्टिगेटिव ड्रामा फिल्म होगी, जो मीडिया की अखंडता पर प्रकाश डालेगी। यामी फिल्म में क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में होंगी। मेकर्स फिल्म की शूटिंग कोलकाता और पुरुलिया के उन वास्तविक लोकेशन पर करने की तैयारी में हैं, जहां पहले दूसरे मेकर्स की नजर नहीं पड़ी है। संगीतकार शांतनु मोइत्रा और गीतकार स्वानंद किरकिरे उस शहर की भावनाओं को अपने गीत में लाने का प्रयास करेंगे। फिल्म पिंक का निर्देशन कर चुके निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी लॉस्ट का निर्देशन करेंगे। फिल्म को लेकर दैनिक जागरण से बातचीत में अनिरुद्ध ने कहा कि भले ही यह फिल्म इनवेस्टिगेटिव ड्रामा है, लेकिन फिल्म में कमिटमेंट और जिम्मेदारियों को एक साथ मिलकर दुनिया को खूबसूरत बनाने की बातें भी होंगी। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जो भी फिल्में बनाऊं वह सामाजिक संदर्भ में हो और वह कहानियां आसपास की दुनिया से ली गई हों। फिल्म में पंकज कपूर, राहुल खन्ना, नील भूपलम और तुषार पांडे जैसे कई कलाकार होंगे। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी।



फिल्म लॉस्ट में नजर आएंगी यामी • इंस्टाग्राम